खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-02) अंक-25

सोमवार 04 जुलाई, 2022 13 आषाढ़, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-02) में अंक 25 से अंक 26 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-3 (भाग-2)   सोमवार, 04 जुलाई, 2022/13 आषाढ़, 1944(शक)   अंक-25

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	निधन संबंधी उल्लेख	4-7
3.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	8-33
4.	विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विचार एवं पारण	33-107
5.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	108-139
6.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	140-194

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-2) सोमवार, 04 जुलाई, 2022/13 आषाढ़, 1944 (शक) अंक-25

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1 श्री अजेश यादव
2 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
3 श्रीमती ए. धनवती चंदेला ए
4 श्री अजय दत्त
5 श्री अमानतुल्ला खान
6 श्री अब्दुल रहमान
7 श्रीमती बन्दना कुमारी
8 सुश्री भावना गौड
9 श्री बी एस जून
10 श्री धर्मपाल लाकड़ा
11 श्री गिरीश सोनी
12 श्री जय भगवान
13 श्री करतार सिंह तंवर
14 श्री कुलदीप कुमार
15 श्री मोहिन्दर गोयल
16 श्री मुकेश अहलावत
17 श्री नरेश यादव
18 श्रीमती प्रीति जितेन्द्र तोमर

19 श्री प्रलाद सिंह साहनी
20 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
21 श्री ऋतुराज गोविंद
22 श्री रघुविंदर शौकीन
23 श्री राजेश गुप्ता
24 श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
25 श्री रोहित कुमार
26 श्री शरद कुमार चौहान
27 श्री संजीव झा
28 श्री सोमदत्त
29 श्री शिवचरण गोयल
30 श्री सोमनाथ भारती
31 श्री सौरभ भारद्वाज
32 श्री सही राम
33 श्री एस. के. बग्गा
34 श्री सुरेन्द्र कुमार
35 श्री विशेष रवि
36 श्री विनय मिश्रा
37 श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
38 श्री अभय वर्मा
39 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
40 श्री अजय कुमार महावर
41 श्री जरनैल सिंह
42 श्री जितेन्द्र महाजन
43 श्री मदन लाल
44 श्री मोहन सिंह बिष्ट
45 श्री ओम प्रकाश शर्मा
46 श्री पवन शर्मा
47 श्री राजकुमार आनंद
48 श्री राजेश ऋषि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-2) सोमवार, 04 जुलाई, 2022/13 आषाढ़, 1944(शक) अंक-25

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

सभी माननीय सदस्य राष्ट्रीयगीत-वन्दे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीयगीत - वन्दे मातरम)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सातवीं विधानसभा के तीसरे सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है।

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कम से कम समय में शालीनतापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करें ताकि सदन के समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके।

मैंने पिछले सत्र के दौरान भी बताया है और इस बार भी यह दोहरा रहा हूं कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी भी अन्य विषय पर विचार

नहीं किया जाएगा। अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें।

माननीय सदस्यगण, यह बहुत खुशी का अवसर है कि राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र से नव निर्वाचित सदस्य श्री दुर्गेश पाठक जी आज पहली बार सदन में उपस्थित हुए हैं। माननीय सदस्य अब पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। माननीय सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से नव निर्वाचित सदस्य श्री दुर्गेश पाठक जी का हार्दिक स्वागत करूंगा। ओथ कहां है। आइए।

(माननीय सदस्य श्री दुर्गेश पाठक द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की गई।)

माननीय अध्यक्षः जैसाकि हम सभी जानते हैं दुर्गेश जी अन्ना हजारे आन्दोलन से जुड़े हुए थे, अच्छे वक्ता है। उनकी कार्यशैली से पूरी दिल्ली की जनता परिचित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा ये कामना करता हूं कि ये जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन करेंगे।

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप सबको विदित है कि गत दिनांक 13 मई, 2022 को बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में स्थित फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हो गये। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को इसे बुझाने में काफी मुश्किल

आई। इस दुर्घटना के कारण जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो अत्यंत दुखद है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतकों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

(मणिपुर में भी भू-स्खलन से हुए जान-माल के नुकसान के प्रति शोक संवेदना)

आप सबको विदित है कि गत दिनांक 29 जून, 2022 को मणिपुर के नोनी जिले में तुपुल रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर भू-स्खलन से 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तथा 25 लोग लापता हो गये। बारिश के कारण बचाव और राहत कार्यों में भी बाधा आ रही है। मलबे के नीचे निकाले गये शवों में टेरिटोरियल आर्मी के जवान और नागरिक शामिल हैं।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से मृतकों के प्रति हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है।

माननीय अध्यक्षः बैठिए-बैठिए, सब बैठिए एक बार।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आप जो लोग इस तरह से मारे गए हैं उसमें भेदभाव कर रहे हैं, ये कहां का तरीका है।

माननीय अध्यक्षः कौन सा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई माननीय सदस्य।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकेंड मैं बात तो सुन लूं न।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): किस तरह से उनका कत्ल किया गया।

माननीय अध्यक्षः भई आप गुस्से से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं। आप गुस्से से बोल रहे हैं या प्रस्ताव रख रहे हैं। गुस्से से बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा तरीका है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): जो आप चाहेंगे वो ही सब होगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं ये कौन सा तरीका है बात करने का। पहले बैठिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है बैठिए, सोमनाथ जी बैठिए जरा, बैठिए प्लीज।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): आप जोड़िये इसको।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): आप शहीद कन्हैया का नाम जोड़िये इसमें...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आपने बात रख ली न, बैठिए, गुस्से में नहीं, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: दुनिया तो बहुत चीजों से स्तब्ध है। बैठिए आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: इतना गुस्से में बिधूड़ी जी मैंने कभी देखा नहीं आपको बैठिए। हांजी सौरभ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए।

श्री सौरभ भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मेरा ये निवेदन है कि ये जो उदयपुर की घटना हुई है ये देश की शांति व्यवस्था को भी प्रभावित करती है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये सभी समुदायों के लिए मुझे लगता है कि इसके अंदर एक लकीर खीचीं जानी चाहिए कि कोई भी जो है समुदाय का कोई भी आदमी किसी भी दूसरे समुदाय के आदमी को उसके अंदर कितनी ही नपफरत क्यों न भरी हो मगर वो अपने हाथ में इस तरह से जो है ये काम नहीं सकता कर और सदन से ये मैसेज जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं

ये बात मानता हूं कि ये मैसेज जाना चाहिए और ये सभी धर्मों के लिए जाना चाहिए ऐसा नहीं है और ये जरूरी है क्योंकि इस घटना से जो है बहुत लोग आहत है और देश के अंदर ऐसा दोबारा न हो, इसलिए ये मैसेज जो है इस सदन से भी जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन ट्विट भी किया, बयान भी दिया कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आज हिमाचल के अंदर भी एक बस जो है पलटी जिसके अंदर कुछ स्कूली बच्चे भी थे जिनकी जो है मृत्यु हुई है। तो मैं मानता हूं कि इनकी बात का समर्थन करना चाहिए और ये जो है हिमाचल वाली चीज पर भी हमें करना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः इसके साथ जो अभी बिधूड़ी जी ने बात रखी और सौरभ भारद्वाज जी ने भी अपनी बात रखी। दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए इस obituary में मैं ये दोनों घटनाएं भी जोड़ रहा हूं। अब इन सबकी, हां, दो मिनट का हम सभी के लिए खड़े होकर मौन रखेंगे।

(सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया।)

माननीय अध्यक्षः ओम शांति शांति शांति। आज दर्शक दीर्घा में काफी सदस्य दुर्गेश पाठक जी के आए हैं उनके समर्थक। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा किसी भी विषय पर ताली-वाली नहीं बजाएंगे, कोई नारा नहीं लगाएंगे ये सदन की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। विशेष उल्लेख-280 श्री नरेश यादव जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे 280 में मेरी विधान सभा की समस्या उठाने का मौका दिया। सर्वप्रथम अध्यक्ष जी मैं हमारे न्यू सदस्य

दुर्गेश पाठक जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने राजेन्द्र नगर विधान सभा से बम्पर जीत दर्ज की है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी मैं इस जीत का श्रेय देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा जो विषय आज है वो पूरी दिल्ली के लिए है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा जो विधवा की बेटी है उसकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अध्यक्ष जी जो परिवार गरीब है जिस बेटी के मां-बाप अभी है लेकिन वास्तव में वो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है और उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे भी बहुत सारे परिवार अध्यक्ष जी हमारे पास आते हैं। बड़े ही संकोच के साथ में कई बार जब किसी बेटी की मां हमारे पास आती है तो मैं पूछता हूं कि उनके फादर क्या करते हैं।

सिर्फ ये जानने के लिए क्या उनके फादर जीवित हैं या नहीं। तो अगर वो जीवित हैं तो ये पता चलता है डायरेक्टिली पूछना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उनको हम लोग मना करते हैं कि अगर किसी बेटी के माँ बाप हैं तो उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती। तो अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से विधवा की बेटी के लिए हम लोग आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं उसी तरह से एक गरीब परिवार की बेटी के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रोविजन कुछ करना चाहिए सरकार की तरफ से और इसके लिए मेरा सुझाव है कि 51 हजार रूपया रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी हमारे माननीय सदस्य भी इसके लिए सहमत होंगे क्योंकि उनके पास भी ये समस्याएं आती होंगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बिधूडी जी। नेता विपक्ष।

श्री रामवीर सिंह बिधूडी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा बंद किये जा रहे सरकारी स्कूलों के गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शहीद अमीर चन्द के नाम पर लूडलो केसल में बने सर्वोदय विद्यालय को भी बंद कर दिया गया है। हर साल सौ स्कूल खोलने के वादे के साथ सत्ता में आई केजरीवाल सरकार इस साल में ही अब तक 31 स्कूल बंद कर चुकी है। मास्टर अमीर चन्द जैसे शहीदों के नाम पर बने स्कूलों को बन्द करना शहीदों का भी अपमान है। अध्यक्ष जी, शहीद अमीर चन्द के नाम पर बना ये सर्वोदय विद्यालय पिछले 59 सालों से चल रहा था। जिसमें दो हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते रहे हैं अब इस स्कूल को स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी और अभिभावकों की मर्जी के बिना ही शंकराचार्य मार्ग पर बने स्कूल में मर्ज करने के लिए बंद कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि स्कूल बंद करने का जो आदेश जारी किया गया उसमें कहा गया है कि स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी और अभिभावकों की सहमति से ऐसा किया जा रहा है। जबकि उनकी राय तक नहीं पूछी गई और वे इस पफैसले का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार 30 स्कूल पहले ही अन्य स्कूलों में मर्ज कर चुकी है। दिल्ली सरकार बिना किसी सुविधाओं को बढ़ाए नई युनिवर्सिटी आदि बनाने की घोषणाएं कर रही है। इस स्कूल को भी बंद करके यहां स्पोटर्स युनिवर्सिटी खोली जानी है जो कि यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ बड़ा अन्याय हो गया। अध्यक्ष जी, शहीद अमीर चन्द दिल्ली के उन शहीदों में शामिल हैं जिन्हें स्वतन्त्रता संग्राम में 1915 में फांसी पर लटकाया गया था। ऐसे शहीदों

की याद को मिटाने की कार्रवाई बर्दास्त नहीं की जाएगी। अतः आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि अमीर चन्द सर्वोदय विद्यालय को पुनः शुरू किया जाए क्योंकि यहां पढ़ने वाले छात्रों को अन्य स्कूल में भेजना उनके साथ ज्यादती होगी। अध्यक्ष जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एक तरफ सरकार जो है राष्ट्र भक्ति थीम बजट की बात करती है और दूसरी तरफ शहीदों के नाम पर जो स्कूल उनके नाम पर थे उनको बंद कर रही है। ये शहीदों का अपमान है। अध्यक्ष जी स्कूलों में ना प्रिंसिपल है, ना वाईस प्रिंसिपल है। अध्यक्ष जी स्कूलों में ना कॉमर्स और सांइस की पढ़ाई है। अध्यक्ष जी स्कूलों में साढ़े चौबीस हजार टीचर्स की कमी है और दूसरी तरफ लगातार हम स्कूल बंद करते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये कहा गया था कि हम पहले पांच सालों में पांच सौ स्कूल खोलेंगे। अभी तक सात सौ स्कूल खुलने चाहिए थे।...

माननीय अध्यक्षः भई बिधूड़ी जी जितना आपने लिखा था उससे...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं, मैं अध्यक्ष जी, वो जो हमारा...

माननीय अध्यक्षः अब नहीं। देखिए अगर नेता विपक्ष अगर, नेता विपक्ष मर्यादा का पालन नहीं करेगा। जो आपने लिखा था वो हो गया।...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxx[1]

माननीय अध्यक्षः नहीं अब बैठिए। ये जो भी अब बिधूड़ी जी बोल रहे है उसको रिकार्ड नहीं किया जाए। प्लीज। माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

1. xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हुआ कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष सदन में इतना बड़ा झूठा आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। अब इसकी दो ही वजह हो सकती हैं या तो ये इस गलतफहमी में हैं कि ये जिन स्कूलों के बंद होने की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो सकता है एमसीडी के हों या बीजेपी के किसी और राज्य के हों। दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल बंद करने में यकीन नहीं करती है, स्कूल खोलने में यकीन करती है। बहुत बेबुनियाद, झूठा और गुमराह करने वाला बयान नेता प्रतिपक्ष ने सदन में दिया है। सामान्यत: 280 के कुछ भी यहां बयान चलते है। पोलिटिकल उसमें मोटिवेटिड होते हैं मैं रिएक्शन नहीं देता हूं। लेकिन इस पर देना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ये स्कूल के बारे में बात की है। दिल्ली में इन्होंने जब सरकार दिल्ली में चलानी शुरू की बहुत लम्बे समय तक सरकार चलाई। जानबूझकर डीडीए के प्लॉट प्राईवेट स्कूलों को तो दिये गए, सरकारी स्कूलों को नहीं दिये। यहां तक इन्होंने किया पिछले पांच सात साल में कि स्कूल की जमीन जो स्कूल के लिए आवंटित की गई थी उसका लैंड यूज डीडीए और एलजी साहब के दफ्तर मे बैठकर अपना हैड क्वार्टर बनाया इन लोगों ने ये किस मुंह से बात कर रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिये। स्कूल की जमीन की लैंड यूज चेंज करके हैड क्वार्टर में बदलने, भारतीय जनता पार्टी के हैड क्वार्टर में बदलने वाले लोग सदन में खड़े हो कर झूठ बोले तो दया आती है, शर्म भी नहीं आती है, इन पर दया आती है। मैं बोल रहा हूं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः हां बता रहे है वो, बिधूड़ी जी,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईए बिधूडी जी, बैठ जाईए। उत्तर दे रहे है वो पूरा। सुन लीजिए आराम से। आज क्या करके आए हैं आप। मेरी समझ में नहीं आता जो इतना, बैठिए, बैठिए। आप तो बड़े शालीन आदमी है। बैठिए, बैठिए। बड़े ही शालीन आदमी है, बैठिए तो सही। आप तो बहुत शालीन आदमी है।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः सर उनकी गलती नहीं है ये राजेन्द्र नगर हार कर आए हैं। सर इनकी गलती नहीं है वो कुछ तो होगा सर, राजेन्द्र नगर हार के आए हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अध्यक्ष महोदय मैं इस बात पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने इन्होंने जितने कुकर्म कर रखे थे और इनके मौसेरे भाईयों ने जितने कुकर्म कर रखे थे स्कूलों को लेकर उनको सबको बहुत अच्छे से साफ करते हुए पिछले सात साल में एजूकेशन में बहुत काम किया है। इतने कमरे बनवाए हैं, जहां-जहां जगह हो सकती थी। लेकिन दो-दो शिफ्ट में बने हुए स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में मर्ज करने को ये कह रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं। एक स्कूल जिसकी ये बात कर हैं उसको स्पोर्टस स्कूल में दुनिया के, देश के शानदार बच्चे को स्पोर्टस स्कूल में लाकर वहां पढ़ाई कराई जाएगी, स्पोर्टस की पढ़ाई कराई जाएगी। उसको ये कह रहे है बंद कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है। झूठ बोल रहे है कि स्कूल बंद कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्री: स्पोर्टस स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्पोर्टस स्कूल में कन्वर्ट करने को ये कह रहे हैं स्कूल बंद कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्री: शर्म आप करो। दिल्ली नगर निगम ने कितने स्कूल बंद किये है अध्यक्ष महोदय।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बिधूड़ी जी,

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्री: इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: ये तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए प्लीज बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नहीं जवाब आ गया है। उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने क्लीयर जवाब...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः क्या इस देश को मैडल नहीं चाहिए। क्या इस देश को गोल्ड मैडल नहीं चाहिए। क्या इस देश को गोल्ड मैडल नहीं चाहिए। बैठ जाइये, बैठ जाइये।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः नगर निगम के स्कूल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बंद किये हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाए।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः दिल्ली नगर निगम के सैंकडों स्कूलो को बंद कर गए और आज हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम एक स्कूल को स्पोर्टस स्कूल खोल रहे हैं वहां पर। उसको full-fledged स्पोर्टस स्कूल में कन्वर्ट कर रहे है झूठ बोल रहे हैं। स्पोर्टस स्कूल बनाने को कह रहे है बंद कर रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठ जाईए, बैठ जाईए। अब बैठ जाईए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है इन्हें शर्म आनी चाहिए। नगर निगम के इतने स्कूल बंद कर दिये। देश भर में जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेशर्मी से स्कूल बंद करे जा रही है बेशर्मी से और वहां पर जहां-जहां इन्होंने बेशर्मी से पूरे देश में स्कूल बंद किये हैं

वहां-वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्राईवेट स्कूल चल रहे हैं। सारे देश में स्कूल बंद करते हैं। किस मुंह से बात करते हैं कि दिल्ली सरकार स्कूल बंद कर रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूडी जी मैं अब अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxx[2]

माननीय अध्यक्षः देखिए ये कोई भी रिकार्ड में नहीं आएगा जो कुछ बिधूडी जी बोल रहे हैं। nothing to be recorded whatever Biduri ji is speaking nothing to be recorded बैठिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxx[2]

माननीय अध्यक्षः ये 280 है, बहस नहीं है। बिधूडी जी ये 280 है। ये 280 है। ये बहस नहीं है। बैठ जाईए। बैठ जाईए। बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब नहीं। ये बहस नहीं है, राखी जी बात समझ लीजिए। बैठिए प्लीज। राखी प्लीज बैठिए। ये 280 है इसमें परम्परा गलत मत डालो।

...व्यवधान...

---

2. xxx चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

सुश्री राखी बिरला: मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है आपको सुनना पड़ेगा, उप-मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ये इनका अपमान है एक साथ पूरा विपक्ष खड़ा होकर चिल्ला रहा है...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए, चलिए, बैठिए-बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अब बैठिए। प्लीज बैठिए। राखी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलिए अब बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए। भई राखी जी अब बैठ जाईए प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: राखी जी आप बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: राखी जी मैं ऐसे अलाऊ नहीं कर रहा हूं। नहीं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अब बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए। श्रीमान भूपेन्द्र सिंह जून साहब। भूपेन्द्र जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई अब, भईया ये 280 है सरदार जी। अब 280 है इसमें इसको होने दो बाकी सदस्यों को।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः किसका।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मै नाम बोल चुका हूं। भूपेन्द्र सिंह जून जी का अब बैठिए। प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं-नहीं बैठिए अब। ये समय सारा खराब हो जाएगा। बाकी सदस्य रह जाएंगे, उनको भी अपनी बात रखने की...

...व्यवधान...

श्री प्रलाद सिंह साहनीः मेरी बात सुनो, स्कूल की मीटिंग हुई और डायरेक्टर साहिबा ने बुलाई, सारे पेरेंटस आए, मैं भी वहां गया, पेरेंट्स ने रिक्वेस्टकी उसके बाद हमने स्कूल को मर्ज किया।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे भई उप-मुख्यमंत्री जी जवाब दे चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं आप।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः क्या, शांत हो गया था सदन आपने,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आग में घी डाल दिया बेमतलब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः क्या है जरनैल जी, कोई तमाशा है ये। आप भी खड़े हो गए बेमतलब के लिए। बैठ जाइये, अब नीचे बैठ जाइये, नीचे बैठिए, बैठ जाइये।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्षः मैं मार्शलस, मैं चेतावनी दे रहा हूं, सदन में मैं नारेबाजी अलाऊ नहीं करूंगा। आप बैठ जाइये गलत क्या हो रहा है मुझे मालूम है, बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मार्शलस, मोहन सिंह बिष्ट को बाहर करें। मोहन सिंह बिष्ट को बाहर करें। तीन बार मैंने कहा है, तीन बार नाम लिया आपका, आप मान ही नहीं रहे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं बोल रहा हूं बार-बार, बैठ जाइये, बैठ जाइये। तमाशा बना रखा है। आपका 280 हो गया बाकी औरों का नहीं होगा। बाहर करिये, जल्दी बाहर करिये, nothing to ask.

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मेरे कहने पर बिधूड़ी जी चुप हो गए, चलिये ठीक है जाइये। अब बैठ जाइये जी, अब बैठ जाइये। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिए, ओम प्रकाश जी बैठ जाइये, मुझे 280 चलाना है, हाँ बैठ जाइये। जून साहब। माननीय सदस्य शांत हो जाएं, जून साहब।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइये, आपने जाना है जाइये, जब आना होगा आ जाइएगा। जून साहब।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से वाक आउट किया गया।)

श्री भूपेंद्र सिंह जूनः धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः एक सेकंड जून साहब। माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने वाक आउट किया है सभी ने और अब 280 में विपक्ष के किसी भी सदस्य का नाम होगा, उसको मैं नहीं लूंगा।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः सर, मैं एक लाईन बोलना चाह रहा था क्योंकि माननीय सदस्य ने भी इसको सूचित किया, उन्होंने शोर में उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, माननीय साहनी साहब ने जो जिक्र किया। स्कूल 'मर्ज' शब्द यूज किया है, स्कूल बंद नहीं किया।...

माननीय अध्यक्षः आपने भी बोला था ये बात।

माननीय उप मुख्यमंत्रीः हां, और वो, अब उनको अंग्रेजी में 'मर्ज' समझ में बंद आ रहा है तो उसमें उनकी गलती है मेरी तो गलती नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी मैं अब किसी भी, सदन में घोषणा कर चुका हूं। मैं किसी भी सदस्य का नाम नहीं लूंगा। जिनका भी नाम आज 280 में आया हुआ है I will not allow मुझे बहुत दुख है। मुझे बहुत दुख है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): क्या हुआ अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः मैंने घोषणा कर दी है की मैं 280 में अब किसी भी सदस्य का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों ने वाकआउट किया है, 280 तक

वाकआउट रखिये। हां, मैं नाम नहीं लूंगा। अब बैठ जाइये आप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, आप जो मर्जी करेंगे।

माननीय अध्यक्षः हाँ बैठिये, ठीक है,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः कोई दिक्कत नहीं है। जून साहब।

श्री भूपेंद्र सिंह जूनः धन्यवाद सर। सर जैसा की हम सभी जानते है की दिल्ली इंटरनैशनल टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू की वजह से एक गेटवे है, इंटरनैशनल टूरिस्ट आते हैं फिर उसके बाद different parts जो हैं कंट्री के उनमें जाते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट मेरी विधान सभा में पड़ता है तो एयरोसिटी, आसपास के जितने भी होटलस हैं वो सारे एक टूरिज्म हब के तौर पर डवलप हो रहे है। सर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी भारी प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही है कि 2 साल में टूरिज्म बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, अब धीरे-धीरे पिकअप कर रहा है। इंटरनैशनल टूरिस्ट को सर कोचिज चाहिये, लग्जरी कोचिज और लग्जरी टैक्सिसीज। वो अवेलेबल आज के दिन दिल्ली में टूरिज्म purposes के लिये अवेलेबल नहीं है। उसका एक रीजन सर ये है के 11 दिसम्बर, 2015 को एनजीटी ने एक ऑर्डर किया की जितनी भी बीएस-3 स्टैंडर्ड की बसें या डीजल व्हीकलस हैं उनको दिल्ली में रजिस्टर ना किया जाए। उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। उसके बाद सर 13 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया की बीएस-4 जो compliant

engines हैं या व्हीकलस हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन ना हो। तो 2015 के बाद completely दिल्ली में डीजल रजिस्ट्रेशन जो लग्जरी कोचिज हैं और जो taxies हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। अब सर लीगली देखा जाए तो ये 2015 और 2017 का जो ओर्डरस थे, एनजीटी के और सुप्रीम कोर्ट के वो रिलेट करते थे बीएस-3 और बीएस-4 को। 1 अप्रैल, 2020 से भारत सरकार ने जो ऑयल सप्लाई किया डीजल और पैट्रोल वो बीएस-6 स्टैंडर्ड का सप्लाई करना शुरू कर दिया और कम्पनीज ने भी जो है इंजन बनाने शुरू किए वो बीएस-6 स्टैंडर्डस के बनाने शुरू कर दिए। आज के दिन कोई भी व्हीकल जो है अगर दिल्ली में रजिस्टर हो रहा है या मैन्यूफैक्चरिंग हो रही है वो सारे बीएस-6 स्टैंडर्डस के हैं। लेकिन 2015 और 17 के ऑर्डर की वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो 2000 बीएस-6 के स्टैंडर्ड की buses या luxury coaches उनको भी रजिस्टर नहीं कर रहे, जिनकी वजह से टूरिज्म पर फर्क पड़ रहा है, revenue generation का भी फर्क पड़ रहा है और unfortunately सर ये बसें जो बीएस स्टैंडर्ड-6 की हैं वो चोरी से आज भी दिल्ली में चल रही है। तो इससे better यही है की हम उनको रजिस्ट्रेशन दें और उनको टूरिज्म purposes के लिये इस्तेमाल करें। अगर कोई लीगलहिच है इन दोनों judgements की वजह से तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक क्लैरिफिकेशन ले ले। क्योंकि आज बीएस-6 prevalent है कल को बीएस-7 भी आएगा, बीएस-8 भी आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं उन जजमेंटस के बेस पर हम आगे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही बंद रखें। तो मेरा एक यही आग्रह है सर की इसको reconsider करें, इन दो जजमेंटस को properly interpret करें और जो 2000 बीएस-6 के जो compliant engines हैं, मैन्युफैक्चर जो कम्पनियाँ कर रही हैं

उन व्हीकलस को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि टूरिज्म थोड़ा सा और आगे बढ़े और लोगों को employment generate हो, धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः थैंक्यू। प्रकाश जारवाल जी। अखिलेश पति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने 280 में महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, ये मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं ये दिल्ली के लगभग सभी विधान सभाओं को टच करती है, सभी विधान सभाओं में निर्वाचन कार्यालय खोले गए हैं और निर्वाचन कार्यालयों की हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष जी, जब भी कोई वहां जाता है तो हालत ये है वहां पर कह दिया जाता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, प्रिंटिंग मशीन ठीक नहीं है, किसी का अगर वोटर आईडी खो जाता है वो डुप्लीकेट लेने जाता है उसके इशू नहीं किये जाते और इशू किए जाते हैं तो कहते हैं डाक से जाएगा और हालत ये है की वो कुछ खास लोगों के पास पहुंच जाता है और जो लाभार्थी है उस तक नहीं पहुंचता। अभी हाल के दिनों में पीछे चुनाव हुआ राजेंद्र नगर विधान सभा में, वहां देखा गया की बड़े तादात पर किरायेदारों के वोट काट दिये गए। लोग वहां पर कुछ जाति और धर्म के लोगों के वोट काट दिये गये। लोग आ रहे हैं उनका ऑनलाइन में शो कर रहा है लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट में डिलिशन का मोहर लगा हुआ है। लोग वोट नहीं डाल पाए और जान-बूझकर के कुछ खास लोगों को टारगेट करके, लोगों के वोट काटे जा रहे है। ये बहुत निंदा का विषय है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक-एक व्यक्ति जब से हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, जो भी योजनाएं चल रही है उसका लाभ उठाने के लिये उनको पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता

पड़ती है। वो व्यक्ति आज अगर किसी योजना का लाभ लेने के लिये जाता है जैसे उसे सिटी स्कैन कराना है, जो फ्री है। उसको कहीं पर जाकर के खून की जांच करानी है, कोई अन्य डीएल बनवाना है या और कोई लाभ लेना है किसी योजना का, तो मतदाता पहचान पत्र सूची में उसका नाम होना जरूरी है। लेकिन खास लोग, खासकर के पूर्वांचल के लोग, उनको टारगेट करके राजेंद्र नगर विधान सभा में उनका वोट काटा गया और आज, वो आज भी दर–बदर भटक रहे हैं उनको दो नुकसान हो रहा है इससे। एक तो वोट नहीं डाल पाए, दूसरा दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम सामाजिक योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है 280 के माध्यम से की ऐसे कितने वोट जो बिना वोटरों के सहमति के काट दिये गये वो किस आधार पर काट दिये गये, वो सदन के माध्यम से पता चले सभी सदस्यों को। वोट काटने का पैमाना क्या है, किस आधार पर वोट काट दिये जाते हैं, किस आधार पर वोटर लिस्ट से डिलिशन कर दिया जाता है किसी का नाम। इसका कोई सख्त पैमाना बने ताकि आने वाले समय में ऐसे लोगों को लाभ मिल सके, दिल्ली सरकार के सारी योजनाओं का और मत देने के अधिकार का भी प्रयोग कर पाएं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री शिवचरण गोयल जी।

श्री अजय महावरः मेरा नाम अध्यक्ष, जी मेरा नाम छूट गया क्या?

माननीय अध्यक्षः अभी बात करूंगा। श्री शिव चरण गोयल जी। बैठिए मैं करूंगा अभी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई देखिये comments नहीं प्लीज।

श्री शिव चरण गोयलः अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान मोती नगर विधान सभा में आए दिन जो हमारी गाय माता है उसकी दुर्दशा के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा पंजाबी बाग क्षेत्र मोती नगर, रमेश नगर, जहां पर हम अपने हिन्दू धर्म के संस्कारों की बात करते हैं। हम हिन्दुत्व की बात करते हैं, हिन्दू राष्ट्र होने पर गर्व महसूस करते हैं और हर कार्य की शुरूआत हम अपनी गऊ माता की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हमारे इसी धर्म ने सिखाया है की ये गाय हमारी माता है और हर शुभ कार्य का आरम्भ हमारी गाय माता का पूजन करके शुरूआत करते हैं। गाय को रोटी खिलाना, उनको चारा देना और हर यज्ञ में उनका गो-दान करना हमारे धर्म में पुण्य का काम माना गया है लेकिन अध्यक्ष जी आज इन्हीं गायों की वजह से भापजा शासित एमसीडी ने बुरा हाल कर रखा है। सड़कों पर हमारी गाय माता बैठी रहती हैं, गंदगी फैलती है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और गायों का इस तरह से वहां पर दुर्दशा और जहां पर देखकर मन बड़ा आहत होता है। जहां भी उठाकर देखो सड़कों पर, गलियों में, पार्कों में, मोहल्लों में हर जगह बुरा हाल है। और न इनकी देखरेख करने वाला है, न इनका खानपान की कोई व्यवस्था है,

श्री शिवचरण गोयलः हालात इतने बुरे हैं कि आये दिन दुर्घटनाएं होने के आसार बने रहते हैं और इसके लिए पूरी तरह से भाजपा शासित एमसीडी

जिम्मेदार है और यदि इनसे ये व्यवस्था संभल नहीं रही, इनसे विभाग संभल नहीं रहा तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये विभाग हमें दे दें। दिल्ली सरकार इनको संभाल लेगी क्योंकि ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। झूठ पर झूठ बोलते हैं। सदन को गुमराह करते है और हर वक्त झूठ का पुलिन्दा इनके मुखौटे पर लगा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से हमारी संस्कारों में लिखा है कि ये गायों की दुर्दशा हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे या तो इनको आप व्यवस्था कर लें नहीं तो हम खुद संभालेंगे। मैं आपके माध्यम से आपने मुझे इतना गम्भीर विषय पर बोलने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री अनिल बाजपेयी जी। अनुपस्थित। चलिये, अजय महावर जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः इसके बाद आपका ही है।

श्री अजय कुमार महावरः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं जो विषय अभी उठाने के लिए 280 के माध्यम से जा रहा हूं। मुझे लगता है कि सभी विधायकों के यहाँ ये तकलीफ होगी और ये पूरे दिल्ली का ही विषय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान समाज कल्याण विभाग एवं महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा बुजुर्गो, विधवाओं, दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी जानकारी में ये आया है कि बुजुर्गो, विधवाओं, दिव्यांगजनों की मृत्यु से पहले सरकार द्वारा जो पेंशन की राशि जारी की गयी थी उस राशि में से जो राशि उनके द्वारा खर्च नहीं की गयी उस बचत राशि को उनके मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त विभाग द्वारा उनके

खाते से वापस ले ली जा रही है या बैंक के खातों में स्टाप कर दिया जा रहा है। ये मानवीय आधार पर असंवेदनशील प्रतीत होता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि उनकी मृत्यु के समय भले ही उनके खाते में कुछ धनराशि बच रही हो पर उन पर बहुत बड़ी धनराशि का कर्ज भी होता है। सरकार द्वारा उनके खाते से पेंशन की राशि वापस लेने से उनका कर्ज उनके परिवारजनों को भरना पड़ता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कृप्या बुजुर्गो, विधवाओं, दिव्यांगजनों को उनकी मृत्यु से पूर्व जो पेंशन जारी कर दी गयी है, कृप्या उसे मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए वापस नहीं लिया जाये और उस राशि को उसके परिवारजनों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाये। साथ ही सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन को तुरन्त शुरू किया जाये क्योंकि बुजुर्गों की सुनी आँखें इसकी राह ताक रही है, इंतजार कर रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान, उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे 280 में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि मैं सदन में कम से कम चार या पाँच बार इसको उठा चुका हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एसडीएम कार्यालय गाँधी नगर से नन्द नगरी जो ट्रांसफर किया गया है, मैं उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आज से लगभग दस साल पहले, ग्यारह साल पहले एसडीएम कार्यालय को गांधी नगर से हटाकर नन्द नगरी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। आज गांधी नगर विधान सभा के लोगों को यदि आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, मकान की रजिस्ट्री करवानी

हो, शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो और एसडीएम कार्यालय से सम्बन्धित जो भी समस्यायें हैं उसके लिए कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोई डाइरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन गांधी नगर मेरी विधान सभा से नन्द नगरी के लिए नहीं है। मैं इसके लिए एक बात और भी आपसे कह देना चाहता हूं कि एसडीएम कार्यालय गांधी नगर हैं। गांधी नगर में एसडीएम गांधी नगर है और हमारा जो भी डूडा का जो हमारा बजट एमएलए पफंड का आया, वो भी गांधी नगर से आया। एसडीएम इलेक्शन, दो चुनाव मैं भी वहाँ से तीन लड़ा हूं। वहाँ का एसडीएम इलेक्शन है वो भी गांधी नगर में है। जब सारी चीज गांधी नगर में उपस्थित है तो लोगों को नन्द नगरी क्यों भेजा जाता है। मैं कई बार सदन में मैंने ये उठाया है। मेरे पास अध्यक्ष जी एक रास्ता अब और बचा है कि या तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा किसी दिन मंत्री जी के आगे जनता को लेकर बैठूंगा मैं। क्योंकि ये जनता की समस्यायें हैं। चार से पांच बार मैं इस विधान सभा में अध्यक्ष जी उठा चुका हूं। आपसे भी पिछली बार मैंने अनुरोध किया था। माननीय अध्यक्ष जी आपने भी कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया है और माननीय मंत्री जी कैलाश जी भी हैं और ये कैबिनेट में केवल लगना है। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर साहब के यहां से भी हो गया है। अगर ये कैबिनेट में लग जाये तो गांधी नगर के लोगों का। हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं ये अलग बात है कि हम किसी राजनीतिक दल से विधायक है और आप सत्तारूढ़ दल के लोग बैठे हुए हैं लेकिन गांधी नगर के लोगों की समस्या है। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वापस गांधी नगर लाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने 280 में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, बुराड़ी कांस्टीट्यून्सी अनॉथराइज कालोनी से बसी हुई कांस्टीट्यून्सी है और मुझे लगता है कि जो बात मैं रखने वाला हूं कमोबेश ये हर वो विधान सभा जहाँ अनॉथराइज कालोनी है, ये समस्यायें कमोबेश वहाँ पर हैं। डीडीए की उदासीनता के कारण लगातार अनॉथराइज कालोनी बसता जा रहा है। पिछले 8–10 साल पहले जो कालोनी बसा चूंकि वो जो यूडी का डवलपमेन्ट प्लान है उसमें वो कालोनी नहीं है और यूडी की लिस्ट में वो नहीं होने के कारण वहाँ डवलपमेन्ट वर्क नहीं हुआ। अब जो लोग उस कालोनी में रह रहे हैं। कालोनी बसा हुआ है उस कालोनी में जो रह रहे हैं हर बार बरसात का मौसम उनके लिए आफत लेकर के आता है। पिछली बार हमारे कमोबेश 10–12 ऐसे कालोनियाँ थीं जहाँ के लोग पूरे बरसात में घर से बाहर नहीं निकल पाये। गर्दन से ऊपर तक पानी था। कई घर में साँप में घूस जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लोग नौकरी में, नौकरी के लिए अपने कार्यालय नहीं जा पा रहे थे फिर बरसात का मौसम है। एक, दो बरसात हुई। कमोबेशवो ही हालात सभी कालोनियों के हो गये हैं। मैंनें पिछली बार भी निवेदन किया था कि इन सभी कालोनियों में जब तक ये विकास का काम नहीं हो पाता है कुछ आपदा नियंत्रण कोष बनाकरके कम से कम सॉलिड मलबा डाल दिया जाये ताकी वो अपने घर से सड़क तक आ पायें। तो मैं आपके माध्यम से यही आज निवेदन कर रहा हूं कि फिर से उन सभी कालोनियों के लोगों में वही खौफ है जो पिछले बरसात में था। तो इसके लिए कम से कम सॉलिड मलबा डालने के लिए कोई एक कोष बना दिया जाये ताकी लोग जो अपने घर में पफंस जाते हैं वो घर से बाहर निकल पायें। कई घटनायें,

कई हादसाएं ऐसे हुए कि वो बीमार पड़ गये और वो घर से बाहर नहीं निकल पाता तो उनके वो शिकार हुए। बच्चे, कई बच्चों को साँप काट लिया। ऐसे ढेरों सारे उदाहरण हैं। मुझे लगता है मानवता के नाते भी और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत विपदा भरा समय था। तो फिर वो दोबारा न देखना पड़े। इसलिए उन सभी कालोनियों में कुछ सॉलिड मलबा डालने की व्यवस्था की जाये ताकी अपने घर से वो ठीक से निकल पायें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद संजीव जी। सही राम जी।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा के अति-महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय पूरे तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी या प्राईवेट अस्पताल नहीं है। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा के चारों तरफ करीब-करीब दस से पन्द्रह किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी अस्पताल ही नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में एक 500 बेड का अस्पताल का निर्माण कराया जाये। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जहाँ अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है उस स्थान को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्वीकृत सर्वे भी हो चुका है। यह स्थान इन्दिरा कल्याण विहार में डीएसआईडीसी के अधीन जमीन आती है और इस जमीन में आगे का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। यह जमीन पूरी कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा ही नहीं तकरीबन उसके साथ-साथ पाँच विधान सभा तुगलकाबाद विधान सभा, कालका जी, संगम विहार, बदरपुर, ओखला करीब 15 लाख लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य

सेवाओं से लाभान्वित नहीं है। बहुत भारी कीमत पर उन्होंने अपने खर्चे से इलाज कराना पड़ रहा है। यह जमीन कई एकड़ है और जमीन अभी किसी उपयोग में भी नहीं है। मेरी शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्य में आगे कोई प्रगति नहीं की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी विधान सभा में एक पाँच सौ बेड का अस्पताल जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें और मेरी विधान सभा की जनता को एक अस्पताल का उपहार दें। वहाँ की जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरी विधान सभा क्षेत्र के ही इन्दिरा कल्याण विहार में एक डूसिब की जमीन है। बिल्डिंग बनी हुई है। ये भी नहीं कि बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। उस जमीन पर पहले एमसीडी का स्कूल चलता था लेकिन अब वहाँ एक एमसीडी की नई बिल्डिंग बन चुकी है। वो स्कूल वहाँ स्थानान्तरित हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस बिल्डिंग में एक मोहल्ला पोलो क्लीनिक बनाने का आग्रह है। मैं आपसे आग्रह करूंगा। मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि उसको जल्द से जल्द कराया जाये।

इसके साथ-साथ अभी हमारे विपक्ष के साथी स्कूलों पर बड़े जोर से बड़ी शोर मचाया था उन्होंने अध्यक्ष महोदय। अभी पाँच दिन पहले की घटना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पाँच दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के गुजरात कैडर के लोगों को दिल्ली लाया गया कि आपको दिल्ली सरकार के ये कहकरके कि आपको दिल्ली सरकार क्योंकि हमारी सरकार वहाँ जाकरके अपने स्कूलों का मॉडल दिखा रही है तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को यहाँ दिल्ली लाया गया। ये कहकरके कि दिल्ली सरकार के खराब स्थिति के मॉडल स्कूल हम आपको दिखायेंगे। मुझे कॉल आयी। मैंने जॉच करायी तो स्कूल पाया

गया जो खराब मॉडल का गुजरात में दिखाया जा रहा है जी अभी। आतिशी जी का मुझे कॉल आया मैंने चेक कराया था तो जो खराब मॉडल का स्कूल दिखाया गया है वो भाई करतार सिंह तंवर जी के यहाँ एक संजय कालोनी झुग्गी स्लम बस्ती है। वहाँ का वो प्राइमरी स्कूल है। दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी स्कूल को गुजरात में दिल्ली सरकार का खराब मॉडल बताकरके ये दिखाने का ये काम कर रहे हैं।

ये जुमलों वालों की सरकार है, इनके कर्म ऐसे ही रहेंगे। आपने मुझे इतने गंभीर मामले में बोलने का मौका दिया, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि मेरे यहां अस्पताल का निर्माण जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्री साहनी जी और जरनैल सिंह जी कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रहलाद सिंह साहनीः अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करता हूं।

विधेयक का प्रस्तुतीकरण

माननीय अध्यक्षः Introduction, consideration and passing of bills श्री कैलाश गहलौत जी Hon’ble Minister of Law, Justice and Legislative Affairs to introduce the following five bills. श्रीमान कैलाश गहलौत जी।

श्री कैलाश गहलौत (माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते

संशोधन विधेयक 2022 वर्ष 2022 का विधेयक संख्या सात को इंट्रड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: वेतन और भत्ते पेंशन से संबंधित पांच विधेयक सदन पटल पर पेश हुए हैं, इन पर चर्चा के लिए कुछ सदस्यों के नाम आए हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए तथा समय के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए पहले सभी पांचों विधेयक पेश किए जा चुके हैं। अब माननीय सदस्य इस पर चर्चा में भाग लेंगे। अब माननीय मंत्री जी का

ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलौत जी विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-7) सदन में इंट्रोड्यूस करता हूं।

माननीय अध्यक्षः विधेयक पर विचार करना अब श्री कैलाश गहलौत जी माननीय विधि एवं न्याय विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को सदन में पुरः स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-7)[1] पर विचार किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को सदन में पुरःस्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-7)पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री कैलाश गहलौत जी माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 08) को सदन में इंट्रड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

1. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23055 पर उपलब्ध।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 08)[2] को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। मंत्री महोदय।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 08) को सदन में इंट्रड्यूस करता हूं।

माननीय अध्यक्षः श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी

---

2. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23056 पर उपलब्ध।

क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 08) पर विचार किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री: मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को सदन में पुर:स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि (संशोधन)विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 08)पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

सदस्यों के हां कहने पर

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री कैलाश गहलौत माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य **सचेतक** के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या नौ) को सदन में इंट्रड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य **सचेतक** के वेतन एवं भत्ते (संशोधन)

विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या नौ)[3] को इंट्रड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

सदस्यों के हां कहने पर

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री कैलाश गहलौत जी माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या दस) को सदन में इंट्रड्यूस करने की परमिशन मांगेगे। अब माननीय मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रड्यूस करेंगे। कैलाश जी। अब माननीय मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रड्यूस करेंगे।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या दस)[4] को सदन में इंट्रड्यूस करता हूं।

---

3. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23057 पर उपलब्ध।
4. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23058 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या दस) पर विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः सर मुख्य सचेतक का विचार भी किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षः नहीं बिधूड़ी जी का आने वाला है अभी आया नहीं है। वो ठीक समय पर वापिस आ गए हैं। अब राखी जी भी समय पर आ गई हैं। अब श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय विधि न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या दस) को सदन में इंट्रड्यूस करने की परमिशन मांगेगें।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंराष्ट्रीय राजध ानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या दस) को इंट्रडयूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव, हां जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दोनों साथ साथ पास करवाना। हां ठीक है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए। छूट गया मैं करता हूं।

ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री कैलाश गहलौत माननीय विधि न्याय विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 9) पर विचार किया जाए। कर दीजिए कोई बात नहीं। एक बार कर दीजिए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष का।

माननीय अध्यक्षः कह रहे हैं शायद छूट गया है। फिर एक बार कर दीजिए अगर छूट गया होगा तो हो जाएगा।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को सदन में पुर:स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या 9) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्षः ये प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं ना कहें

सदस्यों के हां कहने पर

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

...अब ध्यान रखना। अब श्री कैलाश गहलौत- माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते, ये हो गया, ये हो गया, पास हो गया, अध्यक्ष का पास नहीं हुआ है भई।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए। अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष का पास हो गया न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः गोपाल जी, कह रहे हैं नहीं हुआ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री विधेयक को, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में है, सदन में इंट्रोडयूस करेंगे। ये ले लीजिएगा, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष वाला।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या- 10) को सदन में इंट्रोडयूस करता हूं।

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलौत जी- माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या- 10) पर विचार किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या- 10) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जी, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री कैलाश गहलौत जी, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–11) को सदन में इंट्रोडयूस करने की परमिशन मांगेंगे।

...व्यवधान...

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–11) को इंट्रोडयूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जी, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोडयूस करेंगे।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-11)[5] को सदन में इंट्रोडयूस करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री कैलाश गहलौत जी- माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-11)पर विचार किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 जुलाई, 2022 को सदन में पुर:स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा में नेता, प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक 2022, (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-11) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जी, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

---

5. दिल्ली विधानसभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23059 पर उपलब्ध।

अब माननीय सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकेंगे और माननीय मंत्री जी बाद में चर्चा का उत्तर देंगे। सर्वप्रथम श्री विशेष रवि जी। विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। सर विधायक और विधायक कार्यालय हमारे पूरे सिस्टम का केंद्र बिंदु होता है। विधायक कार्यालय को और विधायक को उसके इलाके की जनता को सम्भालना होता है। उस इलाके के अंदर आने वाली सारी धार्मिक, सामाजिक, NGOs व अन्य संस्थाओं को सम्भालना होता है और इसके साथ-साथ सारी जो सरकारी मशीनरी है उसको भी विधायक कार्यालय जो है अपने कार्यालय से सम्भालता है, वहां से उस पर काम कराता है। विधायक कार्यालय पर, क्योंकि एक तरह से विधायक का काम पूरे अपनी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले सभी कामों का मॉनिटरिंग का, सुपरविजन का और मैनेजर के तौर पर काम करने का जिम्मा होता है इसलिए विधायक कार्यालय पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। हर वो काम जो सरकारी कार्यालय में नहीं होता है या हर वो काम जो सरकारी कार्यालय में जनता का नहीं हो पाता है तो जनता को सबसे ज्यादा आसान जो कार्यालय लगता है, सबसे आसान जो आदमी लगता है जिससे मिलकर उसको ये उम्मीद होती है कि मेरा काम किया जाएगा या मेरे काम पर सुनवाई होगी, वो विधायक कार्यालय होता है। चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन का काम हो, चाहे थाने का काम हो, चाहे डीडीए का काम हो, जितनी भी एजेंसिज, जितने भी विभाग दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैंउनसे संबंधित कोई भी काम होता है, तो जनता जो है सबसे पहले पसंद करती है कि अपने विधायक को, जिसको उसने वोट किया है, वो उसके कार्यालय पर

जाए, उसको बताए और वो ये उम्मीद करती है जनता कि वहां बताने के बाद उसके काम का हल होगा, उसके काम का निपटारा होगा। जब, जिस कार्यालय के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है काम का, जिस कार्यालय के ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीदें जनता की जुड़ी हुई होती हैं, उस कार्यालय के पास साधन, उस विधायक को एक उचित वेतन मिलना मुझे लगता है कि एक बहुत, बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो काम था।

जब हमने, 2015 में जब सरकार हमारी दुबारा बनी आम आदमी पार्टी की तो हमारी सरकार ने इस जरूरत को महसूस किया और एक कमेटी बनाई गई जिसको ये जिम्मा दिया गया कि वो यह एनालाइज करे कि दिल्ली के अंदर जो विधायक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या सही है, क्या उसकी बढ़ोतरी की जरूरत है और क्या, अगर बढ़ोतरी की जरूरत है तो किस-किस क्षेत्र में है और कितनी जरूरत है। उस कमेटी के अंदर बहुत सारे नामी लोग थे जो, जिन्होंने बाहर से पूरे सिस्टम को देखा और फिर ये तय किया कि दिल्ली के अंदर जो विधायकों को सैलरी दी जा रही है या जो भत्ते दिए जा रहे हैं, वो बहुत कम है और उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। और उस कमेटी की सिफारिश के ऊपर 2015 के अंदर मुझे याद है कि 3 तारीख, बारहवां महीना था यानी कि 3 दिसम्बर, 2015 के दिन इसी विधान सभा के अंदर हम ये प्रस्ताव लेकर आए थे, इस बिल को लेकर आए थे और 3 ही तारीख को ये बिल पास भी हुआ था और 3 तारीख को, 3 दिसम्बर, 2015 को यहां से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया था कि वो इसमें अपनी अनुमति दें ताकि दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ पाए। लेकिन ये बड़ा दुख है बताते हुए कि 7 साल लगे केंद्र सरकार को ये तय करने

के लिए कि दिल्ली के जो विधायक जो सैलरी ले रहे हैं, दिल्ली के जो विधायक भत्ता ले रहे हैं, वो बहुत कम है और उनको बढ़ाने की जरूरत है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिए।

श्री विशेष रविः सर, केंद्र सरकार ने जो, इस बिल को जो भेजा गया, जिसमें जो प्रस्ताव किया गया था उसको पास तो किया लेकिन इस तरह से पास किया कि वो पास करने के बाद भी जो है वो बहुत कम भत्ता और विधायक को सैलरी जो है इसमें तय की गई है। हमने जो प्रस्ताव किया था वो 2 लाख कुछ रूपये किया था सैलरी में और केंद्र सरकार ने जो पास किया है उसके हिसाब से हमारी जो 53-54 हजार तनख्वाह है इस समय या जो सैलरी और जो भत्ता मिलाकर है, वो जो हमें 80 हजार के आसपास मिलता है, वो अब वो डेढ़ लाख के आसपास मिलेगा यानी बढ़ा तो है लेकिन जो हमने भेजा था, जैसे हमने प्रस्ताव किया था..

माननीय अध्यक्षः अरे आपने ज्यादा बता दिया।

श्री विशेष रविः हैं।

माननीय अध्यक्षः बहुत ज्यादा बता दिया।

श्री विशेष रविः 1.20

माननीय अध्यक्षः 54 से 90,

श्री विशेष रविः सर मैंने 53,

माननीय अध्यक्षः पहले 54 हजार था,

माननीय अध्यक्षः हैं।

श्री विशेष रविः अगर 54 से करेंगे तो 90 ही हुआ है।

माननीय अध्यक्षः हां, 90,

श्री विशेष रविः 54 से करेंगे तो 90 होगा। मैंने जो डाटा आपरेटर था उसको लगाकर बताया था। तो अगर हम सिर्फ...

माननीय अध्यक्षः उसको मत जोड़िए भई। आप गलत, गलत कर रहे हैं सारा।

...व्यवधान...

श्री विशेष रविः अलग-अलग, अलग-अलग अगर,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः रवि जी, पढ़कर नहीं आए लगता।

श्री विशेष रविः 12 हजार का 30 हजार हुआ है और अगर हम 53 से बात करें या 54 से बात करें तो वो 90 हजार हुआ है।

माननीय अध्यक्षः हां, ये ठीक है।

श्री विशेष रविः ये सही आंकड़ा है। सर, जब ये हमने प्रस्ताव भेजा था तो उस समय हमारी विधान सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो लोग, जब 15 में हमने प्रस्ताव पास किया था तो लोग,

हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो इस प्रतीक्षा में थे कि हमने ये प्रस्ताव पास करके भेज दिया है, अब जब ये प्रस्ताव पास होकर आ जाएगा तो हम लोग जो है वो शादी या फिर विवाह जो है आराम से कर लेंगे। बहुत सारे मेरे साथी हैं, इसमें ऋतुराज जी हैं, संजीव भाई हैं, अखिलेश भाई हैं, मैं भी उस लिस्ट में हूं, हम लोगों ने ये सोचा था कि 15 में हमने ये भेजा है तो 6 महीने में या 8 महीने में ये प्रस्ताव पास होकर आ जाएगा, उसके बाद बढ़ी हुई सैलरी के साथ जो है, जो, हम जिनसे हम रिश्ता करने वाले हैं उनके परिवार को बताएंगे, जब पूछेंगे भई विधायक तो है लेकिन इनकी तनख्वाह क्या है, तो हम उनको जो है ये सम्मान-जनक राशि बता पाएंगे कि भई हमारी तनख्वाह जो है इतनी है। लेकिन समय बीतता गया और सैलरी नहीं बढ़ पाई तो अंत में ये हुआ कि सारे साथियों ने जो है वो एक-एक करके जो है शादियां कर ली और लेकिन सैलरी जो है वो नहीं बढ़ पाई। पूरे 7 साल, पूरे 7 साल लगे केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को पास करने के लिए और सर जो, जो गम्भीर बात है वो ये है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर अगर किसी के ऊपर भी आप जिम्मेदारी दे रहे है, उसको काम दे रहे है और उसको अगर उचित वेतन नहीं मिल रहा है,

श्री विशेष रवि: उसको उचित साधन नहीं मिल रहे हैं तो वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जो है वो ठीक से नहीं निभा पाएगा। उसको जो है कहीं न कहीं जो है परेशानी होगी और इस मामले में क्योंकि परेशानी जिसको होनी है वो जनता है जिसके लिए हम सब लोग यहां बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, सरकार चल रही है अगर उस जनता को परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि

वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। साधन और वेतन अच्छा होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं होगा आपके पास तो फिर वो आदमी जिसको साधन कम मिल रहे हैं, वेतन कम मिल रहे हैं, दबाव बहुत ज्यादा है काम का तो वो क्या करेगा वो यहां वहां देखेगा। और जब वो यहां वहां देखेगा अपने साधनों की पूर्ति करने की कोशिश करेगा तो उससे जो है अल्टीमेटली नुकसान जो है वो सरकार का, सिस्टम का, और जनता तक पहुंचेगा क्योंकि वो अपने काम ठीक से नहीं कर पायेगा। तो आज सर ये जो प्रस्ताव पास हुआ है मैं सबको बधाई देता हूं सारे अपने विधायक साथियों को कि 7 साल में ही सही लेकिन ये आपके कारण ये विधेयक पास हुआ है और शायद अब ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा उनसे स्वीकृति के लिए। अब क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के भी चुनाव होने वाले हैं तो शायद उसमें और कुछ समय लग जाए लेकिन कम से कम अब यहां से निकलने के बाद कोई वापस आने की जो है इसकी उम्मीद नहीं है जो भी समय लगेगा इसको जाके स्वीकृति में लगेगा। आखिर में सर मैं बधाई देते हुए इतना कहूंगा कि सेलेरी के अलावा सर दो प्रस्ताव और हमारी कमेटी ने पास किए थे वो था एक तो डाटा आपरेटर के बारे में और दूसरा जो गाड़ी पे, विधायक किसी को गाड़ी लेनी है उस पर जो रेट आफ इंटरस्ट है वो बहुत ज्यादा है। डाटा आपरेटर्स सर हमें जो दिए हुए हैं इस समय... तो डाटा आपरेटर हमारे को अभी दिए हुए हैं सर वो दो दिए सरकारके अंदर और उनकी जो तनख्वाह हमें दी जाती है, भत्ते हमें दिए जाते हैं वो 15 हजार रूपये मात्र है। तो सर आज जो विधायक कार्यालय पर जो बोझ है, इतना काम का लोड है, इतनी सारी जो हैं स्कीम्स हैं सरकार की, उनको जो है उस डाटा आपरेटर्स से कर पाना जो है वो संभव नहीं है।

मेरा इसमें जो है आज इस मौके पर प्रस्ताव है कि जो डाटा आपरेटर जो हमें दिए गए हैं एक तो उनकी संख्या दो के बदले 4 की जाए और जो उनको हम तनख्वाह दे रहे हैं 15 हजार रूपये, सर आज की डेट में दिल्ली के अंदर कम से कम जो अनस्किल्ड है सर जो लेबर है वो भी 15 हजार में नहीं मिलती सर। मुझे ये कहना है सर कि कम से कम जो स्किल्ड लेबर की जो हम तनख्वाह दे रहे हैं क्योंकि डाटा आपरेटर का काम अब वो काम नहीं है कि सिर्फ नामों की एंट्री करना है उसको भी बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो एक स्किल्ड व्यक्ति ही कर सकता है। तो जो स्किल्ड व्यक्ति को जो तनख्वाह दिल्ली सरकार या दिल्ली के अंदर दी जा रही है वही तनख्वाह 25 से 30 हजार रूपये के अंदर जो है वो हमारे लिए भी डाटा आपरेटर जो हैं उनको दिए जाए और उनकी संख्या को डबल किया जाए साथ में सर ये जो मैंने कहा कि जो इस समय विधान सभा से अगर हमें गाड़ी लेनी हो या मुझे गाड़ी लेनी हो जैसे मान लीजिए तो 11 परसेंट जो है सर विधान सभा जो है वो रेट आफ इंटरस्ट लेती है। सर 11 परसेंट तो सर मार्किट में साढे सात परसेंट मिल रहा है कोई भी आप अगर गाड़ी लेने जाएं और विधान सभा में 11 परसेंट है। तो मेरा सर ये भी प्रस्ताव है कि इसको जो है खत्म किया जाए, इसको जो है जीरो इंटरस्ट किया जाए जो भी विधायक जो है वो गाड़ी लेना चाहे सर क्योंकि पहले स्वीकृति हमें 8 लाख की गाड़ी के लिए थी।...

माननीय अध्यक्षः अब कंक्ल्यूड करिए विशेष जी, कंक्ल्यूड करिए प्लीज।

श्री विशेष रविः सर अभी जो स्वीकृति हो कर आयी है 10 लाख की होके आई है। तो अब 10 लाख तक की गाड़ी वैसे मिलती भी नहीं है तो

मेरा बस आखिर में ये कहना है कि इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करे और इसको भी ऐलान कर दे क्योंकि ये दोनों काम सरकार से ही होने हैं वो केन्द्र सरकार के पास इसको जाने की जरूरत नहीं है हमने ही इनको करना है तो अगरइन दोनों को भी कर देंगे तो जो केन्द्र सरकार ने तनख्वाह हमारी कम की है, कम बढ़ा के भेजी है तो उसका लोड जो है कुछ कम होगा और सभी विधायकों को जो है इसमें जो है राहत मिलेगी। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिन्द, वंदे मातरम।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हालांकि सारी बातें विस्तार से विशेष भाई ने बता दिया कि आखिर ये जरूरत क्यूं थी और मैं सबसे पहले सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं और मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद करता हूं कि 7 साल के संघर्ष के बाद ही सही आज ये बिल सदन में पेश हुआ। बिल्कुल ठीक कहा विशेष भाई ने कि 2015 से ये संघर्ष शुरू हुआ था। 2015 में जब ये प्रपोजल हाउस में आया उसके बाद हमारे अपोजिशन के साथी हैं मतलब इनका प्रॉपगैंडा का मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है ये देखिए कि प्रपोजल आया इन्होंने कहा कि सेलेरी बढ़ गयी। यहां तक कि गूगल अभी टाईप कीजिए कि दिल्ली के विधायकों की सेलेरी तो 2 लाख या 3 लाख दिखा रहा है, 2 लाख 10 हजार। ये इनका झूठ का प्रॉपगैंडा का मशीन मुझे लगता है कि 7 साल के बाद जब ये बिल हाउस में आया तो एक्सपोज भी हो रहा है और देश को समझना भी चाहिए कि किस तरह से ये लोग झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं और लोग

उस बात को मान लेते हैं। मैं ये मानता हूं कि अभी जो ये प्रपोजल आया है 2015 में सदन ने जो प्रपोज किया था उसको बहुत शार्टन करके ये आज हाउस में ये बिल पेश हो रहा है। मैं कुछ स्टेट का देख रहा था सैलेरी शायद ये तेलंगाना का देख रहा हूं मैं 2 लाख 50 हजार, उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं 2 लाख 10 हजार, आंध्र प्रदेश 1 लाख 75 हजार, गोवा में 1 लाख 99 हजार, हिमाचल में 1 लाख 90 हजार, उत्तराखंड में 2 लाख 4 हजार। दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहां तो खर्चे उस स्टेट की अगर तुलना करें तो ये कई गुणा ज्यादा खर्चा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि आज जो बिल पेश हो रहा है, जो प्रपोज किया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि दिल्ली में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का है और उसी को देखते हुए सांइटिफिकली डिजाईन किया गया था। लेकिन ये भी जैसे दिल्ली के साथ हमेशा होता रहा है ये केन्द्र सरकार की एक जो राजनीति है उसकी ये भेंट चढ़ गया। मैं ये मानता हूं कि चलो आज जो कुछ भी बिल के जरिये जो आपने मंत्री जी ने आज सदन में पेश किया अलग अलग विधायक का, मंत्री का, सदन का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, हमारे लीडर आफ अपोजिशन का, मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ में दो तीन बातें विशेष भाई ने कहा है, मुझे लगता है बहुत गंभीर और बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा सर कि अगर हम गाड़ी लेते हैं मार्किट में 6 परसेंट, साढे 6 परसेंट का इंटरस्ट रेट और यहां ये 11 परसेंट का इंटरस्ट रेट और मुझे लगता है ये सदन का अधिकार है ये। तो सदन इसको कम से कम गाड़ी लेने का जो लोन है उसको इंटरस्ट फ्री कर दे ताकि लोग गाड़ी खरीद सकें। मेरा तो प्रपोजल यह है कि अभी दिल्ली सरकार की केबिनेट ने यह फैसला किया है कि सभी व्हीकल्स

जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। मुझे लगता है ये सदन में सभी विधायकों में भी कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाईड किए जाएं, सर फायदे भी हैं। एक तो पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है दिल्ली सरकार बहुत गंभीर है इस बात पे, तो वो भी, पर्यावरण संरक्षण भी जो जाएगा, क्षेत्र में लोग देखेंगे प्रचार भी होगा और हम लोगों का आना जाना, आपका एक काम अगर किसी ब्यूरोक्रेट से हो गया तो एक बार जाने से होता नहीं है तो बार बार जो आना जाना लगा रहता है तो उसमें जो खर्चा होता है उससे हम लोग बचेंगे। दूसरी भी प्रपोजल जो विशेष भाई ने कहा मैं उनका समर्थन करता हूं कि काम विधायक कार्यालय में बहुत बढ़ गया है, बहुत भीड़ रहती है। तो पहली बात कि इसको जिन्होंने कहा कि दो से उसको 4 कर दिया जाए और साथ में हमने आपको चिट्ठी लिख के भी दिया था और सारे विधायक ने कहा था कि अब भीड़भाड होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने कहा था कि सिविल डिफेंस का स्टाफ को नियुक्त कर दिया जाए। मैं ये मानता हूं कि ये सदन के अधिकार क्षेत्र में है इसके लिए हमें मंत्री या केबिनेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस सदन के मुखिया हैं और सदन के अधिकार क्षेत्र का विषय है तो इसको लगातार विधायक बहुत वर्षो से उठाते रहे हैं इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। अभी आंगनवाड़ी का प्रोटेस्ट हो रहा था। हर एक विधायक आफिस में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ किया, मारपीट की, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उससे अपने आपको सुरक्षित रखना या उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो भी अगर साथ में एड हो जाए तो मैं मानता हूं कि ये अच्छा रहेगा। तो ज्यादा न कहते हुए बस मैं आपका और अपने कैबिनेट

का आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये बिल सदन में पेश हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री अनिल बाजपेयी जी।

श्री अनिल बाजपेयीः मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने महत्वपूर्ण मसले पर मुझे बोलने का अवसर दिया और हम लोगों के लिए खुशी की बात भी है कि देर आए दुरूस्त आए कम से कम विधायकों की सेलेरी कुछ तो बढ़ने जा रही है और हम सारे विधायक हम लोग चिंतित रहते थे। लेकिन हमारे आतंरिक मतभेद कुछ भी रहे लेकिन जब भी कमेटी की मीटिंग सेलेरी बढ़ाने के लिए हुई हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम सभी लोग एक स्वर से इस विधान सभा में हम सब लोग मिल कर एक दूसरे के साथ खड़े रहे। क्यूंकि ये हम सब लोगों का भविष्य भी कहीं न कहीं डिपेंड करता है। लेकिन कुछ चीजें जरूर हैं हो न हो ये तो सदन के ऊपर डिपेंड करता है आगे। जैसे 12 हजार रूपये से 50 हजार कर दिया गया मतलब ये कम है। अगर...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तीस हजार किया गया है।

श्री अनिल बाजपेयीः तीस हजार रूपये है और राज्यों के अनुपातिक अगर आप देखें पूरे भारत वर्ष के राज्यों को तो ये बहुत कम है ये और विधायक जब मिलते हैं दिल्ली से हम बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब आपकी कितनी सेलेरी है हम कहते हैं जी 12 हजार है। बोलते हैं केवल 12 हजार

है तो हम लोगों को भी बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस करते है तो 12 से 30 कम है कम से कम 50 हजार ये होना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है ये। मीटिंगों की बात होती है 1 हजार रूपये हमको पर मीटिंग हम लोगों को मिलता है। 1500 किया गया है, ये भी कम है। कम से कम सर 2 हजार तो पर मीटिंग का होना चाहिए क्योंकि अभी 1 हजार मिलता है हमको पर मीटिंग में, अब 1500 का है। 2 हजार रूपये कम से होना चाहिए। 40 मीटिंग अगर हैं तो अगर 2000 भी मिलेगा तो कम से कम विधायकों को कुछ उसका फायदा होगा। अभी संजीव भाई भी कह रहे थे कि हम लोगों की विधान सभा में काफी संख्या में लोग आते हैं और आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली है और इसके अंदर 18 से 25 हजार रूपये किया गया है। कम से कम 50 हजार रूपये ये भी होना चाहिए। ये मेरा मानना है। गाड़ी की बात रखी गयी है कि 4 से 8 लाख रूपये लोन हो जाएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन जब हम लोग अपनी गाड़ी फाइनांस कराने के लिए कहते हैं भई विधान सभा में लोग भी कंस्टीट्यूएंसी में पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं अरे भाई गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो आपको तो जीरो परसेंट पर मिल गयी होगी। तो बड़ा अजीब सा लगता है सर। और अगर हम बाहर से अगर गाड़ी फाइनांस कराएं तो हमको कम इंटरस्ट देना पड़ता है और अगर दिल्ली विधान सभा के थ्रू अगर हम लोग करें तो हम को इंटरस्ट कहीं न कहीं ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जीरो परसेंट वाली जो बात है और पूरे देश के अंदर ये उपलब्ध है कि अगर हम सभी विधायकों को अगर गाड़ी लेनी हो तो अगर जीरो परसेंट पर अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। बात पेंशन की भी आती है सर। आप सब लोग विधायक हैं, कल सत्ता में कुछ पता नहीं

होता कौन कहां होता है। लेकिन जो 7500 रूपये जो पेंशन है मैं समझता हूं ये बहुत कम है। अगर और राज्यों में देखें आप तो 60 हजार पेंशन है सर ये। और यहां केवल 7500 रूपये तो रिटायरमेंट के बाद 7500 रूपये जो पेंशन है ये बहुत कम है, इसको कम से कम सर 50 हजार रूपये तो कम से कम होना चाहिए। ये मेरा मानना है। एक बात सर और भी है कि सदन में सबकी सेलेरी बढ़ाई गयी है सर आपकी भी बढ़ाई गयी, मुख्यमंत्री जी की, मंत्रियों की भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष की भी जो है सेलेरी बढ़ाई गयी और हमारे दिलीप पांडे जी मुख्य सचेतक की भी सेलेरी बढ़ाई गयी है। तो विपक्ष में भी हमारे मुख्य सचेतक हैं तो कम से कम विपक्ष के मुख्य सचेतक की भी सेलेरी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। ये मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद धन्यवाद।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः और सर एक प्वाईट और है। और हम इतना कहना चाहते हैं जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे विशेष रवि जी कि बहुत साल ये हमारा केन्द्र सरकार में पेंडिंग रहा। कई बार हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो अधिकारी हैं क्योंकि मीटिंग में कई अधिकारी विशेष भाई बुलाते थे तो कई बार दिल्ली सरकार ने भी जो हमारा प्रपोजल था उस फाईल को रोका गया, कई बार इसके बारे में जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने भी काफी प्रयास किया है इस संबंध में, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कम से कम लेकिन थोड़ा कहीं न कहीं हम लोगों से भी गलती सर हुई है, हमने एक साथ सारी सेलेरी का प्रपोजल दे दिया। अगर और राज्यों में अगर आप देखें कि हर साल कोई न कोई प्रस्ताव विधायकों की सेलेरी के बढ़ाने में आता है। आज अगर

ये प्रस्ताव पास हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि अगले सेशन में या अगले साल जो भी हो कम से कम एक नया प्रस्ताव जो विधान सभा के सारे सदस्यों को देखते हुए ये कम से कम होना चाहिए। ये मेरा मानना है सर ये। और हर साल सर एक प्रस्ताव विधायकों की सेलेरी बढ़ाने के लिए होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं अगर ये बात मैं आज रख रहा हूं तो सत्ता पक्ष भी हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें हमारा समर्थन करेंगे। इसके साथ हो या नहीं हो बताओ?... साथ हो न, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज सदन में कैलाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। और ये बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है 2014 में जब हम पहली बार विधायक बने, बल्कि 13 में बनें थे, 13 के दिसम्बर में तभी से ये बात चल रही थी कि किसी तरह से जो है सेलेरी को इतना जरूर किया जाना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा, समझदार आदमी विधायक बन के इस सदन के अंदर लंबे समय तक सेवा दे सके और एक sustainable model जो है वो इस विधान सभा का विधायिका का बन सके। अध्यक्ष जी, कई बार मैं सुनता हूं और कई बार इसके ऊपर समाज के अंदर चर्चा होती है कि भई आप लोग विधायक जो है वो सेलेरी लेने के लिए कोई न बनें, आप लोग तो सेवा करने के लिए आए थे और मैं सुनता हूं कि यही चर्चा जो है कुछ दिनों पहले जब हम अग्निवीर की बात कर रहे थे तब भी कही गयी कि भई वो वहां पर पेंशन लेने के

लिए कोई न जाते हैं, वो तो वहां पर सेवा करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मेरा अध्यक्ष जी, ये मानना है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर सहमत भी होंगे कि सेवा अपने आप में एक अच्छा कांसेप्ट है। मगर जो व्यवहारिकता है समाज की व्यवहारिकता है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग एक hypocritical society के अंदर आजकल जी रहे हैं जिसके अंदर सारी की सारी अपेक्षाएं जो हैं वो विधायकों से, सांसदों से, जजिज से, पुलिस से, फौज से, इनसे सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस सारी दुनिया को है मगर कोई इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग भी इंसान हैं। इनके भी परिवार हैं, ये लोग भी पढ़लिख के अच्छी युनिवर्सिटी से, अच्छे कालेज से पढ़े हैं, ये अपना परिवार कैसे चलाएंगे? अध्यक्ष जी और सबसे बड़ा एतराज जो है मुझे दिल्ली की मीडिया से रहेगा कि पिछली बार जब सेलेरी बढ़ाने का बिल इस सदन से भेजा गया केंद्र सरकार को तो दिल्ली की मीडिया ने खासतौर पर इसको प्रचारित किया कि दिल्ली की सेलेरी बढ़ गयी है। अध्यक्ष जी, कई बार इसकी शिकायतें भी हमारे पास आई आप आज भी अगर गूगल करके देखें कि दिल्ली के विधायक की सेलेरी कितनी है, तो कम से कम 15-20 वेबसाईट्स ऐसी हैं इंक्ल्यूडिंग न्यूज चैनल्स की वेबसाईट्स जिसके अंदर ये सेलेरी 2 लाख 10 हजार, ढाई लाख, इस तरीके की सेलेरी जो है वो आती हैं। कई बार रिलेटिव्स के बीच में, दोस्तों के बीच में भी चर्चा हो जाती है वो कहते हैं भई कितनी सेलेरी है हम बताते हैं 12 हजार सेलेरी है। तो तुरंत गूगल करके कहते हैं देख यहां तो 2 लाख 10 हजार रूपये लगी हुई है, झूठ बोल रहे हो। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है कि आपकी चेयर से आज जो है हमारे मीडिया के मित्रों को भी जो है ये हमारी तरफ से एक मैसेज जाए कि इस

खबर को सही तरीके से छापा जाए और हमारे मीडिया के साथी इस चीज को भी छापें कि ये सेलेरी जो है आज पहली बार बढ़ने का पूरा प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज भी बढ़ गए, वो प्रस्ताव जो 2015–16–17 मतलब कई सालों से जो चल रहा है वो प्रस्ताव अब फाइनली वापिस आया है केन्द्र सरकार से और अब वो दोबारा से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है। ये जो है हमारे मीडिया के साथी इसको बहुत ध्यान से छापें। और अध्यक्ष जी, इसके विषय में मैंने कई बाहर के देशों के बारे में ढूंढ़ा, बाहर के देशों में इसके बारे में बड़ा क्लियर थॉट है। वहां के लोग ये बात मानते हैं और इसके ऊपर कई तरीके की रिसर्चिज जो है अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों के अंदर हुई हैं जैसे मैं अमरीका की या एक सिंगापुर की एक स्टडी के बारे में आपको बताता हूं जिसके अंदर वहां के प्रधान मंत्री ने बोला इस मुद्दे पर 1994 में while high income should never be the motivation for a person to become a minister paying realistic salaries that do not impose unrealistic large financial scarifies on those contemplating political office will reduce one significant obstacle to able Singaporeans to enter politics और अध्यक्ष जी इसके बारें में और कई रिसर्चिज जर्मनी में, न्यूजीलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, अमरीका के अंदर हुई हैं जहां पर अमरीका ने तो यहां तक कहा उनकी रिसर्च The Voters' Blunt tool के अंदर छपी। उसके अंदर ये बताया गया कि अगर आप अपने elected representative को कम तनख्वाह देते हैं तो वो समाज के अमीर लोगों से अमीर पूंजीपतियों से कहीं न कहीं उनसे थोड़ा बहुत जो है फायदा लेने की कोशिश करेगा। और जब वो समाज के अमीर वर्ग से पूंजीपति वर्ग

से, उद्योगपति वर्ग से फायदा लेगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर जिस हाउस के अंदर बैठ के पॉलिसी बनाएगा, कानून बनाएगा वो उस अमीर पूंजीपति वर्ग की तरफ थोड़ा सा जो है उसका झुकाव होगा तो ये बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी कि आपका जो लेजिस्लेचर है, जो आपका कानून बनाता है उसको आप इतनी तनख्वाह जरूर दें कि उसका घर जो है अच्छे से चल सके, डिग्निटी से चल सके, यहां तक कि नारायणमूर्ति साहब ने जब इंफोसिस की शुरूआत की तो उनका भी ये मानना था कि सेलेरीज और इंसेंटिव्स आप अच्छे दें तभी आप अच्छे टेलेंट को ला सकते हैं। और अध्यक्ष जी, हमारा देश जहां पर करीब 45 परसेंट लोग जो हैं मिडल क्लास के अंदर हैं, जहां पर आज बच्चे आईआईटी करते हैं, आईआईएम करते हैं, डाक्टर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्रीज लेते हैं, अध्यक्ष जी, हमारा ये दायित्व बनता है विधायक के तौर पर, और इस विधायिका के तौर पर कि हम इस विधान सभा के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाएं कि आज की जो नया युवा आ रहा है, बड़े बड़े आईआईएम और आईआईटी से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, बहुत शानदार उनके पास आईडियाज हैं, हमने आजकल टीवी पर देखा कि उन बच्चों के पास इतने अच्छे अच्छे आईडियाज हैं कि छोटी सी पूंजी से वो बड़े बड़े बिजनेस खड़े करने के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके आईडियाज के अंदर इंवेस्ट और पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोग हमारी विधान सभा में भी आ सकें, हमारी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें, यहां पर हमारे साथ बैठ के वो कानून के ऊपर चर्चा कर सकें, ये इस विधान सभा की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की एनवायर्नमेंट यहां पर क्रिएट करें और ये जो झूठी हिपोक्रेसी है कि साहब आप अगर विधायक बन गए तो आपको तनख्वाह की क्या जरूरत

है।तो सर तनख्वाह की क्यों नहीं जरूरत है, फिर हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारे घर में कैसे काम होंगे। मतलब मैं तो एक मिडल क्लास फैमिली में रहता हूं और अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ हमारे पुश्तैनी मकान में रहता हूं तो मेरा तो खर्चा चल जाता है अध्यक्ष जी, मेरा तो भाई 6 लाख रूपये महीना कमाता है, उसकी वजह से मेरा खर्चा चल जाता है। मगर ऐसे हमारे विधायक साथी हैं सर जो यहां पर किराए के मकान में रहते हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट करने का नहीं है, आप सोचिए 12 हजार रूपये सेलेरी और कई अखबार उसको बेसिक सेलेरी लिखते हैं वो गलत है, वो बेसिक सेलेरी नहीं है वो सेलेरी है। 12 हजार रूपये सेलेरी आपने विधायक को दे दी और आपने उसको विधान सभा के अंदर छोड़ दिया कि जाओ बेटा अब ईमानदारी से काम करो, ऐसा कैसे हो पाएगा। जो डेलीवेजिज है वो भी मुझे लग रहा है साढे 16 हजार रूपये कर दी गयी है। ये उसको बढ़ाते जाते हैं। अब 21 हजार हो गयी। और हमारी 12 हजार तनख्वाह है। अध्यक्ष जी, इतनी समस्या है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जानबूझकर नहीं बढ़ाई गयी जैसे अनिल बाजपेयी जी कह रहे थे कि वो इतने सालों से बढ़ा लेनी चाहिए थी। बढ़ा लेनी चाहिए थी मगर मुझे लगता है कि जो हौंसला और जो कोऑपरेशन हमें केंद्र सरकार से इसमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमने जो सेलेरीज बढ़ा के भेजी, केंद्र सरकार ने नहीं मानी और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से वो फिगर्स हमें वापिस भेजी हैं कि भई ये ये ये ये सेलेरी कर लो तो हमने सोचा, अपनी तो बढ़ा ली उन्होंने। तो अध्यक्ष जी, हमने सिर्फ ये सोचा कि अब केंद्र सरकार से कब तक लड़ते रहेंगे तो उन्होंने जो कहा वो हमने मान लिया। हमने कहा आप ने जो सेलेरी रिकमंड की है हम वही मान रहे हैं अब आपको भेज रहे

हैं। अब हमारा सिर्फ यही है कि बीजेपी के हमारे मित्र हैं सामने बैठे हैं, बिधूड़ी जी बैठे हैं, अब देखिए राष्ट्रपति महोदय के पास ये जायेगा तो इसके लिए आपकी मदद चाहिए कि आप इसको जो है फटाफट करा लें क्योंकि एक बेसिकली ये एक आखिरी स्टेप है और अगर आप चाहेंगे तो हमारे लोग भी आपके साथ चल सकते हैं और इस काम को जो है हम करवा लें। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एक दो बात कह के अध्यक्ष जी मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अध्यक्ष जी, मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार इतना है। ज्यादातर भ्रष्टाचार के बारे में हम बात करते हैं पुलिस के बारे में। मेरा मानना यह है कि दिल्ली पुलिस की सेलेरीज भी बढ़नी चाहिएं हमारे साथ साथ में। वो एक ऐसा महकमा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगते रहते हैं और उनकी तनख्वाहें भी बेहद कम हैं। हम उनकी तनख्वाहें इतनी कर दें इतनी अच्छी कर दें कि उनके घर की जिम्मेदारी वो आसानी से पूरी करें तो उनको भी इस तरीके की जो है किसी भी गलत चीज के अंदर हिस्सा लेने की जरूरत नहीं। मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूं कि विदेशों में जो बड़े बड़े देशों के उदाहरण हमारे यहां दिए जाते हैं कि वहां पर काफी ईमानदारी से लेजिस्लेचर्स जो है काम करते हैं, वहां की तनख्वाहों का मैं आपको उदाहरण दूं तो इटली के अंदर मेंबर आफ पार्लियामेंट को 8 लाख 59 हजार रूपये मिलते हैं महीने के, आस्ट्रिया के अंदर 8 लाख 34 हजार रूपये मिलते हैं, जर्मनी के अंदर 7 लाख 47 हजार रूपये मिलते हैं, यूके के अंदर 6 लाख 69 हजार रूपये मिलते हैं, डेनमार्क के अंदर 6 लाख 45 हजार रूपये मिलते हैं, नीदरलैंड्स के अंदर 6 लाख 15 हजार रूपये मिलते हैं, आयरलैंड के अंदर 5 लाख 98 हजार रूपये मिलते हैं। अध्यक्ष जी ये सारी बातें मैं इस हाउस

में इस लिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब कल हमारे अखबार के साथी इस खबर को छापें तो इसके साथ कई सारी चीजें छापें सिर्फ इसको एक पब्लिक के लिए एक माहौल बनाने के हिसाब से ही न किया जाए कि देखिए साहब इन्होंने जो है सेलेरी बढ़ा ली, ये भी लिखें कि ये सेलेरी कब से बढ़नी थी, कब नहीं बढ़ पाई, अब इतनी मुष्छिकल से बढ़ रही है। बाकी देशों के अंदर ये सेलेरी क्या रहती हैं, बाकी राज्यों में जैसा कि तेलंगाना के अंदर ढाई लाख सेलेरी है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कष्ठमीर, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा सब जगह जो है सैलेरी 1 लाख रूपये से ज्यादा है, कई जगह तो 2 लाख रूपये से ज्यादा सेलेरी है और अब देखिए मतलब प्रधान मंत्री का जिक्र भी बहुत देशों के अंदर जो है सादगी के लिए, वहां के प्रधानमंत्रियों का जिक्र भी आता है अध्यक्ष जी। मगर वहां पर उस सादगी को इस चीज से नहीं जोड़ा जाता कि उसको भूखा मार दो क्योंकि इसको सादगी से रहना है। उसको उतनी सेलेरी दी जाती है कि उसके घर में उसके बीवी बच्चों का, क्यूंकि ज्यादातर के यहांबीवी बच्चे होते हैं तो उनको दी जाती है कि भई वो अपने घर के अंदर जो है अपना इंतजाम कर ले। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि नीदरलैंड्स के अंदर वहां के प्राईम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूते। उनकी अक्सर जो है फोटो जो है इंडिया के अंदर भी सोशल मीडिया पर चलती है कि वो अपनी इलेक्ट्रिकल साईकिल से आफिस जाते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल दूं और जबकि वहां पर तनख्वाहें खूब दी जा रही हैं। एक और एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जकिंडा आर्डमऔर उनका इंटरव्यू लेने एक अमरीका से स्टीफन कालबर्ग नाम के एक एंकर उनका इंटरव्यू लेने अध्यक्ष जी न्यूजीलैंड गयी और उन्होंने वहां के न्यूजीलैंड के प्राईम मिनिस्टर्स आफिस

में बताया कि भई मैं प्राईम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने आ रहा हूं तो मेरे को कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दें और जब वो प्लेन से उतरे और उनको बताया गया कि आपकी गाड़ी यहां पर है तो स्वयं न्यूजीलैंड की प्रधान मंत्री गाड़ी चलाकर उनको लेने आई। ये है वहां का मतलब कि सिंपलीसिटी का उदाहरण मगर वो हमारी तरह से जो है वो हिपोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं करते कि नहीं हम तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेवा करने आए हैं, ये सब नहीं, जो काम प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बात करते हैं और मूल्य जो हैं, जो वैल्यूज जो हैं उनके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं दोबारा से विशेष रवि भाई का समर्थन भी करूंगा उन्होंने जो दो तीन बातें कही हैं कि डाटा एंट्री आपरेटर्स की जो है उनको 4 कर देना चाहिए अध्यक्ष जी क्योंकि अब बहुत सारे फार्म्स जो हैं वो ऑनलाइन एमएलए आफिस के अंदर भरवाए जाते हैं। जो गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंटरनेट नहीं कर सकते, वो हर चीज का जो फार्म है वो भरने विधायक कार्यालय में आते हैं और विधायक कार्यालय के अंदर हमारे लोग जो हैं उनकी एंट्री करते हैं तो उसको 4 कर दिया जाए और जो है प्रेजिडेंट एसेंटके लिए रामवीर बिधूड़ी जी जो हैं वो हमारी मदद करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जैसा कि विषय हमारा विधायकों की सेलेरी को लेकरके, मैं तो ये कहूंगी कि आज का ये शुभ दिन है और ये शुभ दिन मैं बधाई दूंगी दुर्गेश पाठक जी को, सदन में कुछ समय पहले आ गए होते तो शायद सेलेरी पहले ही बढ़ गयी होती।

अध्यक्ष महोदय, विष्य के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक राज्य के विधायी निकाय को राज्य विधान सभा कहा जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आने वाले व्यक्ति को हम विधायक कहते हैं। अब मुद्दा है विधायक की सेलेरी। सेलेरी अपने आप में एक अंग्रेजी शब्द है, हिन्दी में हम इसे वेतन कहते हैं, तनख्वाह कहते हैं, पगार कहते हैं और शब्दकोष में अगर वेतन का अर्थ जाना जाए तो वो धन जो किसी को भी कोई भी काम करने के पश्चात बदले में दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 1993 से 2021 तक सभी इटैलियन म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के डाटा से यह पता चलता है कि एक उच्च वेतन अधिक शिक्षित उम्मीद्वारों को आकर्षित करता है। और बेहतर भुगतान वाले राजनेता आंतरिक दक्षता में सुधार करके सरकारी तंत्र को आकार देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सिंगापुर के प्रधान मंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय अर्थात् अच्छी तनख्वाह, सिंगापुरवासियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे भाई सौरभ जी ने कहा अमरीका में किए गए एक अधययन द वोटर्स ब्लंट टूल का तर्क है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक भुगतान किया जाता है तो वे अपने आप को बनाए रखने में अधिक निवेश करते हैं और नागरिक अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने की संभावना भी अधिक रहती है। अध्यक्ष महोदय, अन्य लोगों के बीच विधानसभा के सदस्य को लोक सेवा प्रदान करने वाला और कानूनन लोक सेवक के रूप में माना गया है। बड़ी संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात का समर्थन किया है नवीनतम् मामले में से एक अष्ठिवनी कुमार उपाधयाय बनाम भारत संघ है। यह कानूनी प्रावधान होने के कारण एक विधायक एक लोकसेवक है। लोकसेवक को शासित करने वाली ष्ठार्तें भारत के संविधान अनुच्छेद संख्या नंबर

309 से 311 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत शामिल है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मौलिक नियम और पूरक नियम भी लोकसेवक के वेतन के नियमन के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रमुख नियम है जिसे अगला नियम कहा जाता है। इसे हम अंग्रेजी में नेक्स्ट बिलो रूल कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नियम के तहत किसी व्यक्ति का वेतन यदि कनिष्ठ से कम है तो वरिष्ठ का वेतन इतना बढ़ा दिया जाता है कि इसे कनिष्ठ से अधिक कर दिया जाता है। माना जाता है कि वारंट आफ प्रेजिडेंट के अनुसार विधायक राज्य के मुख्य सचिव के उच्च पद पर होता है। ऐसा होने पर नीचे दिए गए नियम वेतन को इतना बढ़ाने के लिए एक मजबूत मामला बनाते हैं और उच्चतम सिविल सेवक यानि राज्य के प्रमुख सचिव के पद पर विराजमान रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिसम्बर, 2015 में विधायकों की सेलेरी को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी आपके अपने एक वक्तव्य में हमने ये सुना कि पिछले 11 साल पहले विधायकों की सेलेरी बढ़ाई गयी थी। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के सदस्यों की सेलेरी हर दो साल में बढ़ाई जाती है। हमारा एक आफिशियल टूर रहा हिमाचल के लिए, वहां स्वयं हमारी कमेटी ने स्पीकर साहब से बात की। सेलेरी के संबंध में हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि जब जब राज्य के अंदर महंगाई बढ़ती है तब तब विशेष तौर पर एक प्रस्ताव हाउस के अंदर लाया जाता है और हाउस में प्रस्ताव लाकर के उसको पास कर दिया जाता है और इस तरह से जितने भी विधायक उनके सदन में हैं, उनकी सेलेरी को बढ़ा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि 11 साल बाद इतनी कम सेलेरी की जो बढ़ोतरी की है क्या वो अपने

आप में सही है? अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पिछले 7 सालों से विराजमान है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं होती, यहां बीजेपी की सरकार विद्यमान होती तो ये सेलेरी आज से 7 साल पहले बढ़ गयी होती, उसका इंतजार नहीं करना पड़ता। और वो भी रेंग रेंग कर नहीं बढ़ती। जब सेलेरी कमेटी ने बिल केंद्र सरकार को भेजा 2015 में तो उस समय महंगाई को देखते हुए, पारिवारिक खर्चों को देखते हुए लगभग 2 लाख 10 हजार का एस्टीमेट बनाकर के केन्द्र सरकार को भेजा। महंगाई अगर हिमाचल में बढ़ती हैं, महंगाई अगर हरियाणा में बढ़ती है, महंगाई किसी दूसरे राज्य में बढ़ती है तो क्या महंगाई दिल्ली राज्य के अंदर नहीं बढ़ती। अगर सेलेरी हिमाचल के लोगों की, अगर सेलेरी हरियाणा, तेलंगाना के लोगों की बढ़ सकती है तो दिल्ली के अंदर उस महंगाई को देखते हुए क्या यहां के विधायकों के पेट नहीं लगे, क्या यहां के विधायकों के परिवार नहीं हैं, क्या यहां के विधायकों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगी क्योंकि सभी साथी लगभग वो सब बात कह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के विधायकों को भी अन्य राज्यों के बराबर ही सेलेरी और भत्ते मिलने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मालूम हो दिल्ली के विधायक देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से एक हैं। यानि देश के अंदर राज्यों के विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है उनकी तुलना में दिल्ली के विधायकों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। भारत के विधायकों में सबसे ज्यादा सेलेरी तेलंगाना की है। यहां सभी भत्तों को मिलाकर एक विधायक को हर महीने 2 लाख 50 हजार रूपये दिए जाते हैं, उतराखंड 1 लाख 98 हजार, हिमाचल 1 लाख 90 हजार, हरियाणा

1 लाख 55 हजार, बिहार 1 लाख 30 हजार, आंध्र प्रदेश 1 लाख 25 हजार, गुजरात 1 लाख 5 हजार, उत्तर प्रदेश 1 लाख 87 हजार, महाराष्ट्र 2 लाख 32 हजार, जम्मू कश्मीर 1 लाख 60 हजार, मधय प्रदेश 1 लाख 10 हजार . ..

माननीय अध्यक्षः भावना जी कंक्ल्यूड करिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः राजस्थान 1 लाख 25 हजार। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि...

माननीय अध्यक्षः नहीं कंक्ल्यूड करिए अब, कंक्ल्यूड करिए प्लीज।

सुश्री भावना गौड़ः ठीक है सर। जैसा कि अभी सौरभ भाई ने बताया एक बड़ा अजीब सा असमंजस लोगों के दिमाग में है। दिल्ली के विधायकों की सेलेरी बढ़ रही है। किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और गूगल को खोलकर के देखता है। गूगल के अंदर आज से नहीं, कई बरसों से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के विधायकों की सेलेरी 2 लाख 10 हजार रूपये दिखाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रुटि है। इसे ठीक करना चाहिए और मुझे लगता है कि इस सदन के माध्यम से यह प्रस्ताव पास होना चाहिए कि जिसने भी यू ट्यूब के ऊपर डाला है या गूगल पर डाला हुआ है वो किन लोगों की गल्तियों के कारण से डला हुआ है, सदन इस प्वाईंट पर विचार करे। अध्यक्ष महोदय, आज विधायकों के वेतन और भत्तों को लेकर के संशोधन बिल पेश किया गया है, लगभग 6 साल बाद ये बिलइस सदन के अंदर आया है। मैं इस सदन के पटल से विधायकों के वेतन और संशोध

न संबंधी बिल का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

...व्यवधान...

श्रीमति राखी बिरलाः अध्यक्ष जी मुझे एक बात बोलनी है

माननीय अध्यक्षः दो मिनट रूको।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब दो मिनट रूकिए। हां रूकिए न।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो सेलेरी बिल हाउस में कैलाश जी ने प्रजेंट किया है, टेबल किया है उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, साथियों ने बहुत विस्तार से चूंकि एक paradigm shift है चूंकि सेलेरी बिल पर जिस प्रकार की बातें हमारे साथियों ने रखी हैं सदन के अंदर, ये अपने आप में जरूरी है। आज तक घर के खर्चे की बात, बच्चों के खर्चे की बात परिवार के खर्चे की बात मुझे नहीं लगता कि किसी सदन में रखी गयी होगी। अध्यक्ष महोदय, एक और बात इससे साफ हो गयी 2015 में 2 लाख 10 हजार सेलेरी बढ़ गयी तब से हम गालियां सह रहे हैं कि सेलेरी आपकी 2 लाख 10 हजार हो गयी। तो कम से कम इस बिल के माध्यम से पूरी दुनिया को और सब को मालूम पड़ेगा कि भई इनकी सेलेरी 90 हजार हुई है वो भी अब हुई है।

...व्यवधान...

श्री सोमनाथ भारती: पूरा मिला कर 12 से 30 हो गयी। तो सेलरी 12 से 30 हजार हुई, साथी ठीक कह रहे हैं। तो 12 से 30 हजार सेलेरी हुई है जबकि अभी हमने मिनिमम वेजिज को 21 हजार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये शुभ है भारतीय राजनीति में इस प्रकार की बातें आज सदन के अंदर साथियों ने की हैं ये अपने आप में बहुत शुभ है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक राजनीति हिन्दुस्तान के अंदर राजा रजवाड़े कर रहे थे। किसको सेलेरी की जरूरत थी? उन्हें जरूरत ही नहीं थी। तो कौन सेलेरी की बात करे याजो महाराष्ट्र में लोग जो वहां से गुवाहाटी गए उनको सेलेरी की जरूरत नहीं है। तो सेलेरी की जरूरत उनको पड़ती है जिन्होंने राजनीति में बदलाव किया है। जब आम आदमियों की एंट्री हुई हम जैसे कई साथी जीवन में सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी विधायक बनेंगे, कभी एमपी बनेंगे, कभी राज्यसभा जायेंगे, ये तो केजरीवाल जी की लीडरशिप के अंदर आम आदमियों की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई है, ये बहुत अपने आप में एक अद्वितीय बात है और उसी के कारण हर व्यक्ति को ये पिंच कर रहा था शुरू से चूंकिहमने ईमानदारी की कसम खा रखी है। हमारे नेता भी कहते हैं, हम सारे अपने क्षेत्रों में कहते हैं कि भई कट्टर अगर कोई ईमानदारी का सबूत इस राजनीति में है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे सारे साथी हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम देखें चूंकिबड़ा थिन लाईन है जहां सेलेरी बढ़ाने की बात करते हैं लगता है कि पता नहीं क्यों सेलेरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेताओं की जो एक इमेज बना रखी है इतना भ्रष्टाचार हर तरफ दिखता है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कैसे कैसे

लोग हैं, कोई एक रूपया की सेलेरी लिया करता था, सेलेरी एक रूपया की और घर से निकले 70 हजार सैंडल। जब वो इनकम टैक्स वाले पहुंचे। तो ये एक रूपये में तो नहीं आती सारी ये चीजें। तो अध्यक्ष महोदय, ये बहुत शुभ है। मैं अपने साथियों को बधाई देता हूं और साथ में ये मुझे याद है चूंकिजब हम 28 एमएलए थे 2013 में, तब भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। 12 हजार की सेलेरी पाने वाला विधायक 5 करोड़ में नहीं बिका। मैं अपने साथियों को बधाई देता हूं कि 12 हजार की सेलेरी पाने वाला विधायक वेट किया कि कब लेजिटिमेट तरीके से कब सदन के अंदर ये सेलेरी बिल पास होगा और हम थोड़े से कंफर्टेबल हो पाएंगे। जो सौरभ जी ने बात रखी बहुत अच्छी बात रखी जो सिंगापुर के पीएम ने कहा कि भई हम सेलेरी के लिए यहां पर नहीं आए हैं, लेकिन जब तक आप एक सांसद की, एक विधायक की लाईफ को कंफर्टेबल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं कर पाएगा, इन फैक्ट वो जो सिंगापुर के अंदर एक कमेटी बैठी थी उसमें साफ साफ कहा गया बड़ा इंटरस्टिंग लाइन है Salaries must be competitive, so that people of the right caliber are not deterred from stepping forward to lead the country. It must be there unless and until we make situations around, surroundings around comfortable,we will not be able to attract best of the minds, brilliant minds, those minds who can do wonders, if they go to parliaments and assemblies.

अध्यक्ष महोदय, I mean basically gradually we are proceeding towards कि वो पॉलिटिक्स प्रोफैशनलाइज हो। आपको यहां पर कोई टाईम बाउंड तो होता नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी है, रात को 2 बजे भी जनता आ रही है, सवेरे

5 बजे भी जनता आ रही है, लोग पानी चेक करने के लिए जा रहे हैं सवेरे सवेरे तो आपके पास मूलतः और टाईम नहीं बचता कि आप कुछ कर सकें अगर आप एक जेनुइन विधायक हैं, जेनुइन सांसद हैं तो आपके पास और कोई टाईम नहीं है कि आप कुछ और कर सकें। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें मैंने कभी अरविंद जी को भी कहा था कि अगर आप सेलेरी वहां बढ़ाने में तकलीफ हो रही है तो कम से कम संसाधन दे दें। 4 स्टाफ और दे दें। जो सहूलियतें हैं वो दे दें। अभी हमारे आफिसिस में लोग नहीं हैं कि हम चिट्ठियां टाईप करवा सकें, हम खुद ही करते रहते हैं।...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी, कंक्ल्यूड करिए प्लीज, कंक्ल्यूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आज परफार्मेंस जो हम डिमांड करते हैं लोगों से चूंकि अगर हमने थिन लाइन है, मैंने पहले भी कहा कि लोग जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो सुनना पड़ता है लेकिन अब ग्रेजुअली दिल्ली के विधायकों ने खास कर के अब पंजाब के विधायकों में जो हमारे पंजाब में सरकार बनी है एक नयी फीलिंग पैदा की है कि भई ये तो काम करने वाले लोग हैं, अब लोग सोचते हैं, देखते हैं। पहले गालियां पड़ती थी कि ये सिर्फ सेलेरी लेते हैं। ये सिर्फ एयर कंडीशंड में बैठे रहते हैं, जनता का फोन नहीं उठाते, किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन अब जनता ये फील करने लगी है कि भई इनसे अगर हमें काम लेना है तो इनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। मैं चूंकि बड़ा अच्छा एक बात कहा था कि भई अगर low paid legislators रहेगा तो he will not only be hijacked by corporates specially crony capitalists - आप देख रहे हैं पूरे देश में किस प्रकार से बातें चल रही हैं और ये बहुत खतरे का विषय है चूंकि डेमोक्रेसी

की सारी व्यवस्था जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि जो असेम्बलिज में और जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो किस प्रकार से अपने आप को इन चीजों से aloof रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा अभी साथियों ने भी कहा...

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी अब कंक्ल्यूड करिए प्लीज। प्लीज कंक्ल्यूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः वन मिनट मोर। तेलंगाना का सेलेरी 2.5 लाख है, महाराष्ट्र का सेलेरी 2.32 लाख है, बहुत ज्यादा है लेकिन जब मैं देखता हूं कि दिल्ली का जो cost of living है, cost of living का जो proportional करते है भई किस प्रकार से इनकी सेलेरी होनी चाहिए, किस प्रकार से इनको सुविधायें उपलब्ध कराना चाहिए तो उस लिहाज से जो ये 12 से 30 हजार हुआ है ये तो बहुत ही कम है, ये शुक्र है कुछ हम जैसे लोग मैं तो देख पाता हूं जैसे हमारे प्रवीन हैं, वो अब जो किराये पर व्यक्ति हमारा विधायक रह रहा हैं परमात्मा साथ दे कैसे गुजारा करे, परमात्मा जानता है लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि अगर विधायकों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए it is a mental torture to keep them living in such a poverty and जो कुछ भी हुआ है हमारे अनिल बाजपेयी जी ने भी कहा कि भई हर साल, दो साल में अगर आपको inflation के according proportional में सेलेरी को भी रिकंसिडर किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पहली असेम्बली है जहां कि अपने आप फैसला नहीं किया हमने। ये फैसला जब आपने पहली बार 2015 में बिल जो भेजा था बना कर के, वो फैसला एक्सपर्ट्स ने किया था। They have studied across the nation जहां जहां किस

प्रकार से व्यवस्था है उसको पहली असेम्बली है मैं साथियों का भी साथ चाहता हूं कि पहली असेम्बली है जहां कि स्पीकर महोदय ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ये अधययन किया, और कमेटी के अधययन के अनुसार ये बात है नहीं तो एमपीज/एमएलएज कहां किसी कमेटी का वेट करते हैं, अपना सदन है, अपने आप बढ़ाया, चुपचाप बैठ गए। तो ये बड़ा शुभ दिन है और Indian politics के अंदर paradigm shift है परमात्मा करे कि ऐसी राजनीति पूरे देश में फैले जहां ईमानदार एमएलएज आएं, ईमानदार एमपीज़ आएं और उसकी चिंता करें किस प्रकार से हमको अपनी जो जरूरतें हैं, जो जनता के लिए आफिसिस खोल रखे हैं कैसे मेनटेन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः एक सेकिंड, महेंद्र जी, उधर से राखी जी बैठी हैं, इधर आप बैठे हैं। वो भी हाथ...

...व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी, एक सेकिंड जरा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता-प्रतिपक्ष): हां जी, हां जी।

श्री महेंद्र गोयलः सर एक मिनट के लिए। इजाजत चाह रहा हूं आज पहली बार।

माननीय अध्यक्षः बोलिए।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस सेलेरी के बारे में विपक्ष के साथी भी और सत्ता पक्ष के साथी भी बहुत कम सेलेरी है इसके ऊपर बातचीत चल रही है। ये केंद्र सरकार के अंदर जब हमारा बिल गया था उसकी चर्चा बता देता हूं कैसे हुई थी। बोला दिल्ली के विधायकों की सेलेरी ज्यादा क्यूं बढ़ाएं, पूरे देश से कम करी जाए। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार लोगों को बिजली फ्री में दे रही है, विधायकों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री है, 400 यूनिट पर सब्सिडी है इसलिए इनकी सेलेरी कम की जाए। दिल्ली के विधायकों को भी पानी फ्री दिया जा रहा है, लोगों को पानी फ्री दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जब फ्री में चीजें दे रही है तो विधायकों के लिए भी फायदा हो रहा है। बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़त हैं। ये सरकार के फायदों को देख के सेलेरी कम की है अनिल बाजपेयी जी ज्यादा मतलब वो हत्तोसाहित होने की जरूरत नहीं, बिजली आपको भी फ्री मिल रही है। ये चर्चा थी वहां पर, ये आपकी सरकार की उपलब्धियां थी वहां पर। इसलिए पूरे देश के अंदर सबसे कम सेलेरी दिल्ली के विधायकों की थी। मुझे तो खुशी है इस बात की, मैं कह रहा हूं इससे भी कम कर दें क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी, बैठिए...

...व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः मतलब की बात पर आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी।

श्री महेंद्र गोयलः मतलब की बात पर आ रहा हूं। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बसों को फ्री कर रखा है इसलिए बोले भाई विधायकों की सेलेरी यहां पर कम होनी चाहिए। आपके हॉस्पिटलों के अंदर सारी की सारी दवाईयां फ्री मिल रही हैं, सारे लोगों...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी आपने एक मिनट का समय मांगा था। विषय से अलग जा रहे हैं हम।

श्री महेंद्र गोयलः सरकार की उपलब्धि है जी ये तो। सरकार की उपलब्धियों के कारण ये केंद्र सरकार ने ये सेलेरी कम की है। अरे आपके भी कर दो वहां पर बिजली फ्री, उनकी भी सेलेरी कम कर दो। दिल्ली के बराबर में ले के आओ न, पता लग जाएगा। दूसरे राज्यों की भी कम होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी अब बैठिए।

श्री महेंद्र गोयलः आपको ले के आना चाहिए ये प्रस्ताव बिधूड़ी जी।

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी। बैठिए प्लीज, हो गया। आपकी बात हो गयी, आ गयी समझ में, बैठिए। धन्यवाद।

...व्यवधान...

श्री महेंद्र गोयलः ठीक है जी। भई करी तो मैंने मतलब की बात है। जोकम करी है...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः महेंद्र जी अब बैठिए, प्लीज बैठिए।

श्री महेंद्र गोयलः सर इस पर बिल पर अमेंडमेंट करवा लो भई इस इस कारण से मतलब ये कम हो रही है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं इसीलिए समय नहीं दे रहा था। मुझे पता है कि विषय भटकेगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई इस विषय पर कोई सदस्य प्रस्ताव लाए न सदन में, क्यों नहीं ला रहे। बिधूड़ी जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बिधूड़ी जी। भावना जी, अब प्लीज, हो गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्षः आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ विधायक माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने इस सदन के विधायकों का जो दर्द है वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ सदन में रखा है। अन्य माननीय विधायकों को भी इस पर बोलने का आपने अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, विधायक का दर्जा दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री के बराबर है। जब हम पहली बार प्रथम विधान सभा के मेंबर बने उसमें आप भी मेंबर थे, जनाब शोएब इकबाल साहब भी मेंबर थे तो हमारी सेलेरी 1600 रूपया थी। दो तीन बातें स्पज़्ट हो जानी चाहियें, ये स्पज़्ट संदेश जाना चाहिए लोगों में कि इस सदन के मेंबर्स को सेलेरी 12 हजार रूपये प्रति माह मिल रही है, 2 लाख 10 हजार रूपये नहीं। ये स्पज़्ट संदेश जाना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदया के या राष्ट्रपति महोदय के अनुमति के बाद जो प्रस्ताव दिल्ली विधान सभा उनके पास भेजेगी, मंजूरी मिलने के बाद ये स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि विधायकों की सेलेरी 30 हजार रूपये होगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं विधायकों को जो आफिसिस दिए हुए हैं ये शुरूआत तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की, मैं तो उसके लिए बधाई देना चाहता हूं चाहे ये फैसला दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लिया हो, चाहे वो आपने लिया हो। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा और आपकी भी कमिटमेंट रही है कि बिजली का बिल जो है वो विधान सभा को पे करना चाहिए।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जो भी है। दूसरी बात मैं ये जरूर चाहूंगा कि डाटा आपरेटर्स की जो सेलेरी है वो 15 हजार रूपये है। न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा उनको। इसको कम से कम डबल किया जाए और संख्या भी डबल की जाए। तीसरी बात यदि आपको या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, इस सम्मानित सदन को यदि ठीक लगे, विधायकों को जो फैलो और असिस्टेंट फैलो जो मिले हुए हैं इसका चयन आप विधायकों के ऊपर छोड़ दीजिए न। वो

चयन करेंगे और जो सेलेरी सरकार दे रही है, वही सेलेरी दें। ये मेरा सुझाव है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अभी अन्य हमारे शायद माननीय विशेष रवि जी ने भी कहा है कि गाड़ी के लिए जब हम लोन, जो हमें गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर 11 परसेंट इंटरस्ट देना पड़ता है। 10 लाख रूपये तक तो जीरो परसेंट इंटरस्ट होना चाहिए। और मैं यह भी चाहूंगा आपके माध्यम से कि एनवायर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा में भी अध्यक्ष जी, चार्जिंग स्टेशन जल्दी से जल्दी हमें लगाना चाहिए। ये भी मेरा आपके सम्मुख सुझाव है। अब और कुछ ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि प्रस्ताव जो विधान सभा से भेजा जाएगा केंद्र सरकार के पास, या राष्ट्रपति जी के पास, उसको जल्दी से जल्दी मंजूरी मिले। सौरभ जी, जो कुछ आपने कहा है आपके आदेश का पालन होगा। आप चाहेंगे तो ज्वाईंट डेलिगेशन भी लेके चलना पड़ेगा तो आप लीड करें, हम आपके साथ चलेंगे। आप कहेंगे कि शायद यह संभव नहीं है, लोगों में गलत मैसेज चला जाएगा कि ये ए और बी टीम है, हमको 'ऐ' कहा जाएगा, आपको 'बी' कहा जाएगा, पहले कहते भी रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो अलग से भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं अपने भाजपा के ऑनरेबल एमएलएज़ के पास जरूर राष्ट्रपति जी के पास जाउंगा और जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। 2015 में जब विधायकों की सेलेरी बढ़ाने की बात मीडिया में बहुत बढ़चढ़ कर आ रही थी तो मैं इस हाउस का मेंबर नहीं था अध्यक्ष जी। लेकिन मुझे बहुत सारे मीडिया के लोगों ने पूछा कि इस पर आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा बिल्कुल विधायकों की सेलेरी बढ़नी ही चाहिए, 24 घंटे काम करते हैं और

अध्यक्ष जी ईमानदारी की बात तो यह है 12 हजार रूपये सेलेरी मिलती है इससे ज्यादा तो हमारे विधायक जो ब्याह-शादी में जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उन बेचारों का चला जाता है, जो सच्चाई है। तो विधायकों को आफिस भी हो उनके लिए, और मैंने तो एक बार जो मुझे जानकारी है महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे 1980 में, मैं उनके नाम की चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन उनके यहां तो यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि विधायक यदि अपनी कंस्टीट्यूएंसी में विजिट करने के लिए जाएगा तो उनके लिए सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी और एरिया के एसडीएम, एरिया के डीएसपी और अन्य अधिकारी उस आफिशियल विजिट में उनके साथ रहेंगे। तो ये व्यवस्था कहीं न कहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये जो प्रस्ताव विधान सभा सर्वसम्मति से पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजेगी, जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई जाएगी, जो सुझाव मैंने दिए हैं। दिल्ली सरकार जो कुछ और अन्य कदम उठा सकती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं इस पर भी सरकार जरूर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी इससे पहले उत्तर दें दो तथ्य मैं रखना चाहता हूं 1993 में पहली बार जब विधान सभा का गठन हुआ और 2011 तक 18 साल का पीरियड उसमें 5 बार सेलेरी बढ़ी है यानि लगभग हर साढे 3 साल में। और इस बार जो सेलेरी बढ़ी है इस से बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, 11 साल में बढ़ी है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी थोड़ा सा विषय रह गया, आप ही ने कहा था कि विधायकों को दो दो सिविल डिफेंस वालंटियर्स दिए जायेंगे

4-4, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। अब आपने कुछ बात कही हो इस हाउस के अंदर अब उसके ऊपर अमल न हो तो ये व्यवस्था भी जरूर हो जानी चाहिए दिल्ली सरकार के बड़े छोटे छोटे अधिकारी जो हैं न वो सिविल डिफेंस वालंटियर्स को लेके घूमते रहते हैं। विधायकों के लिए नहीं होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक बेचारे आफिस में इनको असिस्ट करें, ये व्यवस्था होनी चाहिए अध्यक्ष जी। ये आपका फैसला था, अगर आपका फैसला भी.. अगर ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर अमल नहीं कर रही है तो हम पूरी तरह से आपके फैसले के साथ खड़े हुए हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं पहले एक तो ये सदन को जानकारी देना चाह रहा था और मीडिया को ये बात समझनी चाहिए कि 11 साल बाद पहली बार सेलेरी बढ़ रही है दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है। दूसरी बात मैं सदन को विधायक नहीं बोल पाए उस चीज को मैं बोल रहा हूं कि जब कमेटी का गठन हुआ था 2015 में उसकी रिपोर्ट ये थी कि पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब आईएएस आफिसर्स की सेलेरी बढ़ती है तो विधायकों को क्यों अपनी सेलेरी मांगनी पड़ती है, सदन में बिल लाना पड़ता है। उसी पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों की सेलेरी बढ़े, ये पार्लियामेंट में तो लागू कर लिया उन्होंने लेकिन हमारे लिए नहीं। ये बड़ा अफसोस है और इसका मुझे दुख भी है इतना एक इंडिपेंडेंट रह कर कमेटी की रिपोर्ट गयी थी बहुत निष्पक्ष होकरके। अब मैं माननीय माननीय कैलाश गहलोत जी से प्रार्थना कर रहा हूं चर्चा का उत्तर दें।

माननीय विधि एवं न्यायमंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो एक काफी लंबे संघर्ष के बाद, काफी लंबे सफर के बाद आज फाइनली जो बिल्स असेम्बली में प्रजेंट हुए उन पर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से इस पल का इंतजार सभी माननीय सदस्यों को था, बहुत लंबे समय से तो उसकी मैं सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 2015 से लेकर 2022 हो गया, 2017 में अध्यक्ष जी जब मंत्री बना तो मुझे नहीं मालूम था कि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी तो कैबिनेटें करनी पड़ी, कितनी बार ये गवर्नमेंट आफ एनसीटी एक्ट जो है ये बार बार खोल के पढ़ना पड़ा।

क्योंकि जितनी बार भी हमारी तरफ से प्रपोजल गया माननीय एल.जी. के द्वारा केन्द्र सरकार को गया। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग ओब्जेक्शंस लग के आते। हम दोबारा एक्ट को देखते भई कहां चूक रह गई। लेकिन मेरे ख्याल से एज ए लॉ मिनिस्टर मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद 2015 में मेरे ख्याल से दिल्ली में माननीय सीएम अरविन्द केजरीवाल के नेतष्टत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और कितने हमारे साथी हैं, मेरे ख्याल से सभी का कोई राजनीति से कोई वास्ता तो था नहीं, अलग अलग प्रोफेशन से, वो सब छोड़ कर राजनीति में आए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई भावना जी जब मंत्री जी बोल रहे थे तो ये ठीक नहीं है।

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष: उचित नहीं है ये।

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री: और फिर जो प्रपोज किया गया था उस टाइम बेसिक सैलरी का, अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं सैलरी और जो अलांउसेस हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को ये भी बताना चाहूंगा कि सैलरी का कंपोनेट जो हम 12 हजार कहते हैं और जो दूसरे अलांउसेस है, चाहे वो कांस्टिट्वेंसी अलांउस है, सेक्रेटेरियट अलांउस है, टेलीफोन अलांउस है, कन्वेंस अलांउस है।

सैलरी का जो हमने प्रप्रोज किया था, उस टाइम 50 हजार रुपए थे। बाकी अन्य राज्यों ने दिल्ली की शुरूआत को देखते हुए अभी सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की उसपे मैं नहीं जा रहा क्योंकि सभी ने विस्तार में बता दिया। सौरभ जी ने बाहर जो, जो दूसरे नेशन्स हैं, कंट्रीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये बता दिया। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से कुछ भेद-भाव जरूर रहा कि और स्टेट्स के मुकाबले जो एक विधायक की जो सैलरी वहां पर तेलंगना के देख रहे हैं ढ़ाई लाख, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तरखंड हिमाचल मतलब सबकी जो है लाखों में है और दिल्ली में आज भी विधायक की सैलरी और हमने तो शुरू में कहा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं। तो वो उसका कहीं न कहीं दुःख है मन में कि एक बड़ा दिल, दरिया दिल दिखाके जो प्रप्रोजल 2015 में दिल्ली सरकार की तरफ से गया था। मेरे ख्याल से उसको केन्द्र सरकार को मान लेना चाहिए था और जो सौरभ जी ने बात कही टैलेंट की। आप एक कम्पनी में अच्छा सीईओ देखते हैं, उसकी भी सैलरी, उसके जो काम वो करता है, उसको देख कर करते हैं। मेरे ख्याल से ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एमएलए एक विधायक चौबीस घंटे काम करता है और मेरे ख्याल से आप जितना भी सोच सकते हैं, जिस भी तरह का काम सोच सकते हैं वो मेरे ख्याल से एमएलए आफिस से वो होता है।

मैं तो अध्यक्ष जी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। मेरी विधान सभा नजफगढ़ है। और मैंये, ये इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह के अन्य अन्य काम में विधायक इन्वोल्व होते हैं। विधायक बने बने थे फोन आया, गांव से फोन था बिल्कुल ठेठ, मैंने कहा जी बताइये क्या प्रोब्लम। बोला जी कुएं में भैंस गिर गयी तो मैंने कहा जी उसमें हम क्या करेंगे। बोला जी आप निकलवाओ। अब मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि हम कैसे निकालेंगे वो तो गांव वाले, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है और वो तो कर लेंगे। बोला जी हमें नहीं पता आप निकलवाओगे। अब जब मैंने कहा ठीक है जी देखते हैं। मैं वाकई मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आफिस में बात की जो बड़े बजुर्ग थे उनसे बात की। बोला बेटा ऐसा नहीं होगा ये, ये काम फायर डिपार्टमेंट करेगा। पुराने जो कुंए हैं जो यूज में नहीं थे, उसमें जब खेत में गयी भैंस तो वो गिर गई। बोला बेटा ये ऐसे नहीं होगा, फायर डिपार्टमेंट वालों को बुलाओ। वो रस्सा डालके और उसको निकालेंगे। अब उस चीज से लेके और एक पूरी विधान सभा की मैं समझता हूं किसी भी विधान सभा में जो बड़ी विधान सभा हैं, उसमें ढ़ाई-तीन लाख वोटर्स हैं तो एक एमएलए जो है एक विधायक जो है वो दो-ढ़ाई लाख लोगों का रिप्रजेंटेशन करता है। उनकी जो अलग अलग प्रोब्लम्स हैं, उनको सही फोरम पर, सही डिपार्टमेंट में और जब सैलरी की बात करें तो 12 हजार रुपए। केन्द्र सरकार ने उसको बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं वो 30 हजार रुपए भी कुछ नहीं है आज के दिन में, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और अगर जनता ये चाहती है कि उसका विधायक, उसका चुना हुआ व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करे, अगर लगन से काम करे तो

जो मेरे ख्याल से बिधूड़ी जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि जैसे जैसे पे कमिशन के टाइम बेसिक सैलरी है, वो बढ़ती है तो ये कोई मेरे ख्याल से हरेक विधायक का अधिकार है। इस सदन के जितने भी सदस्य हैं, उनका अधिकार है, कोई मांगने या रिक्वेस्ट करने की कोई बात नहीं है। उनका भी उसी हिसाब से जो बेसिक सैलरी वाला जो कंपोनेंट है, वो बढ़ते रहना चाहिए।

जो माननीय सदस्यों ने बात की डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की, मैं बिल्कुल उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं क्योंकि पहले कुछ साल पहले जो काम जिस प्रकार से विधायक के आफिस में हुआ करता था और आज जिस प्रकार से तमाम् दिल्ली सरकार की जो सर्विस हैं, वो सारी ऑन लाइन और फैसलेस कर दी गयी। हरेक व्यक्ति को एक अच्छे स्किल डेटा एंट्री ऑपरेटर की विधायक को बहुत जरूरत है। कई सौ लोग जो है वो विधायक आफिस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, वो सारी एप्लिकेशन्स ऑन लाइन भरी जा रही हैं। बहुत सी सर्विसेस जो हैं, जिसमें जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सर्विसेज है वहां किसी भी व्यक्ति को जाने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन पूरा जो प्रोसेस है वो फैसलेस है, वो सारा कंप्यूटर के द्वारा, लैप टॉप के द्वारा, मोबाईल के द्वारा वो किया जाता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो डिमांड है मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं और मैं अंत में चूंकि 2015 से लेकर लगातार केन्द्र सरकार और अन्य जो डिपार्टमेंट से फॉलो-अप किया। लॉ सेक्रेट्री यहां पर हैं, उनकी भी, उनको भी बधाई देता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। शायद एडिश्नल सेक्रेट्री बैठी है, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं क्योंकि जब जब एमएलऐज से और माननीय सीएम और माननीय डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग होती कि भई अब क्या हो रहा है तो हम वापस फिर पूरे लॉ डिपार्टमेंट को बोलते और वो आगे

फॉलो–अप करते और सभी उन अधिकारियों का, जिन्होंने इस पूरे लंबे सफर में साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अंत में फिर दोबारा एक बार सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय वित्त मंत्री जी, श्री मनीष सिसोदिया जी।

माननीय वित्त मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा में शामिल करने के लिए मुझे अवसर दिया और अवसर देते हुए एक शब्द जानबुझ कर यूज किया उप–मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या अन्य की जगह वित्त मंत्री।

मैं मूल रुप से ये शायद पहला मौका होगा देश की राजनीति में मुझे बहुत पैसा उसमें नहीं कह रहा हूं लेकिन विधायकों की सैलरी बिल पर दिल्ली विधान सभा में या किसी भी विधान सभा में या सदन में हो सकता है संसद में भी इतनी चर्चा हो रही हो वरना तो ये बिल आते हैं और पास हो जाते हैं और अगले दिन अखबारों में छपते हैं।

अच्छी बात है कि इसपे चर्चा हो रही है। अब सात साल लगा है तो थोड़ी चर्चा भी ठीक ही है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहावत हमारे यहां चलती है। हिन्दी में हम सब लोगों ने सुनी होगी, उससे शुरू करना चाहता हूं। कहावत है किः

उतने पैर पसारिए, जितनी लम्बी सौर।

तेते पांव पसारिए जैती लंबी सौर।

मतलब उतने ही पैर फैलाइये जितनी लंबी चादर। मैं हमेशा से इस कहावत का विरोधी रहा हूं। बहुत क्रिटिकल व्यू प्वाइंट रहा है मेरा इस कहावत को लेकर। ये कहावत कहीं न कहीं जिन लोगों ने भी बनाई ठीक है अभाव के उसमें और उस समय किसी और संदर्भ में बनाई पर इस कहावत ने बड़ा डैमेज किया। मुझे लगता है कि आदमी है, आदमी को ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि उतने पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर बल्कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादे की चादर ले लो। अब अगर आपकी लंबाई पांच फीट, साढ़े पांच फीट, मान लिजिए चलो छः फीट है। अगर किसी आदमी की लंबाई छः फीट है और उसको बोलो भाई पांच फीट लंबी चादर है और अब पांच फीट लंबे पैर फैलाओ तो पैर तो फैलने वाले नहीं हैं या तो सर उघड़ा रहेगा या पैर उघड़े रहेंगे और मच्छर काटेंगे और सर्दी भी लगेगी। मतलब चादर का होना न होना तो बेकार है फिर तो ये जो भाव, जिसने ये कहावत बनाई किसी अच्छे संदर्भ में बनाई होगी और किसी एक अच्छे संदर्भ के अभाव में समझाया गया होगा लेकिन मानव जाति के लिए सबसे बड़ी खतरनाक कहावत है ये। मैं ऐसा मानता रहा हूं क्योंकि छः फीट के आदमी को कभी भी पांच फीट की चादर से संतोष नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे पास में सात फीट की चादर आनी चाहिए। आधा फीट नीचे दबाने, सर के नीचे दबाने के लिए भी हो और आधा फीट पैरों के नीचे दबाने के

लिए और तब अच्छी नींद आएगी। कभी भी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए भई छः फीट का आदमी पांच फीट की चादर से काम चला ले। छः फीट के आदमी को सिद्धान्ततः एक मानवीय जीवन जीने के लिए सात फीट की चादर चाहिए। ये मानवीय जरूरत है। अब होता क्या है कि तेते पैर फैलाइये

के चक्कर में लोग कहते हैं कि तीन फीट की चादर में भी काम चला लो। एक फीट की में भी चला लो, पांच फीट की में भी चला लो, उसमें चलता नहीं। इवन छः फीट की में भी नहीं चलता। अच्छा उसका एक पक्ष ये है।

दूसरा पक्ष ये है कि भई चादर ही चादर इक्ट्ठे कर लो, पूरा थान इक्ट्ठा कर लो। छः फीट के आदमी के लिए 12 फीट की चादर इक्ट्ठा कर लो, 20 फीट की कर लो तो मैं उसमें भी खामी ढूढ़ता हूं/देखता हूं। छः फीट, छः फीट की चादर, छः फीट के आदमी पर, पांच फीट की चादर में भी ठीक से नहीं सो सकता और छः फीट का आदमी अगर सात फीट की चादर ले ले तो आधा फीट इधर दबाए और आधा फीट पैरों के नीचे दबाएं, शान से सोएगा, चैन से सोएगा और छः फीट के आदमी को अगर आप 10 फीट की चादर दे दो तो दुखी रहेगा, रात भर उसी पर उलझा रहेगा, उसी को समेटता रहेगा

तो पैसे के मामले में भी मैं ऐसा ही मानता हूँ चादर पर तो हो सकता है वो कहावत ठीक हो, सिकोड़-विकोड़ के सो जाये आदमी लेकिन पैसा कितना हो आदमी के पास, कैसे इकट्ठा किया जाये, कितना पैसा सैलरी में वेतन में प्रोफिट जो बिजनेस करते हैं उसमें प्रोफिट कहां हो, मुझे लगता उतना प्रोफिट कमाओ उतनी सैलरी लो जितनी जरूरत है और जरूरत से थोड़ी सी ज्यादा लो वो बहुत जरूरी है इसीलिये मैंने कहा, उदाहरण दिया कि 6 फीट के आदमी को थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा 6 फीट का आदमी है 7 फीट दे दो, 7 फीट से नीचे रहेगी वो चैन से नहीं सो सकता और 7 फीट 6 फीट वाले आदमी को 12 फीट की दे दो जिन्दगी भर दुःखी रहेगा और सबको दुःखी करेगा,

रातभर वो गले में उलझी रहेगी वो चादर कभी पैरों में उलझेगी, कोई चोर न काट ले जाये ये भी झंझट है तो इसलिये इस संदर्भ को मैंने रखा है। 7 साल पहले जब हम सब लोगों ने इस सदन में हममें से अधिकतर लोगों ने इस सदन में बैठकर काम करना शुरू किया तो इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया गया है कि यार ये विधायक की सैलरी 12 हज़ार रुपये थोड़ा सा मज़ाक सा लगता है मतलब दिल्ली में विधायक की सैलरी 12 हज़ार रुपये होगी उसको लेकर एक कमेटी बनी, विशेष रवि जी की अध्यक्षता में जिनको आपने सबसे पहले बोलने का मौका दिया उस कमेटी ने बहुत सारे देशभर के विधायकों की internationally, politicians, elected representatives, क्या trends हैं क्या जरूरतें हैं बहुत सारे फैक्टर्स को मंहगाई का इन्डैक्स कैसे आगे बढ़ रहा है आपने भी जिक्र किया 1993 से लेकर और 2011 तक 7 बार बढ़ी।

माननीय अध्यक्षः 5 बार।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः 5 बार, 5 बार बढ़ी तो इन सब सारे पहलुओं को लेते हुये अपनी रिपोर्ट दी और उसमें एक सुझाव दिया और मैं विशेष रवि जी की समिति को बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिये कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी एक्चुअली वो 6 फिट और 7 फिट वाले फार्मूले पर ही दी इन्होंने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि नहीं जी अब तो बस विधायकों की सैलरी बढ़नी है तो 6 फीट के आदमी को 20 फीट की चादर वाली रिपोर्ट दे दो बिल्कुल नहीं दी इन्होंने और इन्होंने ये भी नहीं माना भई 6 फीट का आदमी 5 फीट में काम चलाये ये इन्होंने बहुत बैलेंस एक रिपोर्ट दी वो इसके लिये साधुवाद के पात्र हैं लेकिन अब ये संयोग कहिये दुर्योग कहिये कि पिछले 7

साल से ये कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में भी दो-तीन बार आ गई, कैबिनेट में चली गई एल.जी. साहब के पास केन्द्र सरकार के पास तो काफी जव दंक तिव हुआ, ठीक है। जब ये पहली बार 2015 में यहां से पास हुई इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो प्रपोज़ल ये प्रपोज़ल जो हम आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं 2015 में पहली बार पास हुआ तो उसमें इनका प्रपोज़ल था शायद 50 हज़ार का 12 हज़ार रुपये की सैलरी को 50 हज़ार रुपये कर करने का। अब अगले दिन अखबारों में क्योंकि अब ये अच्छी बात है पॉलिटिक्स की कि वो एकदम media scrutiny, public scrutiny, public critic में खूब रहते हैं हम और वो जरूरत भी है politicians के लिए तो अगले दिन बहुत critical headline छपी। दिल्ली में विधानसभा के विधायकों ने अपना वेतन चार गुना बढ़ाया 400 percent hike. अब ऐसे देखो तो मैं भी अगर आम आदमी के रूप में एक पत्रकार के रूप में देखूं तो बड़ा खराब लगेगा यार मैं इनको टैक्स दिये जा रहा हूँ और ये अपना आराम से इनके पास अधिकार है बैठकर चार गुना वेतन बढ़ा लिया तो हमारे एक पत्रकार मित्र ने मेरे साथ पुराना पत्रकारिता के दौर का उनसे संबंध था उन्होंने अपने एक चैनल पर खूब पांच मिनट इस पर प्रवचन दिया। देखो ये विधायक, देखो ये विधायक अपने आप चार बताये फिगर नहीं बताई चार गुना सैलरी कर ली, चार सौ गुना सैलरी कर ली। ये क्या होना चाहिये इस पर सर्वे होना चाहिये, अच्छी बात है एक बार वो मुझे मिल गई थोड़े दिन बाद कहीं, मैंने उनसे पूछा आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी लेकिन ये तो बताओ कि आपको ये पता है कि सैलरी बढ़ी कितने से कितनी, बोलीं चार सौ परसेंट बढ़ी तो मैंने कहा चार सौ परसेंट तो बढ़ी चार गुना तो बढ़ी पर कितने से कितनी बढ़ी तो चुप उनको शायद आइडिया नहीं था मैंने कहा 12

हज़ार रुपये से 50 हज़ार रुपये का प्रपोज़ल दिया है अभी तो एल.जी. के यहां जायेगी फिर सैन्ट्रल गवर्नमेंट में जायेगी, बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी ये भी नहीं पता पर बढ़ाई भी 12 हज़ार से, कुल मिलाकर 12 हज़ार रुपये सैलरी है 50 हज़ार बढ़ाई है ये तो मुझे भी नहीं पता था ये उनका वर्जन था तो ये कई बार अनभिज्ञता में ये चीज़ होती है तो आज 12 हज़ार रुपये से जो पहले 50 हज़ार रुपये बढ़ाई गई थी उसी सैलरी को 12 हज़ार रुपये से 30 हज़ार रुपये का अब एक नया प्रस्ताव पास हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस बार वो क्योंकि उन्होंने ही 30 हज़ार मान लिया है तो उम्मीद है कि अब उसकी consent हमको मिल जायेगी। कई साथियों ने कहा कम है, ज्यादा है मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता पर मुझे लगता है कि अभी के संदर्भ में ये एक अच्छी बढ़ोतरी है। सौरभ भाई जिक्र कर रहे थे कई और साथियों ने जिक्र किया कि टैलेंट के लिये बहुत जरूरी है। दुनियाभर में चाहें वो प्राइवेट संस्थान हों या गवर्नमेंट संस्थान हों उसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके लोगों को तनख्वाह कितनी कम या ज्यादा मिल रही है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी संस्था में कितने टैलेंटिड लोग बैठे हुये हैं decision making में या execution position पर। किसी भी प्राइवेट कम्पनी की, बड़ी-बड़ी प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ की, सरकारों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कितने टैलेंटिड लोग बैठे हुये हैं और वहां काम करने के लिये कितने टैलेंटिड लोग कम्पनी से या सरकार से बाहर होकर लालायित हैं, इच्छा है उनकी उनका सपना है वहां काम करना। आज Indian Bureaucracy के बारे में हम बात करते हैं कहीं ना कहीं Indian Bureaucracy में आने का सपना Indian Army में आने का सपना, एक बड़ा सपना इसलिये है जबकि

वहां मतलब एक बड़ी चीज़ ये है और सफल मॉडल हैं ये क्योंकि वहां आने के लिये लोग लालायित हैं। इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में सबसे बढ़िया कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के-लड़की भी सोच रहा होगा मेरा मौका मिले तो मैं आई.ए.एस. बनूं, लालायित हैं लोग वहां आने के लिये तो हमेशा किसी भी संस्था को आज बड़े-बड़े Engineering Colleges, Management Colleges में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियां उनकी ड्रिम कम्पनियां तय करके रखते हैं मुझे वर्ल्ड की इन चार-पांच कम्पनियों में काम करना है तो संस्थान की सफलता उसके टैलेंट पर निर्भर है और world over ये देखने में आ रहा है कि टैलेंट को अट्रेक्ट करने के लिये पैसा तो देने की जरूरत है अब क्योंकि हम corporate world में तो हैं नहीं, हम राजनीति में हैं और राजनीति समाज सेवा का काम है। राजनीति में कहीं भी हम इस बात को कम्पटिशन में नहीं ला सकते साहब, सौरभ भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या ये म्युज़िक टीचर थे या और सब लोग अलग-अलग-अलग-अलग काम करते थे वकील थे कि जो एक वकील रहकर कमा सकते हैं वो राजनीतिक रहकर तो नहीं कमा सकते इसमें कोई competition नहीं है। इसमें कोई competition नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुये वो हो सकता है 20 लाख रुपये महीने सैलरी पर होते आज इतने सीनियर हो गये होते, टैलेंट है इनमें लेकिन इस बात से कोई competition नहीं होना चाहिये जी आज ये लड़का तो 20 लाख रुपये कमा रहा होता प्राइवेट कम्पनी में काम कर रहा होता यहां तो अभी नहीं है इतना, नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिये। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारी इस सदन के लोगों की सैलरी टैलेंट के हिसाब से कि इनका मार्केट वैल्यू कितनी है उस पर आये अगर मार्केट वैल्यू पर लेना है तो मार्केट में ही काम कर

लो भई यहां आने की जरूरत नहीं है लेकिन समाज सेवा के point of view से बिल्कुल वो ही फिर से 6 फीट 1 फीट वाला कि भई 1 फीट में भी काम नहीं चलेगा कम से कम 7 फीट तो दो 6 फीट के लिये तो वो जरूरी है आज और उस हिसाब से ये सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। अमेरिका जैसे देश, यूरोप जैसे देश इनको आप अध्ययन करें गौर से इन लोगों ने एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाल रखा है अपने यहां। इनकी सरकारों में दुनिया का सबसे शार्प टैलेंट जा रहा है, कैसे जा रहा है अब इन्होंने बढ़िया-बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं जैसे हमारे यहां IIT, IIM बना है हमारे यहां भी बहुत शानदार institutions हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत शानदार और देशभर की कई यूनिवर्सिटीज़ के इतने शानदार कॉलेजिज़ हैं लेकिन हमारे यहां का वो पढ़ने वाला टैलेंट संतहमसल कहां जा रहा है जो टॉप टैलेंट है वो अमेरिका, यूरोप की किसी कम्पनी में जाकर नौकरी कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं इन्होंने बड़ी शानदार-शानदार यूनिवर्सिटीज़ बनाई Howard, Preston, Oxford, Cambridge, और दुनियाभर के नाम ले लो और उन यूनिवर्सिटीज़ में वो दुनिया के सबसे टैलेंटिड बच्चों को उसमें से pool में से उठाकर लाते हैं। इण्डिया के खूब सारे टैलेंटिड बच्चे आज Cambridge जा रहे हैं, Oxford जा रहे हैं, Howard जा रहे हैं, MIT जा रहे हैं। बांग्लादेश के भी जा रहे हैं, नेपाल के भी जा रहे हैं, चाईना के भी जा रहे हैं, सिंगापौर के भी जा रहे हैं सबसे टैलेंट पूल को उठाकर अपने यहां लेकर आते हैं फिर उनको दो-तीन साल पढ़ाई कराते हैं फिर दो-तीन साल पढ़ाई मान लो इस समय 10 हज़ार बच्चे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटिस में पढ़ रहे हैं दुनिया के सबसे टैलेंटिड बच्चों में से कुछ बच्चों को उठाकर ले जाते हैं उसके बाद

उनको खूब तीन–चार साल पढ़ाते हैं अच्छे से और फिर देखते हैं कि ये talented lot में से जो इमेज talented हम दुनिया से उठाकर लाये थे इसमें चार साल की पढ़ाई के बाद सबसे टैलेंटिड कौन निकल कर आ रहा है उसको उठाकर के अपनी सरकार में ले जाते हैं, उसको उठाकर के अपने research wing में ले जाते हैं, उसको उठाकर अपने water wing में ले जाते हैं तो दुनिया की बहुत सारी सरकारों ने अपने यहां talent attract करने का एक मॉडल क्रिएट कर रखा है। मुझे लगता है हमें भी इस पर किसी भी hypocrisy का शिकार हुये बिना किसी की पूर्व धारणाओं और अपनी मान्यताओं का शिकार हुये बिना इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि भारत में भी जिस तरह से राजनीति में हमने bureaucracy में हमने टैलेंट को hunt करने के तरीके बनाये हैं वैसे ही राजनीति में भी एक टैलेंट को प्रमोट करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये तरीके बनाने चाहियें और उसमें सैलरी उसमें मिलने वाला वेतन एक important factor है। मैं ये नहीं कह रहा फिर से की उतना competitive हो जाये जितना corporate world है बिल्कुल नहीं होना चाहिये और कतई होना भी नहीं चाहिये in principle मैं अगेंस्ट हूँ लेकिन इतना तो हो। अब किसी आदमी को आप बोलो भई तुम्हारे अन्दर सॉफ्टवेयर या हैल्थ के इश्यूज़ को या एजुकेशन के इश्यूज़ को या इन्डस्ट्रीज़ के इश्यूज़ को समझने की बड़ी शानदार क्षमता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हो आओ राजनीति में आओ एम.एल.ए बनकर काम करो। अब वो बोलें जी क्या मिलता है of course power है of course बहुत कुछ करने की वो है उसकी कोई तुलना वहां किसी सॉफ्टवेयर कम्पनी के एग्ज़क्यूटिव से नहीं की जा सकती है वहां उसको कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर बनाने की पॉवर है यहां बैठकर बहुत सारे काम करने की

पॉवर है उस पॉवर को इन्जॉय करने के लिये आओ लेकिन तनख्वाह क्या मिलेगी अगर वो पूछे बोलें जी 12 हज़ार रुपये मिलेगी तो यार 12 हज़ार रुपये में तो एक आदमी केवल इसलिये छोड़ देगा यार मुझे तो नहीं आना फिर और क्या मिलेगा तो बोले जी अभी मौजूदा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ proposed भी बहुत मतलब और ऐसा है। 12 हज़ार के अलावा और क्या मिलेगा, कि जी अपनी विधान सभा होगी एम.एल.ए. चुने गये एम.एल.ए. चुने गये तो वहां कुछ खर्चे–पानी होंगे कोई आपके यहां आयेगा उसको चाय–पानी पिलाओगे किसी के यहां जाओगे कुछ–कुछ जो आपने अभी जिक्र किया बिधुड़ी जी ने भी उसके लिये कितने पैसे मिलेंगे, उसके लिये 18 हज़ार रुपये मिलेंगे जी बस मतलब सारे विधान सभा में जितना भी खर्चा–पानी एक विधायक को महीने में करना है उसके लिये 18 हज़ार रुपये, ये कहते हैं अलाउन्स, उसके अलावा कि जी विधान सभा में घुमोगे गाड़ी में जाओगे लम्बी–लम्बी विधान सभायें हैं 10–15–20 किलोमीटर तो सबका क्षेत्र है। उस विधान सभा में आने–जाने के लिये 6 हज़ार रुपये मिलेंगे। टेलिफोन आज की तारीख में सबकुछ डेटा पर है सबकुछ वाट्सएप पर है सोशल मिडिया पर चल रहा है चार और दो भी बच्चे और होते हैं साथ में काम करने वाले उनके भी टेलिफोन हैं कुल मिलाकर क्या मिलेगा, टेलिफोन के लिये 8 हज़ार रुपये मिलेंगे तो 12 हज़ार रुपये की तनख्वाह 18 हज़ार रुपये का विधान सभा के सारे खर्चे विधान सभा से संबंधित होने वाले 6 हज़ार रुपये का कन्वेन्स 8 हज़ार रुपये का टेलिफोन तो इन सबको मिलाकर जो 50–54 हज़ार रुपये और एक secretarial allowance दस हज़ार रुपये का ना ये कुछ है ये भी मिलता है तो 54 हज़ार रुपये सारे मिलते हैं 53–54 हज़ार रुपये साढ़े 53 हज़ार रूपये, हाँ 1 हज़ार मेडिकल के तो 53 हज़ार रुपये

मिलते हैं 54 हज़ार रुपये, साढ़े 53 हैं न एग्ज़ेक्टली तो अब इसको बढ़ाकर 12 हज़ार रुपये को 30 हज़ार रुपये किया जा रहा है तो सैलरी एम.एल.ए. की बढ़ रही है constituency allowance 18 हज़ार से 25 किया जा रहा है, conveyance 6 हज़ार से 10 हज़ार किया जा रहा है, टेलिफोन 8 हज़ार से 10 हज़ार किया जा रहा है जो secretarial allowance मिलता है वो 10 से 15 किया जा रहा है।

तो कुल मिलाकर फिर 54000 का सारा अलाउंस मिलाकर और अगर मूलरूप से सेलरी देखें तो 12000 तो 12000 की मूल सेलरी को 30000 रुपये किया जा रहा है। टोटल अलाउंस सारा मिलाकर जो 54000 रुपये मिलते हैं उसको 90000 रुपये किया जा रहा है तो ये प्रपोजल इस सदन के सामने है तो मैं समझता हूं कि आज की महंगाई और आज की जरूरतें और वही जो मैंने बात कही की थोड़ा सा इससे हम सब ये इतना नहीं है कि हमारी जरूरतों, इच्छाओं और इन सबके मुकाबले 10 गुना, 20 गुना चीज हो जाए पर मैं हम सब जिस भाव से यहां आए हैं और जिन परिस्थितियों में हैं इस बात को मानते हुए कि ये पैसा किसी कारपोरेट की कमाई के प्रोफिट से नहीं आ रहा है बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहा है तो टैक्स पेयर्स को धन्यवाद करते हुए एक-एक वोटर को एक-एक करदाता को धन्यवाद करते हुए हमें लगता है हम इसको स्वीकार करें और धन्यवाद करते हुए स्वीकार करें एक-एक व्यक्ति का जो इस टैक्स को दे रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हमको जिससे सेलरी मिल रही है हमें इस वक्त उसको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है की उनके दिये गये पैसे में से ये सदन अब सेलरी को बढ़ा रहा है और महंगाई और जरूरतें और इन सबको देखते हुए ये वृद्धि की जा रही है मैं इससे सहमत हूं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अब विधेयक पर खण्डवार विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–07) पर खण्डवार विचार होगा। प्रश्न है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4 विधेयक का अंग बन गये ।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

प्रस्ताव पारित हुआ।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना-

अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुर:स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022 (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-07) को पारित किया जाए, माननीय मंत्री जी।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुर:स्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-07) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–08) पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–6 विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयकका अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

अब विधेयक को पारित करना-

अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-08) को पारित किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों का (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-08) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

विधेयक पर खण्डवार विचार

अब 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-09)पर खण्डवार विचार होगा।

-प्रश्न है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 विधेयक का अंग बन गये ।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयकका अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-09) को पारित किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में मुख्य सचेतक के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-09) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाधयक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–10) पर खण्डवार विचार होगा।

–प्रश्न है कि खण्ड–2 और खण्ड–3 विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 और खण्ड–3 विधेयक का अंग बन गये ।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना

माननीय अध्यक्षः अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-10) को पारित किया जाए।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-10) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता–प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या–11) पर खण्डवार विचार होगा।

–प्रश्न है कि खण्ड–2 और खण्ड–3 विधेयक का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँपक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 और खण्ड–3 विधेयक का अंग बन गये।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयकका अंग बनें–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गये।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री कैलाश गहलोत, माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) '(संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-11)को पारित किया जाये।

माननीय विधि, न्याय एवं विधायी कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 04 जुलाई, 2022 को सदन में पुरःस्थापित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में नेता-प्रतिपक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022' (वर्ष 2022 का विधेयक संख्या-11)को पारित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

विधेयक पास हुआ।

माननीय सदस्यों का धन्यवाद एक घंटे के लिए ठीक 3 बजे तक लंच ब्रेक। लंच माननीय सदस्यों से प्रार्थना है बाईं ओर लंच की व्यवस्था की गई है नया एक लंच के लिए नई व्यवस्था सभागार बन गया है उसका भी आज उद्घाटन हो जाए।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 3.08 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

माननीय अध्यक्षः ध्यानाकर्षण नियम-54।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः अध्यक्ष जी, एक न सेलरी से संबंधित एक मिनट के लिए...

माननीय अध्यक्षः किसके लिए।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सेलरी वाले में ही भारत सरकार की जो रिसर्च एजेंसी है बुक्स पढ़ाती है लोगों को मतलब पूरे भारत में जिसके authenticity को माना जाता है एक पैमाना माना जाता है उसमें भी दिल्ली के विधायकों की जो सेलरी है वो 210000/-रुपया लिखा गया है भारत सरकार की एजेंसी के द्वारा। तो यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैटर को breach of privilege मानकर के प्रिविलेज कमेटी में भेजने का कज़्ट करें ताकी ऐसे मामलों को रोका जा सके और एक नजीर बन पाए मेरा यह निवेदन था और भी सदस्य इस पर कहना चाहेंगे जरूर सुनें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः विद प्रूफ एक बार राइटिंग में मुझे दे दीजिए प्रिविलेज को भेज देंगे इसे। श्री ऋतुराज गोविंदजी। माननीय सदस्य आगामी मानसून के मौसम की अपनी तैयारियों में दिल्ली नगर निगम के लापरवाही पूर्ण एवं गैर जिम्मेदाराना रवैये के संबंध में माननीय उप-मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री ऋतुराज गोविंदः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया। हम सभी जानते हैं कि बरसात दिल्ली में दस्तक दे चुकी है और पिछले साल तो यह स्थिति थी अध्यक्ष महोदय कि 133 साल का रिकार्ड दिल्ली के अंदर में मानसून ने तोड़ा था और जिसकी वजह से शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति नहीं हुई थी। बहुत सारी कमेटीज की मीटिंग हम लोगों ने ली, बहुत तरह के दौरे किये उम्मीद यह थी कि इस बार जो स्थिति हुई है आने वाले मानसून में स्थिति बेहतर होगी उसमें से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के हम लोग कमिशनर को भी बुलाते थे, अधिकारियों को भी बुलाते थे जगह-जगह दौरे भी किये लेकिन इस बार भी ढ़ाक के तीन पात जैसी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर जितनी भी सड़कें जो 60 फुट से छोटी है वहां पर में ड्रेन का काम यानी नालियों की सफाई का काम उसको मेनटेन करने का काम, सड़क बनाने का काम वो करती है और 60 फुट से जो बड़ी सड़कें होती हैं वो पीडब्लूडी करती है ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन यानी कि हमारे संविधान के three tier governance system के अंदर में हमारे संविधान निर्माता जब हमारी संविधान सभा बैठी थी तो इस बात पर चर्चा करते थे कि distribution of power कैसे हो तो उस समय में राष्ट्र

पिता गांधी कहते थे कि जो पावर का distribution है वो पिरामिड सिस्टम में होना चाहिए पिरामिड का मतलब ऐसे होता है a centre should have less power and जो third stage यानि कि जो सबसे निचली सरकार है यानि कि पंचायत और जो लोकल बॉडी है should have maximum power इसका मतलब है कि जनतंत्र की मूल भावना में जनता के सबसे नजदीक जो सरकार होती है वो लोकल बॉडी होती है पंचायत होती है या लोकल बॉडी होती है क्यों होती है क्योंकि day to day life में हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले जनता किसी खिड़की को खटखटाती है तो वो तीसरी सरकार होती है जो जनता के सबसे नजदीक होती है लेकिन आज हो क्या रहा है। आज दिल्ली के अंदर यह पावर लड़ाई के अंदर जो सेंटर जिसको ध्यान देना चाहिए कि external affairs कैसी होनी चाहिए जिसको ध्यान होना चाहिए कि भइया चाइना हमारे देश के अंदर में जमीन कब्जा रहा है, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी कम्यूनिकेशन की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार कैसी मिलनी चाहिए उनका इंट्रस्ट दिल्ली के म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में है यानी कि आपकी गली में नाली साफ हुई की नहीं हुई इसका इंट्रेस्ट सेंटर का है। आप मुझे एक चीज बताइये कि जनतंत्र के अंदर जहां पर जनता अपने चुने हुए नुमाइंदे को चुनती है उससे काम कराने की उम्मीद रखती है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है आप सोचिये अगर उसका चुनाव ही नहीं होगा उसके लिए नगर निगम का चुनाव ही नहीं होगा तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि कैसे जाएगा ऊपर से लोग अमेंडमेंट करके बना है कि कोई स्पेशल आफिसर होगा। स्पेशल आफिसर देखेगा कि जो मानसून को लेकर के क्या तैयारियां हो

रही हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय की मानसून को लेकर के नगर निगम की यह तैयारियां हैं ये किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की यह तस्वीर है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें किराड़ी क्षेत्र के अंदर में 60 फुट से ऊपर केवल एक सड़क है उसको बोलते हैं 70 फुटा रोड और वो पीडब्लूडी की है जिसको पीडब्लूडी मेनटेन करती है। इसके अलावा जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वो सब एमसीडी की हैं। एमसीडी में जो 4 फुट से जो छोटी नालियां होती हैं उसको जो है सो 4 फुट से जो बड़ी नालियां होती हैं उसको एमसीडी की वर्क्स डिपार्टमेंट करती है और 4 फुट से जो छोटी नालियां होती हैं उसको डेम्स डिपार्टमेंट करती है। आप अगर फोन करेंगे कि भइया मुबारकपुर रोड का नाला साफ क्यों नहीं हुआ तो बोलेंगे जी हमें वर्क्स वाला बोलेगा डेम्स का काम है डेम्स वाला कहेगा वर्क्स का काम है करता कोई नहीं है। इसी तरीके से कहेंगे की बाबा विद्यापति मार्ग की यह तस्वीर है, यह मुबारकपुर रोड की तस्वीर है, यह 40 फुटा रोड की तस्वीर है ये सारी सड़कें एमसीडी की सड़क हैं एमसीडी वाले 7 साल से इसको मेनटेन नहीं कर रहे। लोगों को तकलीफ हुई तो हमने एमएलए फंड से ड्रेन बना दिया अब विधायक अपने एमएलए फंड से नाला बना सकता है पर नाले की सफाई कौन करेगा सफाई तो एमसीडी करेगी न। अब एमसीडी अगर कहे कि यह 4 फुट से गहरा नाला है यह 4 फुट से छोटा नाला है अरे चाहे गहरा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो साफ तो एमसीडी को करना है। हम लोग विधायक दल सब Lieutenant Governor से मिलने गये एलजी साहब के यहां मिले। एलजी साहब को हमने बोला कि देखिये दिल्ली के अंदर भी दिल्ली देश की राजधानी है यहां के लोगों को भी उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हो उसके

लिए आप जो है सो पहले पुलिस के अंदर थाने में थाना लेवल कमेटी होती थी आपने भंग कर दिया जिसके चलते आज किसी भी आदमी को किसी भी तरह की प्राब्लम होती है हम उसकी पुलिसिया मदद नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से अभी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अंदर में कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है उसको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। आप यह सुनिश्चित करिये की आने वाली जो बारिश है उसके अंदर मानसून के अंदर में जो नालियों की सफाई है जो म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अंडर में आती है उसकी सफाई अच्छे से हो सके ताकी फ्लड जैसी सिचुएशन लास्ट इयर की तरह न हो। Lieutenant Governor ने एश्योर किया आप चिंता मत करिये एकदम बढ़िया टॉप क्लास आफिसर अपाइंट कर रहे हैं कमिश्नर होगा और उसके ऊपर कौन सा बोले स्पेशल आफिसर होगा। स्पेशल आफिसर तो लगा दिये लेकिन रिजल्ट क्या है मैं बताना चाहता हूं इस विधानसभा के माध्यम से किराड़ी क्षेत्र हो बगल में मुंडका क्षेत्र हो, बवाना क्षेत्र हो, बुराड़ी क्षेत्र हो जहां-जहां अनॉथराइज कालोनीज हैं सब जगह पर यही हाल है। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाता है ईंटा गिरता है बाद में एमसीडी वाला सूंघते हुए पहुंचता है पहले लेकिन इनको यह समझ में नहीं आता है कि अगर छोटी नालियों की सफाई नहीं होगी तो इनफेक्ट हमारे यहां तो सारी मुख्य सड़कों पर नाला ही एमसीडी का है उसकी सफाई नहीं होगी नाला हमने बना भी दिया उसके बाद भी देखिये मेन रोड पूरा फ्लडेड है। अब इसके लिए भी बताइये कोई आदमी देखेगा तो क्या कहेगा उसको तो यही लगेगा न की इस क्षेत्र के अंदर और लोग गिर रहे हैं कोई मोटर साईकिल से गिर रहा है, कोई रिक्शा से गिर रहा है, कोई आटो से गिर रहा है, किसी का टायर फंस

रहा है, किसी का ट्रैक्टर फंस रहा है सबकुछ हो रहा है। अब इनको केवल झूठ से मतलब है। ये बिधूड़ी जी बातें बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जाकर के अपने कम से कम आकाओं को बोलें हर झूठ पर वाह करने से नहीं होता है। जो लोग हर झूठ पर वाह करते हैं वही एक दिन सबकुछ तबाह करते हैं। सच्चाई है जो हर झूठ पर वाह करते हैं वही सबकुछ तबाह करते हैं तो इनके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इस सदन का ध्यान मैं इस प्रकार से आकर्षित करना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने पूरी दिल्ली के अंदर में जो सिचुएशन क्रिएट कर रखा है उनके प्रति कोई किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी को फोन करेंगे फोन उठाएगा नहीं उठाएगा तो झूठ-सूठ जवाब देगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं इतने बड़े चोर उचक्के हैं ये लोग। आप सोचिये की मेन मुबारक रोड, 40 फुटा रोड, बाबा विद्यापति मार्ग ये सबकी सब एमसीडी की सड़क हैं और इन्होंने साफ नहीं किया। सर पर बारिश थी तो हमने अपनी सरकार की एक एजेंसी हैं Irrigation & Flood हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक काम करिये जो contractor हमारे नाले का काम कर रहे हैं आप उन्हीं से जो है इसकी सफाई कराईये। उन्होंने मानवता को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय, मानवता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने Irrigation Department के contractor से Private workers को हॉयर करके नाले की सफाई कराई और नाले की सफाई कराने के बाद जब उसका सिल्ट जो होता है यानी जो गंद होता है जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको दो दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ा जाता है ताकी सूखने के बाद उसको उठाकर के उसको डंप किया जाएगा। रात में पता चला अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान

मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं पता चला की एमसीडी की गाड़ी आई और उसका सिल्ट उठाकर चली गई। अब इरिगेशन वाले परेशान की भइया हमारा सिल्ट वो उठाकर ले गये तो हमारी बिलिंग कैसे होगी तब हमको पता चला कि सिल्ट का जो क्या बोलते हैं वजन होता है उसके आधार पर इसकी बिलिंग होती है। अब क्या हुआ देखिये रात को इरिगेशन का इंजीनियर आया, इधर से एमसीडी का इंजीनियर आया और रात में सोचिये पुलिस थाने में इस बात की पंचायत हो रही है कि वो सिल्ट है किसका। अब फोन बजता है विधायक ऋतुराज झा का फोन आया विधायक जी आप बताइये इसका निर्णय कैसे होगा। सोचिये हम गये और लैटर हैड पर हमने लिखकर दिया है आप कहेंगे तो हम प्रमाणित कर सकते हैं कि भइया हमने रिक्वेस्ट किया अपनी सरकार की एजेंसी आई. एन्ड. एफ. सी को क्योंकि एमसीडी वाले निकम्मे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर पर बारिश है, पूरी विधानसभा डूब जाएगी आप कर दो हमने लिखकर के दिया और हमने कहा की जो जमीन डीडीए से हमने ली है अभी वो खाली है आप वहां पर डंप कर देना उसके बाद आप उसको उठा लेना हमने लिखकर के दिया है तब जाकर के थाने में पंचायत खत्म हुई है बात समझ रहे हैं। मतलब सोचिये अभी तक सुनते थे फलानां चीज चोरी होती है लोहा चोरी होता है, गेट चोरी होता है, सेलरी चोरी होता है सफाई कर्मचारी का बताइये सिल्ट भी चोरी हो जाती है तब हमें समझ में आया कि दुनिया में हर चीज की कीमत है कुछ भी वेस्ट नहीं है। तो मैं आपको जो यह बात बोल रहा हूं यह इस पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि मतलब इनकी लड़ाई किस बात की है, काम नहीं करना है बस फर्जी बिल बनाना है तो अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता

जो टैक्स पेयर है जो वोट देती है टैक्स देती है उससे इनको तनखा मिलती है उससे यह पूरी व्यवस्था चलती है और जनतंत्र की जो मूल भावना है जैसा की मैंने शुरुआत में कहा जब हमारे संविधान निर्माता जब देश का संविधान बना रहे थे तो वो इस बात की चिंता कर रहे थे की किस प्रकार से जो सबसे नीचे की सरकार यानी लोकल बॉडी पंचायत है वो जितनी मजबूत होगी जनतंत्र उतना मजबूत होगा लोगों की समस्याएं उतनी ज्यादा सुनी जाएंगी, उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और लोगों का काम उतना ज्यादा होगा इसी बात के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से नगर निगम को यह मैसेज जाए ताकी वो लोग अनॉथराइज कालोनीज के अंदर खासकर के जो 60 फुट से छोटी सड़कें हैं वहां पर नालियों की सफाई कराएं और Lieutenant Governor यह सुनिश्चित करें कि जब तक चुनी हुई सरकार निगम में नहीं आती है तब तक इनका जो भी स्पेशल आफिसर है वो इस बात को सुनिश्चित करे की वहां की सारी सड़कों पर ड्रेनेज की सफाई अच्छे से हो ताकी बाढ़ जैसी स्थिति मानसून में न हो, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी वैसे तो ऋतुराज झा भाई ने अभी सारी बातें बड़ी विस्तार से बताई हैं लेकिन जब भी हम एमसीडी की बात करते हैं अध्यक्ष जी तो पूरी दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 15 सालों में जो दिल्ली को 15 साल में बर्बाद करने का काम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन आफ दिल्ली ने किया है चाहे वो नाले के माध्यम से हो चाहे वो सफाई के माध्यम

से हो चाहे वो कूड़े के ढ़ेर के माध्यम से हो चाहे वो करप्शन के माध्यम से हो ऐसा एक भी तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे जनता को परेशान कर सकें सारे तरीके इन्होंने अपनाये। अध्यक्ष जी, जब इनका अभी विदाई का समय आया जब इनको जाना था नगर निगम से तो उसी समय पर इन्होंने दिल्ली के चुनाव को भंग कर दिया।

जब इनको पता था कि दिल्ली के लोग इनकी विदाई करने वाले हैं और इन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे वादे उस समय पर किए कि अब जैसे ऋतुराज भाई ने बताया कि दिल्ली को स्पेशल आफिसर चलायेंगे, दिल्ली की एमसीडी एक होगी और एक होने से दिल्ली वालों को लगा शायद कुछ समाधान होगा। लेकिन अध्यक्ष जी, ये एमसीडी एक होने के बाद ये पहले मानसून की बारिश थी अभी मानसून पूरी तरह से आ भी नहीं पाया और पहले मानसून की बारिश ने ही दिल्ली को डुबोने का काम किया। दिल्ली को पानी-पानी करने का काम किया और जगह-जगह ये कुछ मैं फोटोज दिखा रहा हूं अध्यक्ष जी आपको कि किस प्रकार से जगह-जगह ये पानी का जलभराव जो एमसीडी के बड़े-बड़े नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई है अध्यक्ष जी। जैसे मुख्य तौर पर कुछ ड्रेन्स हैं अध्यक्ष जी, जो एमसीडी के अंतर्गत आती है बहुत बड़ी-बड़ी ड्रेन है ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन की। जैसे संजय ड्रेन है अध्यक्ष जी ये बहुत बड़ी ड्रेन है और एक न्यू अशोक नगर ड्रेन है जिससे हमारी विधान सभा, त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज जो तीनों विधान सभाओं का पानी होता हुआ आगे से पूरा गोकलपुरी से इस ड्रेन के माध्यम से आता है अध्यक्ष जी। हम लगातार कहते-कहते परेशान हो गए लेकिन किसी एमसीडी के आफिसर के कान पर जूं नहीं रेंगी और इनकी बदौलत की वजह से हमारा पूरा वसुंधरा एंकलेव मेरा, यहां रोहित जी बैठे हैं

इनकी बगल की विधान सभा का अशोक नगर इस ड्रेन की वजह से पूरा डुबने को तैयार बैठा हुआ था और जगह-जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ था। लेकिन एमसीडी के आफिसर के कानों तक जूं नहीं रेंगी और न ही इस ड्रेन को साफ किया गया अध्यक्ष जी। ऐसे ही मुकेश नगर ड्रेन है, अजीत नगर ड्रेन है, एमबी रोड ड्रेन है ये ऐसी ड्रेन है अध्यक्ष जी, जो एमसीडी की मुख्य तौर की बड़ी ड्रेन्स हैं जिनकी साफ-सफाई नहीं की गई। एक बात और अध्यक्ष जी, जहां-जहां जिस-जिस चीज का उद्घाटन या शुभारंभ मुझे कहते हुए खेद हो रहा है इस बात को कि जिस-जिस चीज का उद्घाटन और शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है वो चीज डुबने का काम हुई है अध्यक्ष जी हमेशा। चाहे वो कुछ भी हो एनएच-24 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया पूरा रोड शो किया। उस रोड के ऊपर आज एनएच-24 पर अध्यक्ष जी आप जाएंगे आपने फोटो भी देखी होंगी इतना-इतना पानी उसके अंदर खड़ा हुआ था बिल्कुल मुख्य सड़क जो मेरठ को जाती है। पूरे एनएच-24 के ऊपर करोड़ो रुपये खर्च किए गए, विज्ञापन में पैसा खर्च किया गया। लेकिन उसको डुबोने का काम हुआ, उसकी पानी की कोई निकासी अध्यक्ष जी नहीं की गई और लगातार वहां पर पानी का जलभराव हो रहा है। उसी तरह से अभी राजेन्द्र नगर में उपचुनाव था अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भाजपा के नेताओं ने सलाह दी होगी। उन्होंने कहा होगा प्रधानमंत्री जी शायद आप इसका उद्घाटन कर दोगे इस अंडरपास का तो शायद राजेन्द्र नगर चुनाव आप जीत जाओगे। अध्यक्ष जी, आनन-फानन में उसका उद्घाटन कर दिया गया और अभी जब आप देखेंगे उसके अंदर जाकर अध्यक्ष जी इतना-इतना पानी उसके अंदर जलभराव था कि कोई गाड़ी उसके अंदर नहीं निकल पा रही थी। उसके कारण से बगल में माननीय

उप-मुख्यमंत्री जी का घर है अध्यक्ष जी, पूरा घर उसकी जो लापरवाही थी उसके कारण से पूरी जगह पानी का जलभराव हुआ, पूरे में पानी भरा रहा। तो इस तरह के काम, इस तरह के प्रोजेक्ट पर ये लोग काम करते हैं जिनके ऊपर इनका ध्यान नहीं होता आनन-फानन में बस केवल वोट बटोरने के लिए जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन लोगों ने तब भी इनको इनका चेहरा दिखा दिया राजेन्द्र नगर के उपचुनाव में। तो अध्यक्ष जी, एमसीडी की कालागुजारी की तरफ से जितना करप्शन इन लोगों ने किया है अध्यक्ष जी, गाद के मामले में हमने एक पहले एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी इसमें कि गाद उठाने में करप्शन, गाद को डालने में करप्शन। तो आज जो दिल्ली को पूरा पानी-पानी करने का काम किया और एक ही मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मिन्टो ब्रिज रोड वहां कुछ समय पहले तक अध्यक्ष जी, पूरी बसें डुब जाया करती थी। अब की बार हम फोटो देख रहे थे सब लोगों ने फोटो देखी है अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वहां पर आज एक बूंद पानी जमा नहीं हो पाया और पूरा का पूरा इलाका क्लीयर रहा। तो ये होता है काम करने का तरीका अध्यक्ष जी और जो दिल्ली की सरकार लगातार कर रही है तो मुझे लगता है कि एमसीडी के हमारे आफिसर्स को एलजी साहब को भी कम से कम एमसीडी की इस कालाबाजारी के ऊपर इसके ऊपर मानसून सत्र में ध्यान देना चाहिए कि कैसे दिल्ली के नाले साफ हो पाए। आज गलियों के अंदर छोटी-छोटी नालियां बनी हुई है अध्यक्ष जी, उन नालियों को साफ करने का कोई काम नहीं हो रहा है। सबको पता है मानसून आ चुका है जब नाले की सफाई नहीं होगी अध्यक्ष जी, तो पानी का जो जलभराव है वो सारा

कहां जाएगा, उसकी निकासी कहां होगी। तो जो बड़ी–बड़ी ड्रेन्स हैं जिनमें ये सारा पानी गिरता है ये एमसीडी के जो ड्रेन्स के मैंने नाम लिए हैं इनकी तुरंत प्रभाव में सफाई हो अध्यक्ष जी और जो लापरवाही इन लोगों ने बरती है इसके अंदर। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ये लोग दिल्ली के चुनाव से डरकर भाग गए। इनको पता था कि दिल्ली के लोग इनको सबक सिखा देंगे अध्यक्ष जी अबकी बार और अबकी बार अगर चुनाव होते तो इनको सबक सिखा देते और मैं तो कहता हूं आप लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आप चुनाव कराइए जो चुनकर सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की वो दिल्ली के नालों को, एमसीडी के नालों को साफ करने का काम करेगी। जैसे पीडब्ल्यूडी के नालों को हमने साफ करने का काम किया, जैसे और नालों को हमने साफ करने का काम किया। आप दिल्ली में चुनाव कराइए डरिए मत अब तो राजेन्द्र नगर के बाद तो इनका डर और बढ़ चुका है। तो मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक रास्ता है जहां पर जनता को किसी भी सरकार को गिराने का मौका मिलता है। तो 15 साल की जिनकी कालागुजारी है, जो 15 साल का करप्शन है अध्यक्ष जी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए एमसीडी के और चुनाव होंगे। तभी दिल्ली की जनता को राहत मिल पाएगी इस जलभराव की समस्या से, इस कूड़े के पहाड़ की समस्या से तो दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत आभार मुझे मौका देने के लिए।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-54 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। मेरे साथी कुलदीप जी और ऋतुराज जी ने बताया कि किस प्रकार दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की स्थिति है और इन्होंने इसके लिए सिर्फ एमसीडी को दोषी ठहराया। जिस प्रकार से एक कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी के नालों की जो स्थिति है। एमसीडी दिल्ली सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार एमसीडी के गला घोंटने का काम किया। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण जिस प्रकार से एमसीडी ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया दिल्ली सरकार एमसीडी को शाबाशी देने तो गई तो दूर अपनी नाकामियों का ठीकरा भी दिल्ली सरकार एमसीडी के गले में डाल रही है। दिल्ली के अंदर आज जो जलभराव की स्थिति है मुझे लगता है कि हमें दोनों पक्षों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जलभराव की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर 60 फुट से ऊपर के जितने भी रोड हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास है हम सब लोग जागरूक विधायक है। नाले साफ करने का जो टेंडर है वो 60 परसेंट, 70 परसेंट बिलोव जा रहे हैं। जिस काम का सरकार एक लाख रुपया देना चाहती है ठेकेदार वो काम 25 हजार रुपये करने के लिए तैयार है। आखिरकार कहीं न कहीं तो कोई गोलमाल है। मैंने तीन-चार दिन पहले माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को मेल करी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था कि लोनी रोड गोलचक्कर पर इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा ये तैयारी की गई है। मगर वास्तव में माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी लोनी रोड गोलचक्कर पर आज तक सम्पवेल की ष्टीाल्ट भी नहीं निकली है बार-बार कहने के बावजूद और जो आसपास के मेरे भाई सुरेन्द्र जी बैठे हुए हैं गोकलपुरी लोनी रोड गोलचक्कर

पर क्या स्थिति है। नालों के अंदर से सिल्ट आज तक निकाली नहीं गई है, जहां पर निकाली गई है वहां पर सिर्फ लीपा-पोती की गई है। मेरा सभी माननीय विधायकों से अनुरोध है कि आज बड़ी-बड़ी सड़कों के ऊपर दिल्ली के अंदर जितनी सड़कें हैं उनके ऊपर एंक्रोचमेंट है। अगर नाले साफ करने की कोशिश भी की जाती है तो एंक्रोचमेंट के कारण वो नाले साफ हो नहीं पाते हैं और आप अगर खुद देखिए मेरे को लगता है माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी, इसकी माननीय विधायक कोई भी विधायक अगर ये शिकायत करता है कि उसके इलाके में नाले साफ नहीं किए गए हैं। तो इसकी जांच करवानी चाहिए और सबसे पहले मैं आपसे शिकायत करता हूं कि रोहताश नगर विधान सभा के अंदर पीडब्ल्यूडी नाले साफ नहीं किए गए हैं। नाले साफ करने के नाम पर औपचारिकताएं पूरी की गई है और जो टेंडर 60 परसेंट, 70 परसेंट बिलोव पर जो टेंडर छूट रहे हैं। उसके अंदर निष्छिचत रूप से सड़कों के ऊपर काम नहीं हो रहा है सिर्फ लीपा-पोती हो रही है और ये ही स्थिति पूरी दिल्ली की है। पूरी दिल्ली के अंदर आप किसी भी जगह के टेंडर उठाकर देख लीजिए चाहे आप वो पम्प हाउस चलाने के टेंडर देख लीजिए, नाले साफ करने के टेंडर आप देख लीजिए कहीं न कहीं दाल में काला है और काली दाल को छुपाने के लिए एमसीडी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इस कांड के अंदर पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार के अंदर जो-जो लोग शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमसीडी तो विपरीत परिस्थतियों में काम कर रही है, एमसीडी के कर्मचारियों को पांच-पांच महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उसके बाद भी वो बेचारे बरसात में भीगते हुए छोटे-छोटे नाले-नालियां जो उनके पास है वो साफ कर रहे हैं। देखना यहां इस बात की जरूरत है कि दिल्ली सरकार अपने

गिरेबान के अंदर झांककर देखे जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्टाचार है। पीडब्ल्यूडी के नालों को साफ करने में भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यूडी के जो पम्पहाउस हैं उनकी स्थिति ये है पीडब्ल्यूडी के पम्पहाउसिज से जो अभी तक सिल्ट नहीं निकाली गई है और माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब वहां तो खेल ये भी है कि अगर 70 किलोवॉट की मोटर है तो उसके ऊपर टैग लगाकर 30 किलोवॉट की मोटरें भी लगाई जा रही हैं आप चेक करवा लीजिए। ये कुल मिलाकर दिल्ली की स्थिति है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी इस विषय पर अनुरोध है कि ये सदन एक ज्वाइंट कमेटी बनाए जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हो और दिल्ली के अंदर जो जलभराव की स्थिति है उसको लेकर मिलकर काम करें और वास्तव में चाहे वो सत्ता पक्ष के हमारे साथी विध ायक है चाहे हम विपक्ष के लोग है। जब भी सड़कों के ऊपर जलभराव होता है तो सभी को असुविधा होती है जनता को असुविधा होती है और आगे से ऐसा कोई एक जिसे कहते हैं कि मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि काम करने के नाम पर जो लोग टेंडर लेते हैं, काम करने के नाम पर जो 60 परसेंट, 70 परसेंट बिलोव टेंडर लेते हैं हमें भी मालूम है कि 70 परसेंट बिलोव में काम नहीं हो सकता है, बिलोव टेंडर में काम नहीं हो सकता। इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं जितेन्द्र महाजन जी के ही बात को आगे बढ़ाते हुए सदन से ये अपील करना चाहता हूं कि जलभराव को

लेकर दिल्ली की एक-एक जनता परेशान है और सत्तापक्ष कहें एमसीडी नहीं कर रहा है, विपक्ष कहता है पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। हम सब बैठकर सोल्यूशन निकालने के लिए शायद तैयार नहीं है इसके माध्यम से भी हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहां लक्ष्मीनगर विधान सभा में तीन-चार प्रमुख सड़कें हैं जो सब पीडब्ल्यूडी का है और लगातार मैंने हाउस में भी प्रश्न लगाए हैं और पीडब्ल्यूडी ने बार-बार मुझसे आश्वासन दिया कि हम नाला सफाई के लिए टेंडर निकाले हैं नाले की सफाई कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ऐसा क्या बात है कि नगर निगम की नालियां नहीं साफ हुई इसलिए क्या पूरी दिल्ली में अंडरपास में पानी भरता है। चाहे कनाट प्लेस का उदाहरण हो, चाहे मुबारकपुर का उदाहरण हो, चाहे पटपड़गंज अंडरपास का उदाहरण हो। सारे पीडब्ल्यूडी रोड्स पर ही पानी क्यों भरता है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं गया हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों का हर तरफ से निकलना मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं मौके पर स्वयं गया हूं। नगर निगम के नाले को लेकर कोई जाम पीडब्ल्यूडी के रोड पर नहीं लगता सत्य ये है।..

...व्यवधान...

श्री अभय वर्मा: बीच में ऐसे नहीं।...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: भई एक सेकेंड, भई एक सेकेंड।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मैं देख रहा हूं, न आप डायरेक्शन देंगे? मैं रोक रहा हूं न उनको आप डायरेक्शन देंगे क्या?

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अभी आप नोट कर लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं है।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः अध्यक्ष जी, रोड्स के नाम पर, पुल प्रल्हादपुर कोई बात नहीं है। अरे ऋतुराज जी रोड्स के नाम पर लड़ाई कर रहे हो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी बैठ जाइए उनको अपना स्पीच पूरा करने दीजिए।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्माः रोड के नाम पर लड़ाई में मत पड़े।

...व्यवधान...

...व्यवधान...आपको मौका मिल जाएगा दोबारा। आप बैठिए आपको मौका मिलेगा।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्मा: पूरा दिल्ली पानी से भरा होता है,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: रोक दिया भई मैंने, मैं खुद रोक रहा हूं।

...व्यवधान...

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: तो मैंने रोक दिया उनको।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी, रोड्स के नाम पर कोई भी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: बोलने का मौका दे देंगे बाद में अभी।

श्री अभय वर्मा: जब अखबार उठाते हैं तो पूरा एक पेज पीडब्ल्यूडी के नाले के कारण रोडों पर जो जाम लगता है वो पूरा एक पेज छपता है और उस पेज को पूरे भारत के लोग पढ़ते होंगे। हम अपना दोष नगर निगम पर फेंककर भाग नहीं सकते। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पीडब्ल्यूडी नाले की सफाई का कार्यभार क्यों अपना जिम्मा ले रखा है। दाल में काला है अध्यक्ष जी, जब आप नगर निगम को कहते हों कि नाले की सफाई नगर निगम करेगी तो वो भी नाले दो न आप नगर निगम को। होता क्या है अध्यक्ष जी, छोटी-छोटी नालियों से पानी इकट्ठा होकर जब बड़े नाले में गिरता है और बड़े नाले की अगर सफाई नहीं होती है तो वो रोड पर पानी आता है ये मेरा स्टडी है। आप किसी भी विशेषज्ञ को भेज दीजिए पानी रोड पर इसीलिए आता है छोटी-छोटी

नालियों से मोहल्ले गली और छोटे-छोटे कस्बे से सारा पानी निकलकर जब बड़े नाले में आता है और बड़ा नाला चूंकि साफ नहीं होता है इसलिए वो पानी रोड पर जाता है और फिर रोड पर जाने के बाद वो अंडरपास पर जाता है। तो सबसे बड़ी गलती अगर कही जाए तो एक तो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है और दूसरा डिपार्टमेंट फ्लड कंट्रोल है। फ्लड कंट्रोल और पीडब्ल्यूडी के पास कोई व्यवस्था नहीं है नाले की सफाई की।

वो सिर्फ बाहाना निकालते हैं कि हम टेंडर कर रहे हैं जी। प्राईवेट टेंडर को बुलाएगें और सफाई कराते हैं हम। क्या अध्यक्ष जी, बारिश के समय एक बार बड़े नाले को साफ करके क्या पूरे साल उस नाले का हम उपयोग कर सकते हैं। नगर निगम सालों भर छोटी-छोटी नालियां साफ करती है तब भी हम उन पर दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी सिर्फ टेंडर निकालेगी, कागज पर टेंडर का काम पूरा करेगी और ये जो सिल्ट की चोरी की बात चल रही है ना पीडब्ल्यूडी से बड़ा चोर कोई नहीं है। ये किसी भी कूड़ा को उठाकर ले जाते हैं पीडब्ल्यूडी वाले। तो मेरा सिर्फ, ये काम, पकड़ना काम सरकार का है, हमारा नहीं है।...

माननीय अध्यक्ष: चलिए अभय जी अब हो गया। पूरा हो गया।

श्री अभय वर्मा: अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, एक आखिरी निवेदन है, मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि इस जल भराव से हर व्यक्ति परेशान है। सादगी और पोजिविटी के साथ बैठकर सोचना चाहिए और किसी एक एजेंसी को जिम्मेदारी देना चाहिए। ये तीन-तीन एजेंसी एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे। कभी भी ये नाले साफ होंगे नहीं और ये जल भराव की समस्या समाप्त

नहीं होगी। कोई एक एजेंसी सर तय कीजिए। और पुल प्रहलाद पुर की घटना आपको पता ही है सारे मीडिया में सबसे ज्यादा इसी के बारे में लिखा जाता है। सारी गलतियां पीडब्ल्यूडी का, आईटीओ पर कनॉट प्लेस पर बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे जगहों पर पानी भरता है। क्यूं भरता है, ये सवाल पूछना चाहिए, आज मंत्री जी को जवाब देना चाहिए इस विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः हो गया अब। चलिए। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप ऋतुराज जी, क्या कह रहे थे आप।

श्री ऋतुराज गोविंदः सर मैं ये कह रहा था कि माननीय सदस्य ने कहा मुबारकपुर रोड। मैने अपने भाषण में भी इस बात को कहा था कि जितनी भी सड़कें 60 फुट से छोटी सड़कें होती है वो एमसीडी की सड़क है। मेन मुबारक पुर रोड किराडी क्षेत्र की बात हो रही है जो इसका इन्होंने जिक्र किया।

...व्यवधान...

श्री ऋतुराज गोविंदः अरे सुनिये पहले पूरी बात।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं ऐसे नहीं चलेगा अभय जी। नहीं, ऐसे नहीं।

श्री ऋतुराज गोविन्दः आपको, आपने बोल लिया, अब मेरी बात भी सुनो। मेन मुबारकपुर रोड किराडी विधान सभा क्षेत्र का मुख्य सड़क है और जिसकी हालत सात साल से इतनी खराब है, इतनी खराब है आज मजबूरन में हमको नाला बनाना पड़ रहा है। जिसकी सिल्ट निकाली और उसको चुराकर के एमसीडी ले गई। जिसका जिक्र मैंने अपने भाषण में किया। अब ये मुबारकपुर रोड की

बात कर रहे थे। मिसलीड कर रहे हैं पूरे हाउस को। मैन मुबारक पुर रोड एमसीडी की सड़क है इन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी की सड़क है। मेरा ऑब्जेक्शन उस बात पर था स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः चलिए। संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि मुझे एमसीडी के लापरवाही और जिस तरह से दिल्ली में जल भराव हो रहा है, उस पर चर्चा करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जिस विधान सभा को मैं रिप्रजेंट करता हूं वो अन-ओथोराईज्ड कालोनी से बसा हुआ विधान सभा है। अन-ओथोराईज्ड कालोनी में गलियां और सड़कें बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और दिल्ली सरकार की है। गली और सड़क बन जाती है लेकिन उसको साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। अभी मैं अपने विपक्ष के दोनों साथियों को सुन रहा था। दोनों ने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके हमें ये साफ सफाई कैसे हो उस पर चर्चा करना चाहिए और दोनों साथियों ने कहा कि एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है, सारी जिम्मेदारी जल बोर्ड की है, "लड इरिगेशन की है। अब एक बात समझिए अगर एक साधारण सा सर्वे करा लें पूरी दिल्ली में कि एमसीडी की साफ सफाई की क्या स्थिति है तो आपको सारा दृष्य समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं इसका मतलब ये है कि आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं। आप जनता के बीच में नहीं है और जनता की परेशानी की खबर आपको नहीं है। आज एक सांईटिफिक तरीका भी बता रहे थे हमारे एक साथी कि सिल्ट कैसे होता है पीडब्ल्यूडी की नालियों में

सिल्ट भरा रहता है नालियां साफ हैं वहां से पानी आती है क्योंकि वो भरा हुआ है इसीलिए जल भराव हो जाता है। अगर थोडा विस्तार से गलियों में जाते होंगे तो समझ में आएगा कि जब बारिश तेज होता है तो अगर छोटी गलियों का सिल्ट आप नहीं निकालते हैं तो वो बारिश के साथ सिल्ट जाता है और जो बड़ी नाली है उसको वो भर देता है और जब वो भर देता है तो जल भराव की स्थिति आती है। तो पहले ईमानदारी से या तो आप राजनीति कर लीजिए या ईमानदारी से ये मान लीजिए कि एमसीडी के नाकारापन के कारण आज दिल्ली में स्थिति इस तरह की अव्यवस्था है। एक भी गली मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी गली दिल्ली में एमसीडी मानसून से पहले अपनी तैयारी नहीं करी है, साफ सफाई नहीं करा है। मानसून से पहले दो जिम्मेदारी है एमसीडी की। एक जितनी भी छोटी सड़कें हैं अगर वो डैमेज हैं तो उसको रिपेयर करें और दूसरा कि जितनी भी गलियां है उसको साफ-सफाई करें। हम लोग एलजी साहब से मिले थे। एलजी साहब ने कहा कि हम दिल्ली में नए है। हम दिल्ली को समझना चाह रहे हैं कि दिल्ली में काम किस तरह से हो रहा है और इसीलिए हम आप लोगों से सजेशन भी लेना चाहते हैं। हमने उनको ईमानदारी से वहां भी सजेशन दिया था। हमने एलजी साहब को कहा था कि देखिए दिल्ली में, दिल्ली सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम हो रहा है और हम लोग काम करा पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तीन एजेंसियां जो है उससे दिल्ली की जनता बहुत निराश है। एक एमसीडी दूसरा डीडीए तीसरा दिल्ली पुलिस। और हमने कहा कि एमसीडी का काम हम नहीं करा पा रहे हैं। डीडीए का काम हम नहीं करा पा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर और उन्होंने कहा कि हमारा एक विजन है कि हम

दिल्ली को किस तरह से एक अच्छा सिटी बनाए। उन्होंने उदाहरण भी दिया। हमारी मिटिंग में उन्होंने कहा कि ये जो कूड़े का ढेर है ये कूड़े का ढेर नेशनल सेम है। हमने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पन्द्रह साल में बीस साल में एमसीडी ने हमें कूड़े का ढेर बना करके दिल्ली को नेशनल सेम जरूर बनाया है, इसमें आपसे मैं सहमत हूं। लेकिन अगर ये एजेंसी हमारे कहने से काम नहीं कर पा रही है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको ये इन्श्योर कराना पडेगा कि ये एमसीडी और जो दोनों एजेंसीज है वो ठीक से हमारे कहे पर काम कर ले या आप कोई एक मैकेनिज्म बनाए, जिस मैकेनिज्म के जरिए जनता उनसे काम करवा पाए। ये देखकर मुझे थोड़ा हैरानी भी होती है और दुख भी होता। मैं रोज एलजी साहब का वो विजिट देखता हूं। वो कभी जल बोर्ड की विजिट करते रहते हैं, कभी सीवर की विजिट करते हैं, कभी कोई इन्वायरमेंट की विजिट करते हैं। लेकिन दिल्ली में एमसीडी की जो गलियों की हालात है उस पर उनका कोई एक न ता ट्विट आ रहा है ना तो कोई उस पर कोई ठोस कार्रवाई दिख रही है। अब देखिए इन्होंने एमसीडी का इलैक्शन टाल दिया। चलो जैसा ही सही चोर, बेईमानी ही सही पार्षद था लोग जाता था उसकी गर्दन पकड़ते थे विरोध करता तोकुछ काम हो जाता था। आज दिल्ली में इलैक्शन टालने के बाद दिल्ली की हालत ये है कि कोई जनता किस के पास जाए। भई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। अधिकारी तक उसकी पहुंच नहीं है। गेट के अंदर वो जा नहीं सकता। तो वो किस को कहे कि एमसीडी की क्या परेशानी है ये आप अन्दाजा लगा सकते हैं और उसका ये परिणाम है कि आज हर तरफ एक बदहाली की स्थिति है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से एमसीडी को भी और मैं निवेदन ये

करना चाह रहा हूं एलजी साहब को कि अगर आप जो हम सब के बीच में बैठ कर जो आप एक विजन की बात कर रहे थे जो आप ये कह रहे थे कि दिल्ली को हम सब लोग मिल करके बेहतर बनाऐगें तो फिर वो पार्टिसिपेशन या वो एक्शन दिख नहीं रहा है। फिर वो आपका भी जो एक्शन है वो राजनीतिक तौर पर ही दिख रहा है वो राजनीति से परे नहीं दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आप को एमसीडी को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। एमसीडी तक लोग कैसे पहुंचेगा आज किसी को नहीं पता। भई एमसीडी से बात करने के लिए डीसी, कमिश्नर से बात करो कितनी जनता। मैं तो, मैं एक उदाहरण देता हूं बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको। आज से चार दिन पहले कोई एक व्यक्ति आया उसने कहा कि 75 गज में मेरा मकान बन रहा है और वो मकान तोड़ने का नोटिस आ गया है। मैने डीसी को फोन किया। मैने कहा जी ये 75 गज में कोई मकान बनाया है और आपने गरीब आदमी है और उसको मकान का आपने कहा, वो भी कोई आर्डर नहीं था। हथौडा लेकर पहुंच गया था बोला डीसी साहिबा ने कहा है तोड़ने के लिए। तो हमने कहा एक तो वर्बल आर्डर पर तोड़ रहे हो समझ में नहीं आया पहली बात और दूसरी बात की आप ऐसे हमारे यहां तो हमने कम्पलेंट किया, बड़े-बड़े टॉवर बन रहे हैं वो तो टूट नहीं पा रहा है। तो बोला नहीं-नहीं-नहीं ये तो हमारे पास जिसका कम्पलेंट आएगा उसको मैं तोडूंगा, आप कम्पलेंट कीजिए। हमने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए ये पिक एंड चूज नहीं होगा। नैचुरल जस्टिस ये कहता है कि सबका डेमोलिशन होना चाहिए फिर। कोई एक गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे उसका डेमोलिशन हो जाएगा और जो दिया उसका बच जाएगा। तो ये एक पूरा गैंग आपरेट करता है जिस गैंग में जो अधिकारी

हैं वो अपने यहां दो चार लड़के रखते हैं। उससे पहले कम्पलेंट कराते हैं फिर पैसे लेते हैं। पैसे मिल गए तो ठीक नहीं पैसे मिल गए तो उसका डेमोलिशन कर दिया गया। तो हमने कहा कि डीसी साहिबा आप उस गैंग का सरदार मत बनिये। मैं इसको आपको इसलिए अभी फोन कर रहा हूं कि पहले एक आपको जानकारी देता हूं वरना अभी ईमानदार लोगों से पाला नहीं पड़ा है। मैं कमेटी में बुलाकर पूछूंगा आपसे कि ये आप कम्पलेंट आए तो काम करेंगे और जो कम्पलेंट नहीं है तो मकान बन जाएगा ये कहीं कोई कानून नहीं कहता है। तो एमसीडी एक लूट का सेंटर बन गया है। अब उस लूट के सेंटर में ये सारे अधिकारी आ गए हैं जहां तक जनता की पहुंच नहीं है। तो इससे जनता परेशान है। एक बारिश हुई है। हमारे यहां एक बारिश में मैने ये देखा कि हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। मैने आज 280 में भी ये ही अपनी चिंता आपको जताया था कि अब सारा जल जमाव एक जगह हो जाता है। कोई साफ सफाई है नहीं। लोगों को निकलना दूभर हो जा रहा है। तो मैं ये मानता हूं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राजनीति से परे उठकर हम सब लोगों को ये तय करना चाहिए कि वास्तव में किस तरह से एमसीडी को जिम्मेदार बनाएं ताकि ये जो समस्याएं आज है जो चर्चा कर रहे हैं उससे जनता को निजात मिले। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं आज जो ऋतुराज भाई ने आज अपनी जो एटेंशन शार्ट डयूरेशन में जो चर्चा किया है मैं उनकी बातों से रूल 54 का जो कालिंग एटेंशन लाया है, मैं उस बात से सहमत हूं और मुझे ये लगता है कि सदन के जरिए ये मैसेज एमसीडी को भी जाए और मैं निवेदन एलजी साहब को भी करता हूं कि इसको संज्ञान लीजिए। अब ये इम्रजेंट नीड

है ताकि ये कुछ लगे कि आप राजनीति नहीं कुछ जनता की दिल्ली में भलाई करने के लिए आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। राखी बिरला जी।

श्रीमती राखी बिरलाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, लगातार तीसरी बार मैं इस विधान सभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहीं हूं। और हर वर्ष मानसून में जो हम लोग स्थिति देखने को हमें मिलती है वो हर साल उससे भी ज्यादा बदतर होती दिखाई देती है। मुख्य तौर पर उसका कारण जो सबसे छोटी एजेंसी है, नगर निगम वो उसकी असफलता को दर्शाता है उसकी असफलता को उसके निकम्मेपन को उसकी चरमराई हुई व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आती है हर साल मानसून के सीजन में। अभी एक साथी विपक्ष के बोल रहे थे कि पूर्ण रूप से इसके लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है। हालांकि डेढ़ दशक से ज्यादा जिस नगर निगम में प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नियन्त्रण था तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसका फेलियर उसका निकम्मापन ये कैसे इस सदन के अंदर जो है एक्शप्ट कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से दिल्ली की चरमराई हुई व्यवस्था दिल्ली की निकासी जो पूर्ण रूप से बदहाल है दिल्ली को कूड़ा-कूड़ा करने की जो भाजपा के नेतृत्व में एमसीडी का कार्य काल रहा है। तो इनको लगता है कि हम उस संस्था को जिम्मेदार ठहराएं जिस संस्था ने चंद सालों के अंदर मिन्टों ब्रिज जैसे जल भराव को खत्म करने का काम किया है। उसकी दूसरी तरफ हम देखें यहां तमाम विधायक बैठे हैं और एक साथी विधायक ने बहुत ही तर्क के साथ बहुत ही आंकडों के साथ बताया

है कि साठ फिट से नीचे जितनी सड़कें आती हैं वो नगर निगम के अन्तर्गत आती हैं और उन तमाम सड़कों पर समय रहते हुए ना तो नाली की और नालों की सफाई की जाती है ना ही उन पर फैले हुए या उन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाता है ना ही उनकी कोई सुध ली जाती है। और इसके पीछे जो एकमात्र लक्ष्य एकमात्र जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से भागना, अपने निकम्मेपन को दर्शाना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा काम है। अभी पिछले महीने जब माननीय उप-राज्यपाल महोदय ने शापथ लेकर दिल्ली में अपना कार्यभार सम्भाला तो मैने व्यक्तिगत तौर पर उनसे संवाद किया, उनसे मुलाकात की और मैंने और मेरे साथी विधायकों ने इस बात पर पुरजोर ध्यान उनका दिलाने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार अपने आप में ऐतिहासिक काम कर रही है। दिल्ली सरकार अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनका पूरा मंत्रीमंडल जो-जो उनके जिम्मे काम है उन पर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिन-रात परिश्रम और मेहनत करते हुए दिल्ली की जनता को सुलभ और एक सुविधाजनक योजनाएं देने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है, बजाए आप दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कार्यों के अंदर हस्तक्षेप करें इसकी बजाए माननीय उप-राज्यपाल महोदय जी मेरा आपसे निवेदन है की आप एमसीडी की चरमराई हुई व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें। आप ध्यान दें इस बात के ऊपर की मानसून आने वाला है और मानसून आने से पहले बरसात आने से पहले आप इस बात को सुनिश्चित करें की दिल्ली की हर एक नाली, हर एक नाला जो एमसीडी के अंतर्गत आता है वो समय रहते हुए साफ हो जाएगा। हर एक वो पेड़, हर एक वो टेहनी जो खतरनाक स्थिति, परिस्थिति में है और तेज आंधी-तूफान में कभी-भी गिरकर किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को,

किसी भी नागरिक को क्षति पहुंचा सकती है, आप कृपया उस ओर अपने ध्यान को लेकर जाएं। लेकिन माननीय उप-राज्यपाल महोदय को तो राजनीति करनी है, उनको तो दिल्ली सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करना है। उनको तो मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की फाइल को रोकने के काम के लिए केंद्र सरकार के माध्यम यहां जरिया बनाकर भेजा गया है। तो मैं यहां विपक्ष के साथियों से इतना कहना चाहती हूं की डेढ़ दशकों तक आपने जिस नगर-निगम की सरकार को चलाकर बदहाल, बदत्तर और बहुत जर्जर व्यवस्था के अंदर छोड़ दिया है वही आज खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है की महज आधे घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली पानी-पानी हो जाती है और स्थिति ये होती है की हमें अपने राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग, फ्लड विभाग या अन्य डिपार्टमेंटो से हाथ जोड़कर निवेदन कर-कर मानवता के आधार पर वहां पर पानी की निकासी के लिये प्रबंध करवाने पड़ते है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं, चूंकि इस वक्त दिल्ली देश की राजधानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से माहौल ऐसा है की इन्होंने चुनाव कराया नहीं और ये सिविक एजेंसियाँ जब अस्तित्व में थी तब भी काम नहीं कर रही थी और आज अस्तित्व में नहीं है तो काम करने की हम क्या ही उम्मीद करेंगे। तो आज आपकी चेयर से इस बात का निर्णय और इस बात का यहां से फैसला होना चाहिये की तुरंत प्रभाव से जितने भी जिम्मेदार अधिकारी, पूरी एमसीडी को एक करने के बाद लगाए गए थे उन तक ये संदेशा पहुंचे की जहां-जहां एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कें है, नालियाँ है या ऐसा कोई भी स्थान है जहां पर जल जमाव, जल भराव होता है, उस पर एमसीडी के अंतर्गत जो भी अधिकारी, कर्मचारी काम करते हैं उनके

लिये एक जिम्मेदारी को तय किया जाए और अगर समयबद्ध तरीके से उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सभी माननीय सदस्यों की चिंताओं को और उनकी परेशानियों को जो क्षेत्र में जनता को परेशानियाँ हो रही है उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं appreciate करता हूं की उन सभी पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की जनता को हो रही असुविधाओं, परेशानियों को यहां तक लेकर आए हैं, उनके प्रति उनका observation उनका कहने का तरीका different हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से जब परेशानी हो रही है तो हमें स्वीकार करना चाहिये की परेशानी हो रही है। क्योंकि बात यहां राजनीति की नहीं है, बात ये नहीं है की कॉग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बात तो ये है की जनता को प्रोब्लम हो रही है और अगर जनता को प्रोब्लम हो रही है तो वो ये कहें या ये कहें या ये कहें या मैं देखूं प्रोब्लम तो प्रोब्लम है। तो मैं समझता हूं कि इसको हमको प्रोब्लम के रूप में देखना चाहिए और मैंने बहुत reviews किये हैं, मैं खुद गया हूं क्षेत्र में, जगह-जगह जाकर मैंने देखा भी है। पर क्योंकि इस वक्त दिल्ली सरकार के दायरे में पीडब्ल्यूडी के 2000 किलोमीटर के नाले आते हैं। उसके अलावा

बाकी नाले या तो डीडीए के पास हैं या एमसीडी के पास में हैं और यही इस बात की समस्या है। अभी हम यहां सदन में देख रहे थे की दोनों ही माननीय सदस्यों को सम्मान देते हुए with due respect मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में बैठे हुए लोगों में भी confusion है की भई कौन सा नाला पीडब्ल्यूडी का है और कौन सा एमसीडी का है और कौन सा डीडीए का है। तो भ्रम तो है ही, confusion उस तरह से कह सकते हैं। तो जनता में तो और ज्यादा होगा, अब जनता किसको बोलेगी, जनता किसको जाकर कहेगी, वो पीडब्ल्यूडी के पास जाएगी वो एमसीडी के पास भेज देगा, एमसीडी के पास जाएंगे वो पीडब्ल्यूडी के पास भेज देगा। तो समस्या की जड़ यहीं है कि नालों की जातियाँ बंटी हुई है, कुछ पीडब्ल्यूडी की जाति के नाले हैं, कुछ एमसीडी की जाति के नाले हैं, कुछ डीडीए की जाति के नाले हैं और सब जाति के टकराव में जनता दुखी है, इसमें मैं सहमत हूं। पर इसका समाधान निकालने के लिये मैं जब रिव्यू करते हैं सब करते हैं तो सारी चीजों को देखते है, पीडब्ल्यूडी वाले भी जब आते है रिव्यू मीटिंग में या मुझे दिखाते हैं, कहते हैं जी हमने देखो ये साफ कर दिया। फिर हम कुछ खामी ढूंढ़ते हैं हम कहते हैं भई ये गलत कर रखा है इसको ठीक करो। निष्छिचत रूप से एमसीडी वाले भी यही दावा कर रहे होंगे जैसे पीडब्ल्यूडी वाले दावा कर रहे हैं जी हमने तो सारे साफ कर दिये। मुझे लगता है हमें इस सदन में बैठकर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को justify नहीं करना चाहिये। हमें ये justification नहीं देनी चाहिये नहीं जी पीडब्ल्यूडी इसके पास है या एमसीडी इसके पास है। अगर पीडब्ल्यूडी ने या एमसीडी ने मानसून से पहले अगर किसी भी नाले को बिना साफ किये हुए छोड़ा है और कहीं किसी रिपोर्ट में लिख दिया हमने साफ कर दिया तो

वो अपराध है। वो चाहे एमसीडी वाले ने छोड़ा हो और वो चाहे पीडब्ल्यूडी वाले ने छोड़ा हो। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं कि अगर पीडब्ल्यूडी वालों ने कहीं गड़बड़ करके छोड़ा होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी माननीय विपक्ष के सदस्यों ने एक बात बहुत गम्भीरता से उठाई की किसी जगह sump बनाया गया वहां पर sump में मोटर एक्स पावर की जगह उस पर लेबल लगा दिया गया, मैं बिल्कुल justify नहीं करता, नहीं किया होगा। हो सकता है किया हो, किसी ठेकेदार ने बदमासी की हो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई। देखिये अंहनमसल कहना की मोटर्स ऐसी लगा दी, 900 मोटर लगी हुई हैं दिल्ली में इस वक्त। जो मेरे पास latest जानकारी है। अब 900 की 900 मोटर्स के बारे में ये कह देना की भई सब जो है आधी horse पावर, मतलब एक horse पावर की दिखाकर आधी horse पावर की लगा दी गई हैं, ऊपर टैग है मुझे लगता है ये ज्यादती होगी। अगर माननीय सदस्य किसी स्पेशिफिक एरिया या मोटर या किसी लोकेशन के बारे में ये बताएं यहां इस ठेकेदार ने ये गड़बड़ कर रखी है, टांग दूंगा उस ठेकेदार को और उस इंजिनियर को जो जिम्मेदार है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने कोई रिश्तेदारों को ठेके थोड़े ही दे रखे हैं, हमने कोई इंजिनियरों से रिश्तेदारी थोड़ी बना रखी है। अगर कोई इंजिनियर किसी ठेकेदार से गड़बड़ी करवायेगा या कोई ठेकेदार गड़बड़ी करेगा इस तरह की तो ये केजरीवाल जी की सरकार है खा जायेगी, कच्चा चबा जायेगी अगर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो। लेकिन यही जिम्मेदारी फिर नगर निगम की भी लें। अब ये एकीकरण के नाम पर पूरे नगर निगम को, कानून को धवस्त कर दिया। एक व्यवस्था बनाई हुई थी, चुनाव तो कई साथियों ने बोला, चुनाव तो है ही है, चुनाव टाल दिया और वो तो

चलो राजनीतिक स्थिति है। इतनी घटिया व्यवस्था बना दी है एकीकरण के नाम पर। नगर निगम के कानून के हिसाब से, पहले के हिसाब से दिल्ली सरकार में एक ऑफिसर होता था जो तीनों लोकल बॉडिज का डायरेक्टर होता था। अब ये एकीकरण का कानून लागू करके इन्होंने कहा भई दिल्ली सरकार का अफसर हमारे ऊपर नहीं होगा अब। उसमें लिख दिया दिल्ली विधान सभा अब सवाल भी नहीं पूछ सकती नगर निगम से। तो आप दिल्ली विधान सभा से सवाल नहीं पूछने देना चाहते, आप दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार में जो लोकल बॉडी का डायरेक्टर था आपने कानून बनाकर उसको भी खत्म कर दिया। फिर आपसे कोई कहीं पूछ ले की भई ये नगर निगम के नाले साफ क्यों नहीं हुए। वो ऋतुराज जी पूछ रहे हैं भई सिल्ट की चोरी क्यों करके ले गए, बोले पैसे नहीं दिये थे। अरे दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिये थे तो क्या सिल्ट बेच के खाओगे। ये जो सिल्ट की चोरी करी, इसलिये की है क्या ये कोई justification है क्या। बिल्कुल justify नहीं करना चाहिये गलत चीजों को। अगर किसी, मैं खुलकर कह रहा हूं फिर से दोहरा देता हूं, अगर किसी पीडब्ल्यूडी के इंजिनियर ने अलाउ कर रखा है या किसी ठेकेदार ने चोरी से ज्यादा horse पावर की मोटर दिखा कर, किसी sunp में कम horse पावर की मोटर लगा रखी है, मैं स्पेशिफिक जानकारी दें मैं personally टांगूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन नगर निगम के सारे पाप को, ये कहकर justify करते हो, सिल्ट क्यों चोरी हो गई जी। क्योंकि दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिये। अरे दिल्ली सरकार ने जितने पैसे देने थे वो तो दे दिये, फिर भी तुम्हें कम लग रहा है की भई चादर हमको 25 फीट वाली लम्बी चाहिये थी हमारा तो 7 फीट में काम नहीं चल रहा। तो ठीक है सोचते रहो कोई झंझट नहीं है।

पर इसका मतलब सिल्ट चोरी करने का, अब सिल्ट खाओगे क्या? पैसे तो खा गए सारे जितनी जनता देती है और सरकार देती है। अब सिल्ट भी खा जाओ चोरी कर–कर के। वो ऋतुराज के इलाके की सिल्ट खा गए चोरी करके। तो इसको justify नहीं करना चाहिये, गलती है अगर कहीं कोई सरकारी विभाग, कोई ठेकेदार गलती कर रहा है जनता को प्रोब्लम हो रही है, बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। और मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं की कहीं से भी, किसी भी इलाके में जहां आपको लगता है कि इस vaguely नहीं, अब 2000 किलोमीटर के पीडब्ल्यूडी के नाले हैं और एमसीडी के भी हजारों किलोमीटर के नाले है। vaguely लिख दो मेरे इलाके में नाले साफ नहीं हुए जी, वो थोड़ा सा vague information है आप बताएं की मेरे इलाके में ये वाले से लेकर ये वाले नाले तक साफ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ confusion होगा, इंजिनियर ने रिकोर्ड पर कराकर कुछ create कर रखा है मैं जवाब दूंगा और नहीं होगा, अगर नाला साफ नहीं हुआ है और गलत लिख रखा है, तो फिर उसको करेंगे, ठीक करेंगे उसको सारी चीजों को ठीक करेंगे और जो गलत कर रहा है, अगर कोई नम्बर दो का पैसा खा रहा है उसको भी ठीक करेंगे, ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे किसी को, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। नियम–55 के अंतर्गत श्री सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली की निर्वाचित सरकार के दायरे से सर्विसिज को हटा देने के असंवैधानिक कदम के कारण निर्वाचित सरकार तथा इसके विभागों जैसे उच्चतर शिक्षा आदि के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी,पहले हमने भी।

माननीय अध्यक्षः भई मैंने देख लिया, जो मैंने, देखिये वो अधिकार अध्यक्ष का है। मैंने कल, जो मुझे उचित लगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं कोई सवाल नहीं है, प्लीज।

नेता प्रतिपक्षः सुबह 11 बजे ये एलओबी आता है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

नेता प्रतिपक्षः सदन में चर्चा हो सके, उसके लिये 11 बजे एलओबी दी जाती है।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

श्री अजय कुमार महावरः ये परंपरा नहीं है और हमने नियम के तहत 3 दिन पहले 7 हमने वो लगाए हैं, short discussion.

माननीय अध्यक्षः बैठिये प्लीज। जो मैंने accept किया है वो हो गए हैं।

श्री अजय कुमार महावरः अध्यक्ष जी कम से कम हम लोगों का कुछ विषय तो आना चाहिये ना।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। चलिये सौरभ जी। ये विषय आप ही के है ये किसके हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिल्ली में, एक सैकंड, एक सैकंड। दिल्ली में सर्विसिज,

...व्यवधान...

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने नियम 55 में...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मैं, आप बैठ जाइये अब, मैं

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं मैंने चर्चा कोई अलाउ नहीं की है बैठ जाइये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सारा देश ही ईडी के कारण जेल में, सारा देश ही ईडी के कारण जेल में है, कौन बाकी है। बैठिये, मैं कह रहा हूं सारा देश ही ईडी की जेल में है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी चर्चा करिये, आप चालू करिये। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आप बैठ जाइये प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी शुरू करें अब।

माननीय अध्यक्षः आपको इतना मालूम होना चाहिये, अभी कोर्ट के संज्ञान में है वो विषय। बैठ जाइये बस, चलिये। सौरभ जी चालू करिये।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है और हाउस में चर्चा रखने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी ये जो विषय है मुझे लगता है कि ये हाउस के अंदर सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों। अध्यक्ष जी, 2015 में जब हमारी सरकार चुनकर आई थी तब केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन लाई थी और उस नोटिफिकेशन के हवाले से केन्द्र सरकार ने जो सर्विसेज विभाग था यानी की जो अफसरों की ट्रांसफर की, पोस्टिंग की उसको किसको क्या विभाग दिया जायेगा, किसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। किसके ऊपर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जा सकता है। किसके ऊपर क्या डिसिपिलिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ये सारे जो अधिकार थे, केन्द्र सरकार ने एलजी साहब को दे दिये थे दिल्ली के अन्दर। उसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया 2016 में। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया अध्यक्ष जी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पॉच जजों की जो बेंच थी उसने अरविंद केजरीवाल जी के बहुत सारे अधिकार जो है वापस उनको दिये और

सुप्रीम कोर्ट ने कहा "Except Public Order, Police and Land, L.G. is bound by the aid and advice of Kejriwal Government which has public mandate. Real authority to take decisions lies in the hands of elected government. This is the meaning of aid and advice, LG has to act in accordance to the aid and advice of the Cabinet." और अध्यक्ष जी इसके बाद जो सर्विसेज का मामला था उन्होंने दो जजेज की बेंच को दिया जिसके अन्दर जस्टिस ए0के0सिकरी थे, जस्टिस अशोक भूषण थे और 2019 में जब उसका फैसला आया तो उन दोनों जजेज की जो ओपिनियन थी वो अलग–अलग थी। एक जज ने माना कि अधिकार एलजी साहब को होना चाहिए। दूसरे जज ने माना कि अधिकार केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार को होना चाहिए लिहाजा ये मामला दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्दर क्योंकि फिर ये जो है अब फिलहाल उसके बाद ये थ्री जजेज बेंच में गया और उसके बाद ये फाइव जजेज बेंच में गया और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अभी तक इसका डिसीजन नहीं हो पाया। मगर अध्यक्ष जी केन्द्र सरकार इसके अंदर अभी भी अपनी मनमानी करके अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग करती है। यहाँ तक भी ठीक था कि आप अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग करिये। जो अफसर अच्छा काम नहीं कर रहा है आप उसको हटा दीजिए। जो अफसर अच्छा हैं उसको आप लाइए। इसको आप ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार दे सकते हैं एलजी साहब को। अध्यक्ष जी मैंने पिछले दिनों जो सरकार के सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेन्ट्स हैं जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए क्रिटिकल होते हैं। उन डिपार्टमेन्ट्स में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेन्ट होता है। जो उस डिपार्टमेन्ट का प्रमुख सचिव होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उनके ट्रांसफर्स की लिस्ट

निकाली और अध्यक्ष जी जब मैं शुरू में एमएलए बना तो मैं जो ये आईएएस अधिकारी थे इनके नाम सेव करता था। जैसे सीईओ दिल्ली जल बोर्ड है तो मैं सेव करता था सीईओ दिल्ली जल बोर्ड फंला, फंला नाम से। फिर एक-दो साल बाद इनका ट्रांसफर हो जाता था तो मैं उसके आगे लिख देता था ओल्ड और नये वाले के आगे लिख देता था न्यू सीईओ दिल्ली जल बोर्ड। तो फिर खोलने में आसानी होती थी। न्यू का मतलब ये है। फिर ऐसा होने लगा अध्यक्ष जी ये हर साल बदलने लगे। तो फिर मैं अब क्या करता हूं कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एजूकेशन तो मैं उसके आगे 2021 लिखता था। 2021, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एजूकेशन। अब क्या है कि मैंने फोन किया 2022 लिखा हुआ था। 2022 प्रिंसिपल सेक्रेटरी फंला। मैंने उसको फोन किया। मैंने कहाँ, हाँ जी। उन्होंने बोला सर मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मुझे महीने लिखने पड़ते हैं। अब मैं लिखता हूं जून, 2022 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एजूकेशन और ये हालत, अध्यक्ष जी ये हालत किसी ओवरसियर की नहीं है। किसी जूनियर इन्जीनियर की नहीं है। एमसीडी में जूनियर इन्जीयर जो बिल्डिंग डिपार्टमेन्ट के तो वो वही है। सात-सात साल से वही है। मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हायर एजूकेशन मतलब वो डिपार्टमेन्ट जिसको इतनों crosanct माना जाता है जिसको मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई आईएएस अफसर इसके अन्दर आयेगा। इसके अन्दर 6 महीने तो उसको सीखने में लग जाते हैं कि ये डिपार्टमेन्ट में क्या है। क्या करना है और ये जो टेक्नीकल एजूकेशन है, हायर एजूकेशन है। ये वो डिपार्टमेन्ट्स हैं अध्यक्ष जी जो देश का भविष्य बनाते हैं। ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अन्दर देश का भविष्य हर साल जनरेट होता है। अगर आज हिन्दूस्तान का नाम पूरे विश्व में हैं तो वो उन चन्द हिन्दुस्तानियों के नाम से है जिन्होंने

बहुत अच्छी, बड़ी–बड़ी भारत की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। हायर एजूकेशन ली। हायर टेक्नीकल एजूकेशन ली फिर वो बाहर जाकरके गूगल के हेड बने। माईक्रोसाफ्ट के अन्दर उन्होंने काम किया। कोका कोला तक पहुँचे। उन लोगों का नाम जो है वो इसलिए हुआ और हमारे देश का नाम इसलिए हुआ क्योंकि हायर एजूकेशन देश की हायर एजूकेशन इंस्टीट्यूट से वो पढ़कर निकले और आगे उन्होंने नाम किया। अध्यक्ष जी, ये फील्ड इतने कम्पीटेटिव होते हैं कि इनके अन्दर हर साल सिलेबस बदले जाते हैं। मैं अध्यक्ष जी आपको बताउॅ कि जब मैंने इन्जीनियरिंग करी तो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन फील्ड होता था कि जो सबसे अच्छा होता था वो इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन होता था और एक–दो साल में ही कम्प्यूटर साइंस का फील्ड आ गया अध्यक्ष जी। कम्प्यूटर साइंस का फील्ड चल ही रहा था उसके बाद नये फील्ड आ गये अध्यक्ष जी। इन्फार्मेशन साइंस आ गया। इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी करके एक ब्रांच आ गया। आजकल हम पूछते हैं बच्चों से तो आजकल आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स, मशीन लर्निंग ये सारी नई–नई ब्रांचेज आ गयी इन्जीनियरिंग के अन्दर, टेक्नीकल के अन्दर। हायर एजूकेशन के अन्दर भी रोज जो हैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी–बड़ी यूनिवर्सिटीज और एजूकेशन इंस्टीट्यूशन्स के सिलेबस के हिसाब से, इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से, बिजनस की रिक्वायरमेन्ट के हिसाब से, हमारी इकोनामिक पालिसीज के हिसाब से रोज नये बदलाव करने हैं। रोज नये इंस्टीट्यूशन्स खोलने हैं। उनके अन्दर नये कोर्सेज लाने हैं। उनके सिलेबस के अन्दर चेन्जेज करने हैं। बाहर से अच्छे लोगों को अपनी यूनिवर्सिटीज के अन्दर लाना है और इस फील्ड को समझने के लिए आपको 6 महीने लगते हैं और बाकी आप फिर देखते हैं कि एक–दो साल के अन्दर अब जो सरकार का

विजन है और जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आप बदलेंगे। मगर इतने में पता चलता है कि कुछ महीने के अन्दर आपने अफसर बदल दिया अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं एक एक्जाम्पल के तौर, एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक लिस्ट लाया हूं। मैंने पिछले चार साल का ये जून का महीना है तो मैंने बोला जून 2018 से जून, 2022 तक का आप ऑकड़ा दे दीजिये कि इन डिपार्टमेन्टस में कितने बार अफसर बदले गये। तो अध्यक्ष जी मैं आपको बताउँ कि ट्रेनिंग एण्ड टेक्नीकल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजिशन है ये 2018 से एच राजेश प्रसाद आये 24 दिन। 24 दिन बाद ट्रांसफर। डॉ0 जी नागेन्द्र कुमार आये 01 महीना 11 दिन। मतलब कमाल हो गया। मतलब ये कोई केन्द्र सरकार कैसे ऐसा कर सकती है कि वो इतना कंफ्यूज है कि किसी आदमी को लाये और 24 दिनों बाद नहीं-नहीं ये ठीक नहीं है। इसको बदल दिया। नया लाये। फिर 01 महीने 11 दिन में आपने उसको बदल दिया। फिर आप दोबारा लाये देवेन्द्र सिंह निज्जर। आपने उनको 05 महीने 28 दिन में बदल दिया। फिर शिव प्रताप सिंह 08 महीने 09 दिन। जी0नागेन्द्र कुमार 04 महीने 11 दिन। मनीषा सक्सेना 06 महीने। एच राजेश प्रसाद, वो ही जिनको 24 दिन में आपने बदला था उनको अब आप दोबारा ले आये। जैसे ताश नहीं होते। ताश फेंटते रहते हैं। कह रहे हैं ये निकल गया, अच्छा इसको डाल दिया। अच्छा ये निकल गया, ये निकल गया। मतलब ये हायर एजूकेशन का हाल। मतलब दुनिया का कोई जो है एडमिनिस्ट्रेसनिंग का आदमी अगर ये कहे कि इसके अन्दर कोई लॉजिक है। कोई आदमी इसके अन्दर जो है दिमाग लगाकरके सोचता है कि इसके अन्दर क्या कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं और ये सरकार चला रहे हैं। देश की राजधानी की सरकार के ट्रांसफर, पोस्टिंग हायर एजूकेशन

डिपार्टमेन्ट के इस तरीके से होते हैं। एच राजेश प्रसाद वापस आये। 06 महीने 25 दिन। इनके साथ भी ज्यादा नहीं। सिर्फ 06 महीने 25 दिन। एस0वी0 दीपक कुमार 05 महीने 28 दिन। अब एक नई आयी हैं। आर0एल0एस0वाज0 ये 09 महीने 09 दिन से टिकी हुई हैं अध्यक्ष जी। मुझे लग रहा है अभी तक का ये मुबारकबाद की हकदार है क्योंकि ये 09 महीने इन्होंने पूरे किये वरना तो सब जो है मैक्सिमम जो गया था अभी तक स्कोर यहाँ पर 08 महीने 09 दिन का गया था। ये हालात है। ये भी हो सकता हैं कि अब जो वहाँ पर जो है इनको, अब मैं आपको डाइरेक्टर का बताऊँ। टेक्नीकल और ट्रेनिंग एजूकेशन डिपार्टमेन्ट डाइरेक्टर गरिमा गुप्ता 02 महीने 08 दिन। वीरेन्द्र कुमार 03 महीने 12 दिन। देवेन्द्र सिंह 03 महीने 26 दिन। एस0एस0गिल 01 साल 06 महीने। अजीमुल हक 11 महीने 16 दिन। रंजना देशवाल 10 महीने 08 दिन। अब एच0पी0एस0सरन 22 दिन।... अब ये भी लिंक ऑफिसर है। हॉ सर, ये लिंक ऑफिसर है। इनको अभी परमानेन्ट चार्ज नहीं दिया। अध्यक्ष जी, यही हाल जो हैं हायर एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का है कि मतलब, मतलब या तो वो लूडो खेलते हैं। कहते हैं अब इसका आ गया। चलो इसको कर दो। मतलब क्या, मतलब हैरानी की बात है कि इसके ऊपर इनको क्या बोला जाये और ये वो डिपार्टमेन्टस हैं जिनके ऊपर पूरे देश का, पूरे एक राज्य का जो एजूकेशन सिस्टम है जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो डिपेन्ड करता है। तो मैं आपको बता रहा था चार साल में इन्होंने 09 लोगों के ट्रांसफर कर दिये। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पर। और डाइरेक्टर की पोस्ट पर चार सालों में इन्होंने सात लोगों के ट्रांसफर कर दिये। सेम जो है इनका दूसरे डिपार्टमेन्टस के अन्दर रवैया है। तो अध्यक्ष जी मेरा इस सदन की तरफ से जो भी हमारे अथार्टीज हैं जो इन ट्रांसफर को करते

है। कहा जाता है कि एलजी साहब करते हैं। मगर जो भी एलजी साहब करते हैं या जो भी इनके पीछे करते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि कम से कम इन डिपार्टमेन्ट्स को तो उनको बख्शना चाहिए। मतलब ये तो बहुत पवित्र डिपार्टमेन्ट्स हैं जिसके अन्दर सालों की जो है विजन तैयार होती है देश की उसके अन्दर आप अगर इस तरीके से अगर ट्रांसफर करेंगे। कल को भविष्य के अन्दर ये सारी की सारी चीजें रिकार्ड हो रही है। लोग हंसेंगे हम पर कि एक ऐसी भी सरकार दिल्ली के अन्दर चली थी जहाँ पर एलजी को पावर्स केन्द्र सरकार ने दे दी थी और एलजी साहब हर दो महीने के अन्दर हायर एजूकेशन डाइरेक्टर ही चेन्ज कर देते थे। तो अध्यक्ष जी मेरी तरफ से हाउस के आगे ये डिसकसन शुरू की गयी है और मैं चाहता हूं कि ये हाउस जो है इसके ऊपर चर्चा करे और इस हाउस से कोई मेसेज जो है संवेदना भरा एक मेसेज जो है एलजी ऑफिस को जाये कि ये जो चीज है ये हमारे पूरे के पूरे भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद स्पीकर साहब।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मौके पर इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। 1966 से 1990 तक दिल्ली की इस विधान सभा का स्वरूप कुछ और था। तब वहाँ दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउन्सिल हुआ करती थी और दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउन्सिल के पास अधिकार था केवल एडवाइज करने का। जिस काउन्सिल को हेड करते थे चीफ एक्जीक्यूटिव काउन्सिल। एडवाइज करनी होती थी एलजी को और एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का

इस्तेमाल कर सकते थे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए और दिल्ली के स्वरूप को देखते हुए जो एक बार नेशनल कैपिटल टेरिटोरी भी है। तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के चुने हुए लोगों की सरकार को और ज्यादा पावर देने के लिए एसेम्बली का गठन करने की सोची और 1991 में कांस्टीट्यूशन में एमेन्डमेन्ट करते हुए दिल्ली लेजिस्लेटिव एसेम्बली का सिस्टम तैयार किया। जिसके 70 विध ायक होने थे जो आज भी है। पावर थी कि वो एड और एडवाइज नहीं करेंगे बल्कि पूरी ताकत रखेंगे सरकार को चलाने dsand LG will be bound to go through the aid and advice of the Govt. as is said by the Saurabh Bhardwaj ji 2018 में कांस्टीट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की ने बड़ा क्लीयरली कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार कि एड एण्ड एडवाइज को एलजी मानने के लिए बाधय हैं और दोनों आपस में मिलकरके हार्मोनियसली काम करेंगे। इसके बाद लगातार ये सरकार जो केन्द्र में बैठी है वो दिल्ली की सरकार को किसी न किसी बहाने तंग करती आयी है। जो सिलसिला इन्होंने 2015 में शुरू किया। 2015 में एक बहुत बड़ा मैन्डेट आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला था जिन्होंने आते ही अगर आपको याद दिला दूं मैं विनोद नाम का एक कांस्टेबल जो शराब माफिया से यहाँ शुरू होती है ब्यूरोक्रेट्स की अपनी पावर और गवर्नमेन्ट की अपनी पावर।

विनोद नाम का एक सिपाही उन शराबी माफियाओं से लड़ते हुए आया नगर के जंगलों में मारा गया, शहीद हो गया। इससे पहले लोग नार्मली सिलाई की मशीन या विडो को कोई हल्का फुल्का चेक देते थे पर ये दिल्ली की पहली सरकार थी जिस सरकार ने एक करोड़ रूपये का अनुदान उस सिपाही

के परिवार को दिया क्योंकि उन्हें लगा वो कर्तव्य निष्ठा में उसने जान गंवाई है और वो करप्शन के खिलाफ लड़ा है। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई से घबराकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे अभी सौरभ भाई ने कहा 2015 में सर्विस खींच ली। एक नोटिफिकेशन के द्वारा चुनी हुई सरकार से सर्विसिस ले ली और ये कहते हुए ले ली कि सर्विसिस पे अब कंट्रोल हमारा रहेगा। ये constitutional amendment नहीं था। इसके बाद ये कानूनी लड़ाई लगातार अब तक जारी है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके बीच में दिल्ली हाईकोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस भी रहे, एक्टिव चीफ जस्टिस थे जस्टिस अर्जुन सिकरी जी, सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने अपने डिविजन बेंच थी दो जजिज की। उनका हालांकि व्यू इसके अगेंस्ट था पर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चुनी हुई सरकार के पास अधिकार ही न हों। और तब उन्होंने कहा था कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के जो 239एए में हैं पब्लिक आर्डर, पुलिस एंड लैंड इनको छोड़ के दिल्ली की सरकार के पास ये अधिकार हैं और ये अधिकार का ऑनर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2018 के बाद 2019 की वर्डिक्ट ने एक तरफ से एक नया सिलसिला, एक नई लड़ाई शुरू कर दी जिसके रहते हुए पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया। इसे छीनने के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो हालांकि पब्लिक के इंटरस्ट में होना चाहिए, लोगों के इंटरस्ट को ध्यान में देते हुए, लोगों की काबिलियत और उनके इंटरस्ट को देख के होना चाहिए, यहां सरकार ने कर लिया कि जो उनके हिसाब से काम करेगा वो पोस्टिंग पे रहेगा, जो नहीं करेगा वो रास्ता देखेगा। यही कारण था कि लगातार एक महीना, दो महीना, तीन महीना में ये ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहीं और

इसी के तहत अफसरों ने अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो अमूमन हम यहां विधान सभा में बैठे हुए कई बार ऑफिसर्स के जो सर्विस डिपार्टमेंट है, लैंड है, पुलिस है उसके बारे में कभी कभी हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की। वहां से जवाब आता है रिजर्व सब्जेक्ट। मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूं यहां बैठके कि एलजी को तो तनख्वाह हम देते हैं, ये दिल्ली के लोग देते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट के थ्रू जा रहा है, सवा दो लाख रूपये से ज्यादा तनख्वाह है और कई लाख रूपये पर्क्स के रूप में, अगर देखें तो शायद हो सकता है करोड़ों रूपये का खर्चा होगा। जितने ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं चाहे वो सर्विसिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हों, सब दिल्ली सरकार पैसे दे रही है पुलिस को छोड़ दो। पर ये डिपार्टमेंट जो बार बार दिल्ली सरकार के मातहत काम करते हुए भी सर हम administrative control की बात ही नहीं कर रहे, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कौन करेगा वो नोटिफिकेशन जायज है, नहीं जायज है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाईड कर लेगा हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या आप उसके बारे में बताना पसंद नहीं करते। अगर लोग जानना चाहते हैं तो क्या आप नहीं बताएंगे। और लोग कौन हैं चुनी हुई सरकार के चुने हुए नुमाइंदे। हम लोग कानून के मुताबिक वो जो 239एए है, जो constitution में amendment है उसके द्वारा चुने हुए हम लोग हैं आप केवल एक नोटिफिकेशन का बहाना लगाके एलजी साहब की छत्रछाया में हर सवाल का जवाब देने से बचते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर जवाब दिया तो जवाब में नुक्ताचीनी की गुंजाइश रहेगी, आपसे पूछताछ करेंगे हम। यही कारण है कि विधान सभा की, अब आप विधान सभा देखिए, विधान सभा की जितनी कमेटियां हैं विधान

सभा की कमेटिज़ को same powers and privilege हैं जो हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को हैं चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। उनकी कमेटियों को जो पावर हैं वही पावर दिल्ली विधान सभा की सारी समितियां एंज्वाय करते हैं same powers and privilege तब ऐसा क्या है कि सरकार के लोग हमारे यहां से तनख्वाह लेने वाले लोग वहां आ के कहते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट है लिहाजा हम न तो आएंगे, न आपको जवाब देंगे। और इसके उलट हो क्या रहा है 2005 में Right to Information Act आया। Right to Information Act का जन्म हुआ कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, ऑफिसर्स में अकाउंटिबिलिटी हो, करप्शन पे चेक लगे और लोगों की जवाबदेही हो, अफसरों की जवाबदेही हो। कोई भी आदमी एक दस रूपये की एक एप्लीकेशन लगाए और सारी की सारी इंफार्मेशन उसे मिल जाएगी। अगर 10 रूपये में किसी सामान्य व्यक्ति को कोई भी सर्विस वाला ऑफिसर चाहे वो किसी रैंक का हो, कोई ऑफिस हो अगर वो वहां से इंफार्मेशन ले सकता है तो ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मजबूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं ले सकते। वो चाहे विधान सभा का माध्यम हो, चाहे वो विधान सभा की कमेटियों का माध्यम हो, इसका पीछे केवल एक कारण है कि ऐसे लोग जो करप्शन बढ़ा रहे हैं उसको एलजी साहब और सेंट्रल की गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको अभयदान देती है और कहती है आपको कोई जवाब देने की कहीं जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं न, तुम जो चाहे करो। ये उसी की वजह है कि बहुत सारे एरेंट ऑफिसर्स चुने हुए प्रतिनिधियों की चिंता नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो इंफार्मेशन नहीं आएगी, पर इंफार्मेशन तो आएगी अकाउंटबिलिटी तय नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 2015 में जब पहली बार एक हेड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस

के 50 हजार लेते हुए घूस पकड़ा गया था तो ये अरविंद केजरीवाल जी की दिलेर सरकार थी जिन्होंने न उसे केवल गिरफ्तार कराया बल्कि habeas corpus दिल्ली पुलिस ने डाली हाईकोर्ट में तो वहां भी करारा जवाब मिला। उसके बाद अंबानी के खिलाफ वो पहला मुकदमा दर्ज करने की किसी सरकार में अगर हिम्मत हुई तो वो केजरीवाल जी की सरकार थी। ये महोदय उसी के बाद था कि इन्होंने कहा where there is a police station अब उन्होंने कहा कि दिल्ली की एसीपी एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करती थी करप्शन को रोकने की, उन्होंने कहा एफआईआर करने की ताकत इनको है। और जहां एफआईआर हो सकती है वहां तो पुलिस स्टेशन है, और अगर पुलिस स्टेशन है तो सब्जेक्ट भी हमारा है। तो इन्होंने वो छीन ली। छीनी केवल इसलिए कि जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं कहीं दिल्ली सरकार ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार कहीं एक एक करके करप्ट अफसरों को जेल भेजना शुरू न कर दे, तो आपने एसीपी को अपने पास ले लिया, ये सबके सामने है।....

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी, कंक्ल्यूड करिए प्लीज, कंक्ल्यूड करिए।

श्री मदन लालः सर, लोग इसकी चर्चा करते हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर्स तो प्लम पोस्टिंग पाते हैं, आप एक जगह से बढ़िया जगह से हटे, आपको अगली पोस्टिंग पता चलेगा उससे भी ज्यादा अच्छी मिली है। वहां से हटे तो और ज्यादा मिली है और बहुत सारे ऐसे अफसर जो दिल्ली सरकार में ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो मोहताज हैं कि कहीं अच्छी सी जगह नौकरी कर लें जहां वो डिलीवर कर सकते हों, जहां वो लोगों के भले के लिए काम कर सकते हों। सर मैं तो कहता हूं भगवान का शुक्र है ज्यूडिशियरी

पे इनका कंट्रोल नहीं है। नहीं तो ये जज रोज बदलवाया करते। हर बार जब भी देखते कोई और पकड़वाना है उससे पहले जज को बदलते। ये शुक्र है इस देश में judiciary independent है। ये शुक्र है कुछ लोग अब भी ईमानदार हैं जो चाहे महीने भर में ट्रांसफर हो जाते हों, पर वो इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि उनको कौन सी पोस्टिंग चाहिए। मैं सर एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो प्रस्ताव सौरभ भारद्वाज जी ने यहां रखा है मैं उससे सहमत हूं, उसका अनुमोदन करता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस सरकार को इस सरकार से सीख लेना चाहिए कि जिस सरकार ने 500 से ज्यादा सरकारी स्कूल नए कर दिए, 20 हजार से ज्यादा नए क्लासरूम बना दिए, 200 से ज्यादा टीचर्स को सिंगापुर भेज दिया, 350 से ज्यादा कैम्ब्रिज प्रिंसिपल भेज दिए, जिसके स्कूलों में 99.97 रजल्ट आ रहा हो, जिसके सरकारी स्कूलों का नाम अब दुनिया में हो रहा हो उस सरकार को चलाने के बाद भी अगर किसी को संतोष नहीं है और उसको खत्म करना चाहते हैं तो वो भूल जाएं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहां के टीचर्स, यहां के स्टूडेंट्स, यहां के लोग, यहां की सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा न केवल जागरूक है बल्कि प्रयत्नशील है और लगातार कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। सर ये उनको समझना पड़ेगा आज नहीं तो कल ये सिस्टम बदलेगा जरूर, क्योंकि जिंदगी में कभी हमेशा के लिए कोई नहीं आया, ऊपर वाली सरकार जरूर बदलेगी 2024 का इंतजार कर रहे हैं हम। इन्होंने ऊपर वाली। जो सबसे ऊपर हैं वो जरूर देख रहे हैं। बस अब 2024 ये कारपोरेशन के अभी के रजल्ट है जहां दुर्गेश भाई इतने भारी बहुमत से जीते हैं।..

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लालः सर और डरा दिया है। हो सकता है जल्दी इलेक्शन न कराएं। पर कोई बात नहीं, आप लोगों के सिस्टम से, हम सब लोगों के इस सिस्टम से हमें जरूर उम्मीद है कि हम अपनी दिल्ली को और ज्यादा सुंदर, सक्षम सर वो पीछे बात हो रही थी सेलेरी की, दिल्ली में 4 लाख 1 हजार रूपया पर कैपिटा इनकम है जो हिंदुस्तान में सेकिंड हाईएस्ट है। जहां 4 लाख आम लेबर के मतलब आप समझो पर कैपिटा इनकम है। वहां आप 12 हजार से 30 हजार, केवल ये दुर्भावना है और जब जब कंस पैदा हुए हैं उनका अंत जरूर हुआ है, अंत जरूर हुआ है। धन्यवाद सर।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद, श्री जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः थैंक्यू स्पीकर सर। अध्यक्ष जी, कहन नूं ते असी दुनिया दी सब तो वडी डेमोक्रेसी विच रहने हां। इस डेमोक्रेसी दे बारे आज तो लगभग 160 साल पहले अमरीका दे जो तद दे प्रेजिडेंट होंदे सी अब्राहम् लिंकन जी, उनां ने बहुत खूबसुरत इदी परिभाषा दिती सी कि डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट सेल्फ गवर्नमेंट है ते बहुत वारी ए लफ्ज जगह जगह ते कोट होंदा है कि डेमोक्रेसी जो है ओ of the people है for the people है by the people है भई लोक अपनी सरकार आप चुननगे ते औ सरकार चुनी हुई लोकां वास्ते काम करेगी। पर इस डेमोक्रेसी दा किस तरीके इस देश दी राजधानी विच वार वार डेमोक्रेसी नूं खत्म करन दी कोशिश किति जा रही है ओहदे ते आज अपा डिस्कशन कर रहे हां। 1993 विच लेजिस्लेटिव असेम्बली दोबारा अपनी होंद विच आई। 1993 तो लैके ते हुन 2022 तक कई वारी स्टेट विच अलग सरकार होई ते

सेंटर विच अलग सरकार होई। पर जिस तरीके दे हालात आम आदमी पार्टी दी सरकार बनन तो बाद दिल्ली विच होए ने ओ आज तक नहीं होए। ते ओहदी बड़ी साफ साफ वजह वी स्पीकर साहब दिस्दी है कि ए ओ ही दिल्ली है जित्थे बिजली दे बिल जीरो आंदे ने। आज तो पहलां आम आदमी पार्टी दी सरकार होण तो पहलां अपां सारे जानदे आ कि बिजली दा बिल दिल्ली वालिया वास्ते एक बहुत वडी चिंता दा विषय होंदा सी। ए ओही दिल्ली है जित्ते आज पानी दे बिल जीरो आंदे ने। ए ओही दिल्ली है जिदे स्कूलां दी चर्चा आज देश विच ही नहीं पूरी दुनिया विच होंदी ए ते जे अमरीका दी फर्स्ट लेडी इंडिया विजिट करदी है ते इक ताजमहल वेखदी है ते दूसरा कहंदी ए मैनूं दिल्ली दा सरकारी स्कूल वेखनैं। ए ओही दिल्ली है जिदे मोहल्ला क्लिनिक दी चर्चा आज देश दे अलग अलग हिस्यां विच होंदी ए। इस चीज दी ही घबराहट आज देश दी केंद्र सरकार नूं बहुत सता रही है, घबरा रहे ने आम आदमी पार्टी दे इस एजुकेशन, इस सिखिया दे मॉडल तो, इस हेल्थ दे मॉडल तो, ते घबरान वी क्यों न जद तक आम आदमी पार्टी दिल्ली विच सीमत सी तद तक इन्हां दी चिंता वी बहुत सीमत जी सी। रिसेंटली पंजाब दे इलेक्शनां दे नतीजे आए ने 117 विचो 2 सीटां ते आइ ए अध्यक्ष जी बीजेपी जिदी सेंटर विच सरकार है। इस करके घबराहट वध वी जा रही है कि भई ए ते मॉडल सक्सेस होई जा रया है, एनां दा मॉडल फैली जा रया है लोग पसंद करी जा रहे ने क्योंकि लोकां दे कम्मा दी गल करदी है आम आदमी पार्टी। जिस इशु ते अपां गल कर रहे आं अध्यक्ष जी, किस तरीके सरकार कम्म न कर सके, इनु सरकार नूं कमजोर किता जावे, ओहदा इक उदाहरण मैं वीं तुहानुं देन लगां।

जिस तरीके साडे मान जोग साथी सौरभ भारद्वाज जी ने कोड किता, मेरे कोल डाटा पया अध्यक्ष जी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट दे सेक्रेटरी दा, ते 22 मई, 2018 तो लैके 2022 अपां आ गये, 4 साल विच 9 अफसर बदली हो चुके ने अध्यक्ष जी। कहन दा मतलब हर 5 महीने, 6 महीने दे दौरान अफसर बदल दिता जांदा है। जद तक अफसर नूं काम समझ आवे ओदी बदली करदो ताकि काम आगे वद्ध ही न सके। काम तो ही घबराहट है अध्यक्ष जी। जे काम तो घबराहट न होंदी ते करा देन दे एमसीडी दे इलेक्शन। एमसीडी दे इलेक्शन टालन दी लोड ही नहीं शी जे अपने काम दे भरोसा होंदा। कहन दे जी बीजेपी दा मॉडल पसंद है, 15 साल दा एमसीडी का साडा कारजकाल वेख्या ते सानूं वोट दे दो पर वो कहन दी हिम्मत है ही नहीं। इस करके इलेक्शन ही, इलेक्शन अध्यक्ष जी की है, मतलब फेरतो डेमोक्रेसी दा गला घोटया जा रहा है। इलेक्शन न करान तो वडा, शर्मनाक काम कि हो सकदा है। लोका कोल राइट है कि 5 सालां विच एक बारी अपनी सरकार आप चुनों। इस केंद्र सरकार ने भाजपा दी ओ हक वी दिल्लीवालयां दा दिल्ली तो खो लैया। इसतो वद शर्मनाक गल कि हो सकदी है स्पीकर साहब। ट्रांसफर-पोस्टिंग टाइम टू टाइम जो हो रही हैं अपने अफसरां दी, ओदे हालत आपा वेख ही रहया। उसतो अलावा साढे मानजोग साथी मदन लाल जी ने हुन आरटीआई दा जिक्र किता। मैंनू एह दसदे बड़ी खुशी हो रही है कि इस सदन दा जो नेता है देश विच आरटीआई लैके आन वास्ते उस लीडर दा बहुत वडा हाथ है, ते सिर्फ आरटीआई लैके आन वास्ते नहीं, उसतो बाद ओदी जागरूकता, ओदे प्रचार प्रसार, लोकां नूं उदे वास्ते अवेयरनेस कर, अवेयर करन वास्ते उस सदन दे नेता दा हाथ है, ते ए सारी सेना दा ओ सेनापति है। ते आज बदकिस्मती है इस सदन दी कि आज इस

सदन दी बनी कमेटी नूं जो इंर्फोशन एक 10 रूपये दे पेपर दे लई जा सकदी है, आज इस सदन नू देन तो मना करदिता जांदा है। एह इस सदन दी प्रतिष्ठा दा वी सवाल है। इसते वी तुसी संज्ञान जरूर लो। अध्यक्ष जी, जिस तरीके एक नफरत दी भाव, एक नफरत दा भाव आम आदमी पार्टी दो रख्या जा रहा है ओदे तो परहेज करनी चाही दी है। आज दिल्लीवाल्यां दी इस इक बहुत ही जबरदस्त मेंडेट नाल चुनी हुई सरकार ओदी भावना, मैं आखिर विच एक ष्टोयर दे जरिए तुहाडे आगे रखना चाहवां गा कि केंद्र सरकार दा जो अहंकार है, ओ उस अहंकार तो बाहर आवे, बहुत खुबसूरत किसी ने दो लाइनां कहियां ने-

कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतिहा कहां तक है,

अध्यक्ष जी, तुहाडी तवजो चाहवांगा। दिल्लीवालयां दी भावना है अपने प्रधानमंत्री वास्ते।

''कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतिहा कहां तक है,

तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है,

वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी,

हमें तो ये देखना है तू बेवफा कहां तक है।''

थैंक यू स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः भावना गौड़ जी। (अनुपस्थित)। विनय मिश्रा जी।

श्री विनय मिश्राः बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं तो बधाई दूंगा माननीय उप–मुख्यमंत्री– श्री मनीष सिसोदिया जी को, इतनी obstruction के बाद, इतनी रोकटोक के बाद जो आज शिक्षा क्रांति दिल्ली में लेकर आए और आज इसी शिक्षा क्रांति की बदौलत पूरे देश में जितनी सरकारे हैं, आज स्कूल और अस्पताल की बात करने लगी है। इससे पहले किसी के मैनिफेस्टो में, चुनाव मैनिफेस्टो में स्कूल की बात नहीं होती थी, विकास की बात नहीं होती थी लेकिन ये दिल्ली सरकार का कमाल है कि आज जो इन्होंने स्कूल बनाए और कभी जिन स्कूलों की स्थिति जर्जर होती थी, जहां बच्चे एडमिशन लेने से कतराते थे, आज वही स्कूल है जहां बच्चे एडमिशन लेना भी चाहते हैं। और इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि आज सरकारी स्कूल के बच्चे अगर यूपीएससी बतंबा कर रहे हैं तो साथ–साथ हमारे सरकारी स्कूल के टीचर भी यूपीएससी बतंबा कर रहे हैं और आज महिला ने, मेरे को अभी जानकारी आई कि एक स्कूल की टीचर है, जिसका नाम, 48 वां रेंक लेकर, आयुषी डबास, जो दिल्ली सरकार में शिक्षक है, उन्होंने यूपीएससी में 48 वां रेंक हासिल किया तो ये दिल्ली सरकार का कमाल है, दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा क्रांति लाए उसका कमाल है।

मैं, मुझे याद है जब मैं चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार मनीष सर से मिलने गया तो उन्होंने एक बात कही कि हमने जो शिक्षा पर काम किया है, हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर हमने काफी काम किया और लगता है कि वो टेक–ऑफ कर रहा है और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। फिर इन्होंने बात की कि अब हम लोगों को टेक्निकल एजुकेशन और हायर

एजुकेशन पर बात करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे एक विश्वास, जैसे नौजवान को जगता है क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूं, तो मुझे बड़ा विश्वास दिखा उनकी आंखों में। उसके कुछ दिन बाद दिल्ली स्कूल के रिजल्ट आए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, 70 साल के इतिहास में कि सरकारी स्कूल के, दिल्ली के सरकारी स्कूल के 98 परसेंट रिजल्ट, सरकारी स्कूल के बच्चे 98 परसेंट बच्चे बारहवीं और दसवीं में पास हुए। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके अगले दिन देखता हूं कि जो डायरेक्टर थे एजुकेशन के, जिनको इनाम मिलना चाहिए था, उनको इनाम न देकर दिल्ली से सीधा अंडमान फेंक दिया। तो जो अफसर अच्छा काम करें उसको केंद्र सरकार ने सीधा-सीधा मैसेज दे दिया, उसको इशारा कर दिया बाकि अफसरों को उनके माध्यम से कि अगर तुम यहां पर ठीक से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी जगह यहां पर नहीं है, तुम्हारे को दूर-दराज कहीं क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा।

मैंने भी एक डाटा देखा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, तो मेरे पास भी डाटा आया तो मैंने भी देखा, मुझे हैरानी है कि मात्र 4 साल में, 4 साल में नहीं, 18 से 21, 3 साल में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी 5 बदले जा चुके हैं। मैं तो हैरान हूं कि कैसे मनीष सर आप काम करते हैं।

मेरे को लगता है इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये आपको भी ट्रांसफर कर लेते अपने पास और कहते कि जी आ जाओ भाजपा में काम कर दो, भाजपा की सरकार दिल्ली में बना दो। गनीमत है कि आम आदमी पार्टी के लोग ट्रांसफर नहीं होते, नहीं तो कांग्रेस और अगर शिवसेना वाले होते तो हो

सकता है ट्रांसफर होकर जो है इनके पास चले गए होते लेकिन... हां, आप भी गुवाहाटी आ जाओ, अभी बुला लेते।

तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से कहना चाहूंगा आजकल दिल्ली में एक पॉलिटिकल टुरिजम चल रहा है। जो हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार का काम है उस पर एलजी साहब जा-जाकर फोटो खींचा रहे हैं और अफसरों को वहां ले जाकर परेड करा रहे हैं। दिल्ली सरकार जल बोर्ड में तो काम कर ही रही है, स्कूल में तो काम कर ही रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डीडीए का काम देखिए, जब दिल्ली में जो दिल्ली ग्राम सभा की जमीन थी, जब urbanize करके, urbanize village की जमीन डीडीए को ट्रांसफर कर दी गई और आज तमाम ऐसी जमीने हैं जो डीडीए को ट्रांसफर करी गई। आज वहां पर कब्जे हो रहे हैं और जमीन कट-कटकर वहां पर बेचे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार इनसे अगर जमीन मांग ले स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कॉलेज के लिए तो डीडीए के अफसर कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम नहीं देंगे। और वहीं माफिया अगर जाकर कब्जा करे, तो वहां कट रहा है और इनके अफसर आंख मूंदकर सोये हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये भी कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी जगह पर भी जाकर देखें, जो इस तरह के अवैध कब्जे हो रहे हैं, जो डीडीए की जमीन कट रही है, कम से कम वो जमीन बचेगी तो दिल्ली सरकार उस पर भी कुछ प्रोजेक्ट लेकर आएगी, उस पर भी स्कूल बनाएगी, उस पर भी अस्पताल बनाएगी और हमको जमीन देगी। तो मुझे इतना विश्वास है कि दिल्ली सरकार उस पर कुछ न कुछ जरूर विकास कार्य करेगी और वो जमीन जो अवैध लोगों के पास जा रहा है उससे आने वाले बच्चों का भविष्य बन पाएगा।

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया और वाकई में ये जो सर्विसेज का मुद्दा है ये बहुत आज दयनीय स्थिति में आ चुका है और अफसर मनमानी कर रहे हैं हर जगह। आज लूट-खसोट चल रही है और इनको पता है कि इनको एलजी साहब पूरा संरक्षण दे रहे हैं तो मैं एलजी साहब से भी कहूंगा कि इनको संरक्षण न दें और ईमानदार लोगों को दिल्ली में लाएं और दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से काम करने दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री जय भगवान जी।

श्री जय भगवानः आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सौरभ भारद्वाज जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग आज, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और एक मिनी भारत के अंदर हम रहते हैं। मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर जगह-जगह से लोग आकर के बसते हैं। हर राज्य से, हर प्रदेश से दिल्ली के अंदर लोग आये हुए हैं और जो ये जो दिल्ली प्रदेश है ये एक मिनी भारत है और इस मिनी भारत को हम लोग represent कर रहे हैं। और हम सभी माननीय विधायक ये चाहते हैं कि यहां पर विकास कार्य हों और जो दिल्ली है वो आगे बढ़े। तो जो दिल्ली के अंदर भारत के कोने-कोने से लोग आकर के यहां पर बसे हुए हैं और जब दिल्ली का विस्तार हुआ तो अनेक प्रकार की कॉलोनियां, गांव, सेक्टर, अनेक प्रकार की चीजें दिल्ली के अंदर आकर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, फिर जैसे-जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे ही दिल्ली के ऊपर भार बढ़ने लगा। भार बढ़ने लगा तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ने लगी

और उन जरूरतों के हिसाब से जो पहले की जो सरकारें थी, क्योंकि जो पहले की जो केंद्र की जो सरकारें थी उन्होंने लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया नहीं कराएं, जिसकी वजह से देश के कोने-कोने से लोग आकर के दिल्ली के अंदर बसे और दिल्ली के अंदर कॉलोनियों का विस्तार हुआ, सेक्टरों का विस्तार हुआ, गांवों का विस्तार हुआ, लाल डोरे का विस्तार हुआ, ग्राम सभा का विस्तार हुआ, बहुत विस्तार हुआ दिल्ली के अंदर। लेकिन जो विकास का जो विस्तार होना चाहिए था वो कभी नहीं हुआ। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2015 में तो लोगों को सही मायने में विकास दिखने लगा। चाहे मैं बात करूं अनऑथराइज कॉलोनी की, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी की मैं बात करूं, चाहे मैं सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं गांव की बात करूं, उन सभी के अंदर दिल्ली की सरकार ने, चाहे पानी की लाईन की बात करूं मैं, चाहे सीवर लाइन की बात करूं मैं, चाहे गली बनाने की बात करूं मैं, चाहे लाइट लगाने की बात करूं मैं, कैमरा लगाने की बात करूं मैं, वाई-फाई लगाने की बात करूं मैं, अध्यक्ष महोदय, हर कोने में दिल्ली की सरकार ने काम करने की कोशिश की है। कोशिश की है कि दिल्ली विकास के पथ पर भारत में सर्वश्रेष्ठ हो और इस पायदान पर दिल्ली सरकार की कोशिश भी है और हम सब लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो दिल्ली है वो भारत के अंदर बहुत ही सुंदर और अच्छी राजधानी बने, जिसमें हमारी सरकार चाहती है और हम सब लोग मिलकर कार्य भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार ने एजुकेशन के मामले में लगातार नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी

विधान सभा की ही बात करूं तो मेरी विधान सभा के अंदर बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लोग, बच्चे परेशान थे, बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं नहीं होती, वहां क्लासें नहीं थी। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 50 हजार दिल्ली सरकार के द्वारा जो नई क्लासें बनाई गई हैं, नए-नए स्कूल बनाए गए हैं, नई-नई लेबोरेटरी बनाई गई हैं, नए-नए synthetic track बनाए गए बच्चों के खेलने के लिए, खेलकूद के लिए। नए-नए कॉलजों की जगह बनाई गई हैं, कॉलेज बनाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, तो इससे एक मंशा दिखाई देती है कि जो दिल्ली की सरकार है वो विकास करना चाहती है, काम करना चाहती है। तो हम सबको सहयोग करना चाहिए क्योंकि भारत पहले भी विषय गुरू था। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय और अनेक प्रकार के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे, लोग विदेशों से पढ़ने के लिए इस भारत भूमि पर आते थे। वही दिल्ली की सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से हमारे लोग आज विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं और विदेशों के लोग आकर के इस भारत भूमि में, भारत के अंदर आकर के पढ़ें, दिल्ली के अंदर आकर पढ़ें। तो दिल्ली की सरकार बड़ी अच्छी तरीके से मेहनत कर रही है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो अच्छी, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिएं, वो उनको मिलनी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं यहां पर मोहल्ला क्लिनिक की, मैं बात करूं ऑडिटोरियम की, स्विमिंग पूल की मैं बात करूं, लायब्रेरी की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की बात करूं, सिंथेटिक ट्रैक की बात करूं, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो दिल्ली की सरकार ने वो सब कुछ बनाने की कोशिश की है जो लोगों की जरूरतें हैं। हर चीज पे काम करने की कोशिश

की है दिल्ली सरकार ने। बाबा साहब डा. भीम राव अंबेडकर जी जो symbol of knowledge जैसे अमरीका जिसे आज हम विष्य का सबसे ताकतवर देश मानते हैं, लोग कैंब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बाबा साहब डा. भीम राव अंबेडकर जी के नाम से school of excellence पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा खोले गएं। क्यूंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं क्यूंकि आज मैं विधान सभा में बोल रहा हूं कि डा. भीम राव अंबेडकर जी के नाम से हमारी सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी द्वारा डा. भीम राव अंबेडकर जी के नाम से school of excellence के नाम रखे हैं।...

माननीय अध्यक्षः जय भगवान जी, कंक्ल्यूड करिए अब, कंक्ल्यूड करिए, प्लीज।

श्री जय भगवानः छोटा ही बोल रहा हूं सर मैं छोटा ही बोल रहा हूं सर ज्यादा बड़ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो जिस प्रकार से सरकार एजुकेशन के मामले में काम कर रही है हायर एजुकेशन के मामले में काम कर रही है और एलजी साहब के द्वारा बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो सर्विस डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टेक्नीकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके सभी अधिकारियों को और जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सभी को बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी जैसा कि सौरभ भाई दिखा रहे थे कि कई लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्यूंकि अभी मेरे पास लिस्ट है जैसे गरिमा गुप्ता जी दो महीने, वीरेन्द्र कुमार जी तीन

महीने, देवेन्द्र कुमार जी तीन महीने, एस एस गिल जी एक साल, अमाजुल हक जी ये ग्यारह महीने, रंजना देशवाल जी दस महीने और एचपीएस सरन जी ये बाईस दिन। अध्यक्ष महोदय ये क्या हो रहा है कि जो लोग दिल्ली के अंदर विकास चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एजुकेशन के मामले में दिल्ली अग्रणी हो, आगे बढ़े, आम लोग देश का नाम रोशन करें, लेकिन सभी अधिकारियों को बार बार थोड़े थोड़े दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इससे क्या हम लोग क्या महसूस करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार को ये चाहिए कि दिल्ली का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्यूंकि दिल्ली जो है वो मिनी भारत है। जब मिनी भारत के लोग अच्छी तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, दिल्ली एजुकेशन के मामले में नाम रोशन करेगी तो पूरा देश भी नाम रोशन करेगा। जिस प्रकार से दिल्ली के मॉडल को शिक्षा मॉडल को अनेक प्रकार से, अनेक राज्यों के लोग आकर के यहां से देख कर जा रहे हैं जैसे कि अनेक प्रकार के जो हमारे अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर दौरा करके गए हैं, विदेशों से भी, अमरीका के राष्ट्रपति की पत्नी भी यहां पर दौरा करके गयी हैं उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली के जो स्कूल हैं वो इतने बेहतरीन हैं। तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर तानाशाही हो रही है, दिल्ली की सरकार को परेशान किया जा रहा है, माननीय एलजी साहब द्वारा माननीय केन्द्र सरकार के द्वारा चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के हमारे सीईओ हों, चाहे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे हमारे किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बार बार, थोड़े थोड़े दिनों में हटाया जा रहा है,

परेशान किया जा रहा है, दिल्ली के विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये जो तानाशाही चल रही है ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए और माननीय हमारे जो सौरभ भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षः रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। बिधूड़ी जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, कैसे होगा ये?

माननीय अध्यक्षः भई बिधूड़ी जी, अब, समय 5 बजने वाले हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप शॉर्ट बिजनेस डिस्कशन लगाएंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं आप।

माननीय अध्यक्षः अभी 5 बजने वाले हैं। मैं कल समय दे दूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप बिल्कुल ही विपक्ष का गला घोंटना चाहते हैं ये तो ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्षः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये ठीक नहीं है।...

माननीय अध्यक्षः कल समय दे दूंगा मैं आपको।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं...

माननीय अध्यक्षः नहीं, अब...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हाउस में फ्रूटफुल डिस्कशन हो, सरकार रिप्लाई करे, मेंबर्स को बोलने का अवसर मिले।...

माननीय अध्यक्षः देखिए 5 बजने वाले हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये कोई तरीका नहीं है। अब देखिए न।

माननीय अध्यक्षः बोलिए, आप बोलिए

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चीफ व्हिप को बोलने का अवसर दें, वो दो मिनट बोलेंगे उसके बाद फिर।

माननीय अध्यक्षः बोलिए। आप रख लीजिए उनकी बात, मेरी रिक्वेस्ट है। थोड़ा समय का अभाव है, नहीं मैं,

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आपने इनको बुलवाया।

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं, बोलिए आप बोलिए। एक्चुअल में। बोलिए। बिधूड़ी जी, करिए शुरू करिए प्लीज। महावर जी, कल दे देंगे समय आपको पूरा। कल समय दे दूंगा महावर जी को,

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं तो बहुत आपका सम्मान करता हूं अध्यक्ष जी, बहुत तकलीफ है।

माननीय अध्यक्षः मेरा आग्रह मान लीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः बहुत तकलीफ है।

माननीय अध्यक्षः मेरा आग्रह मान लीजिए। बोलिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मेंबर्स को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, नहीं ये तो....

माननीय अध्यक्षः बोलिए, मैं अवसर दे रहा हूं, बोलो न।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, अवसर क्या, अब हमारे...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः आज समय का अभाव है 5 बजने वाले हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः नहीं अब प्लीज। बोलिए। मैंने उनके भी दो नाम काटे हैं। दो नाम उनके भी काटे हैं। दो नाम उनके भी ड्राप किए हैं भईया। बोलिए, बिधूड़ी जी, बोलिए जल्दी। बोलिए प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब लीडर आफ अपोजिशन का समय आप तय कर दीजिए मुझे कितनी देर बोलना है।

माननीय अध्यक्षः बोलिए आप बोलिए अच्छा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं मुझे बता दीजिए मुझे कितनी देर बोलना है।

माननीय अध्यक्षः आप कितनी देर बोलना चाहते हैं बोलो?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः 20 मिनट तो दीजिए न मुझे।

माननीय अध्यक्षः 20 मिनट?

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हां। कमाल है आज आप अन्य विधान सभाओं का आप...

माननीय अध्यक्षः आप 7 मिनट। सेवन मिनट्स बोल लीजिए। 7 मिनट्स।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः 7 मिनट्स का है, फिर आप छोड़ दीजिए, आप कहिए कि बोलिए ही मत।

माननीय अध्यक्षः हर विधायक को 3-3 मिनट, 4-4 मिनट आए हैं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये कोई तरीका थोड़ी न है।

माननीय अध्यक्षः चलिए आप 10 मिनट बोलिए, 5 बजे तक बोलिए, आप करिए शुरू करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं नहीं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, 10 मिनट तक बोलिए आप।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, ये 10 मिनट क्या। ये कोई बात है क्या।

माननीय अध्यक्षः नहीं, 5 बजे और इससे ज्यादा क्या होगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः तो आपमुझे कम से कम 15 मिनट का समय दीजिए। जैसे आप मुझे देते रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः ऐसा है अगर नियम बनवाना है मेरे से फिर संख्या के अनुसार मैं समय तय कर दूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं नियम अन्य अन्य प्रदेशों में तो नियम है कि...

माननीय अध्यक्षः नहीं नियम फिर मैंसमय के अनुसार नियम तय कर दूंगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अध्यक्ष जी, मैं तैयार हूं। अन्य प्रदेशों में लीडर आफ अपोजिशन के लिए जो भी नियम हैं वो आप मेरे पे लागू करें।

माननीय अध्यक्षः आप करिए, अब समय न खराब करिए, प्लीज। करिए। करिए, करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव लाए हैं, सौरभ जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका जो प्रस्ताव है वो सच्चाई से परे है। मैं रिपीट कर देता हूं। माननीय सौरभ भारद्वाज जी हमारे बहुत ही अच्छे इस हाउस के मेंबर हैं लेकिन उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव में सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को सीधे सीधे भाजपा विधायक दल की ओर से रिजेक्ट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देखो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई देखिए डिस्टर्ब न करिए, लंबा समय हो जाएगा। उनको बोलने दें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनने का भी माद्दा रखो मैंने तो बहुत सुना है।

माननीय अध्यक्षः अब क्यों, प्लीज। अब कोई बोलेगा नहीं।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः हमारी केन्द्र सरकार जिसका नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना के रूप में एक शानदार एलजी दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जितने भी दिल्ली के...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई ये चीज नहीं चलेगी। ऐसे तो नहीं काम चलेगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं आज...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई राजेश जी, प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः सदन अच्छा चल रहा है गड़बड़ हो जाएगा।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः और मैं ये कह सकता हूं...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब देखिए।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अब बताइए। अध्यक्ष जी, मैंने किसी की निंदा तो नहीं करी है।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी, प्लीज।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैंने कोई आरोप नहीं लगाया।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद जितने भी उप राज्यपाल आए हैं मैं ये कह सकता हूं कि आज मैं ये कह रहा हूं कि ये शानदार उप राज्यपाल हैं दिल्ली के लिए और कल ये बात आम आदमी पार्टी के नेता भी कहेंगे। मैं आज कह रहा हूं विश्वास के साथ। आदरणीय अध्यक्ष जी, उप राज्यपाल...

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये।

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, उप राज्यपाल पूरी दिल्ली के प्रशासक हैं। उप राज्यपाल दिल्ली के गार्जियन हैं और दिल्ली की जनता की तकलीफों से वो वाकिफ हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस हाऊस में ये कहा गया है बहुत हैरानी की बात है...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं ये कहता हूं कि इस हाऊस में किस तरह की...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप चुप रहिए भई आप चुप रहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई मुझे नहीं पसंद आ रही ये चीज। मैं बहुत हकीकत में बोल रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं ये टीका टिप्पणी बंद करें। पूरा दिन सदन अच्छा चला है सदन का अंत अच्छा होने दें।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को ये मालूम होना चाहिए कि लैंड, लॉ एंड आर्डर और सर्विसिस केंद्र सरकार के अधीन हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः उनको बोलने दो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः तो माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अगर मेरे द्वारा कही गयी बात अगर गलत होगी मैं खड़ा होकर माफी मांगूगा। आदरणीय अध्यक्ष जी,...

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः ये क्या ये देखिए, तरीका है क्या। क्या तरीका है ये?

...व्यवधान...

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं ये सुनने को तैयार नहीं हैं। मैंने इनको किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये तरीका नहीं है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः दिलीप जी, रोकिए ये ठीक नहीं है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं इस सदन में कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कि कृप्या करके गलतबयानी करना बंद करें। लैंड, लॉ एंड आर्डर, सर्विसिस केंद्र सरकार के पास है और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील में गए हैं नहीं गए हैं उस फैसले के खिलाफ? क्यूं गए हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में? आपने सर्विसिस मांगी है, ये सच्चाई है। आपको नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे अभी।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः जवाब दें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अरे भई माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे या नहीं देंगे, मुझे समझ नहीं आती बात। आपने उत्तर देना है तो आप दे दीजिए। माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं उत्तर देने के लिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं कृप्या करके सुप्रीम कोर्ट के इंतजार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें। मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पाल्यूशन की। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पाल्यूटिड कैपिटल है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। यदि आज दिल्ली के ऑनरेबल एलजी पाल्यूशन को लेकर चिंतित हैं, दिल्ली में पाल्यूशन कैसे कम हो, तो क्या हमें दिल्ली के उप राज्यपाल को बधाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्या भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफिरल रोड बना कर 60 हजार ट्रक्स की रोज एंट्री होती थी दिल्ली प्रदूषित होती थी, एंट्री बैन कर दी, एंट्री रूक गयी तो क्या पाल्यूशन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया क्या?

आज मेरे बदरपुर विधान सभा क्षेत्र में पोलूशन को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ईको पार्क बनाया जा रहा है 885 एकड़ जमीन पर और दुनिया का सैकेंड लारजेस्ट ईको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयार्क में हैं। क्या

इसके लिए हमें केन्द्र सरकार को बधाई देनी चाहिए, नहीं चाहिए और उसी काम को लेकर दिल्ली के ऑनरेबल एल.जी. आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग तो कहते थे कि दिल्ली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। आज यदि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चाहे वो डीडीए के अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो लैंड के रोबर्स के साथ मिलकर सैकड़ो करोड़ रुपए की जमीन को लूट रहे थे। अगर दिल्ली के ऑनरेबल एल.जी. ने उनके खिलाफ एक्शन किया है, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उनको और इस हाउस को बधाई देनी चाहिए। क्या मालूम नहीं हैं हमारे माननीय सौरभ जी को कि उनके, उनकी शिकायत पर भी एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई है। बताएं क्या दिल्ली के एल.जी. ने जो मुद्दा सौरभ जी उठाते रहे, यदि उसके अधिकार के खिलाफ कार्रवाई करके सौरभ जी की इच्छा को पूरा किया है तो सौरभ जी क्या हमको बधाई नहीं देनी चाहिए एल.जी. साहब को।

आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के उपराज्यपाल एन.डी.एम.सी. एरिया में भी गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल जिस दिन उन्होंने उपराज्यपाल की शपथ ली है, उसी दिन वो दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं राज निवास में कम रहूंगा, दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा लोगों को दिखाई दूंगा। क्या यह हमारे लिए खुशी का विषय है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, डीडीए के ऊपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर कंट्रोल नहीं है। डीडीए केन्द्र सरकार के अधीन हैं। गोविन्दपुरी में झुग्गी–झोपड़ी के लोगों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की जो योजना ''जहां झुग्गी, वहीं मकान'' बनाकर देंगे। यदि जो "लैट बनाये गए हैं,

जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई, उस क्वालिटी में अगर खराबी पायी गयी तो मैं दिल्ली के एल.जी. को बधाई देना चाहता हूं कि वो मौके पर गये और डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन किया, उनको सस्पेंड किया। क्या आप भीनहीं चाहते हो कि दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो। ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या आपको नहीं मालूम है ऑनरेबल डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं। दिल्ली की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की योजना हो, चाहे डीटीसी को जो डेढ़ सौ इलेक्ट्रिक बसें दी हैं केन्द्र सरकार ने या जल बोर्ड को जो आर्थिक सहायता दी है और यदि दिल्ली के लोग एक एक बून्द पानी के लिए तरस रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करके यदि वो पीने के पानी की समस्या का समाधान ढूढ़ रहे हैं तो क्या हमें दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय नेता, प्रतिपक्षः देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः चलिये आप बोलते रहिए।

माननीय नेता प्रतिपक्षः अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बंदना जी ये मुझे देखना अब।

माननीय नेता प्रतिपक्षः अब समय भी ये तय करेंगे मेरे लिए आदरणीय अध्यक्ष जी वो आप ही तय कर दें।

माननीय अध्यक्षः मैं बोल तो रहा हूं, आप बोलिए न।

माननीय नेता प्रतिपक्षः मैं तो बहुत सम्मान करता हूं आपका।

माननीय अध्यक्षः मैंने रोका तो नहीं आपको। टाईम खराब हो रहा बोलिए, आप बोलिए।

माननीय नेता प्रतिपक्षः आपकी काबिलियत पर, आप की शराफत इंसानियत पर मुझे नाज है, लेकिन ये हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स जो हैं, अरे यार हम आपको झेल रहे हैं। आप...

...व्यवधान....

माननीय नेता प्रतिपक्षः क्या हैं आप क्या।

...व्यवधान....

माननीय नेता, प्रतिपक्षः ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं गहलौत साहब।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए।

माननीय नेता प्रतिपक्षः अध्यक्ष जी दर्जनों गांव नजफगढ़ के आस-पास रावता और उसके साथ दर्जनों गांव कई सालों से बरसात के पानी में डूब जाते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि हरियाणा सरकार की जो तीन ड्रेन्स हैं, उनका पानी भी हमारे खेती-बाड़ी की जमीन में आकर उनको बर्बाद कर रहा है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि जो हमारी अन-अथोराइज कॉलोनिज हैं, उनमें आप क्योंकि ड्रेनेज की ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, वो गंदा पानी भी हमारी उन गांवों में आ रहा है। यदि दिल्ली के उपराज्यपाल उन दर्जनों गांव में जाकर किसानों के बीच में और उनके आंसू जाकर पूछते हैं और किसान प्रसन्न होकर

उनको पगड़ी पहनाते हैं तो क्या ये हमारे लिए सम्मान की बात है या नहीं है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। आज एल.जी. साहब के ऊपर सवाल उठ रहा है। आपने पिछली बार कहा था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुल प्रह्लादपुर का जो अंडर पास है, उसमें हम बरसाती पानी को नहीं रूकने देंगे। पिछली बार एक व्यक्ति महरौली-बदरपुर रोड इतनी, इतनी बिजी सड़क है। लाखों वाहन सुबह से लेकर शाम तक मथुरा रोड से लेकर साकेत, महरौली गुड़गांव की तरफ जाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक नहीं दर्जनों बार ये कहा कि इस बार 2022 की जब बरसात आएगी हम प्रह्लादपुर के अंडरपास में पानी इक्ट्ठा नहीं होने देंगे। ट्रैफिक नहीं रूकेगा।

अध्यक्ष जी, पिछली बार भी एक व्यक्ति की मौत हुई और इस बार इस बरसात से पहले थोड़ी सी बरसात हुई। एक व्यक्ति पहले डूब कर मर गया और अभी जो बरसात हुई, पूरा अंडरपास बंद हो गया और यदि दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए। अधिकारी अगर इनकी बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो चिंता करें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के आदेश की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आदेश की। अगर वो पूरा करवा रहे हैं तो क्या इस दिल्ली के लें"टनेंट गवर्नर को हमको बधाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं। आज गंभीरता से बात हो।

माननीय अध्यक्षः बिधूड़ी जी 15 मिनट।

माननीय नेता प्रतिपक्षः जी।

माननीय अध्यक्षः 15 मिनट हो गए हैं। बैठिए प्लीज। कंक्लूड करिये। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी सारी बातें रख दी।

माननीय नेता प्रतिपक्षः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। कर रहा हूं। अरे मैंने तो बहुत कुछ सुना है आपका।

माननीय अध्यक्षः चलिए, चलिए अब हो गया।

माननीय नेता प्रतिपक्षः मैंने तो ये भी सुना है अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे। मेरे समाज के नेता भी हैं और 2024 आ रहा है, मालूम हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारे पास लोक सभा में एक सीट थी वो भी तुम्हारी चली गयी। तुम 2024 की बात कर रहे हो। तुम 2024 की। वो क्या बोलते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल। क्या बोलते हैं : ये मुंह और मसूर की दाल, अरे वाह।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। प्लीज।

माननीय नेता प्रतिपक्षः लोक सभा में एक मेम्बर नहीं हैं और चले हैं, चले हैं। सूत न कपास और अम्मा चली.... लट्ठम लट्ठा हो रही है न अब तो। सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी, अभी तो।

...व्यवधान...

माननीय नेता प्रतिपक्षः अरे हमसे तुम्हारी लट्ठम लट्ठा नहीं है। लट्ठम लट्ठा तो अभी होगी तुम्हारे साथ।

माननीय अध्यक्षः चलिये, चलिये बिधूड़ी जी।

माननीय नेता प्रतिपक्षः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः हो गया, बैठिए, बैठिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राजेश जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये प्लीज। ऋतुराज जी बैठिये। राजेश जी क्या हो रहा है ये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये।

माननीय नेता प्रतिपक्षः खत्म कर रहा हूं न। समअप कर रहा हूं। मुझे मेरी बात समाप्त तो करने देंगे न।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये लोग... बैठिये, बैठिये, बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः राजेश... माननीय विधायकों से प्रार्थना है बैठे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी बैठिये, प्लीज बैठिये। हो गया। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः ये सदन का समय खराब हो रहा है। अब बिधूड़ी जी कंक्लूड करिये।

माननीय नेता प्रतिपक्षः सर समअप कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः हां कंक्लूड करिये।

माननीय नेता प्रतिपक्षः मैं अंत में आदरणीय अध्यक्ष महोदय यह कह रहा हूं कि दिल्ली को एक बहुत ही ईमानदार, योग्य उपराज्यपाल, केन्द्र की मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को दिया है। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी ओर से और अपने सभी विधायकों की ओर से इस थोड़े से समय में जिस मेहनत और लग्न के साथ वो दिल्ली की सेवा करने में जुटे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और क्योंकि वो दिल्ली के प्रशासक हैं। दिल्ली यूनियन टेरोटरी है वो लॉ एंड आर्डर भी देखेंगे वो सर्विसेस भी देखेंगे, लैंड भी देखेंगे और जो दिल्ली सरकार के ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं क्योंकि इसमें हमारी केन्द्र सरकार का भी योगदान हैं, उनको भी मॉनिटर करेंगे। मैं आज स्पज़्ट कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप-मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः अब जरा शांत हो जाएं प्लीज।

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः बहुत बहुत,

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई आपसी बातचीत बंद करिये। माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

माननीय उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सौरभ भारद्वाज जी का एक कंसर्न उन्होंने उठाया है सदन के सामने और उस पर एक वो प्रस्ताव लेकर आए। उस प्रस्ताव के संबंध में कई सारे साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने एक बहुत सीरियस मुद्दे को उठाया है और मैं समझता हूं उस मुद्दे की सीरियसनेस को बनाये रखना जरूरी है। पर, उसकी चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक लाइन कही मैं उसी पर थोड़ा सा बोल देता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा, मूल मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि कल ये बात आम आदमी पार्टी वाले भी मानेंगे कि वी.के. सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। मैं कह रहा हूं कि कल क्यूं मान ले, हम तो आज ही मान लेते हैं। वी.के. सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, ग्रेट।

अब मुद्दे पर बात करते हैं। इन्होंने 15 मिनट सदन के खराब किये ये सिद्ध करने में कि वी.के. सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। हम तो एक सेकेंड में कह दे रहे हैं कि वी.के. सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। अब आगे आ जाओ, अब आगे आकर बात करते हैं।

हम ये भी मानते हैं कि संविधान के... नहीं ये तो अच्छे हैं ही, ये तो जगह गलत बैठे हैं नहीं तो आदमी बहुत अच्छे हैं और कभी बैठेंगे। कल

ये भी मानेंगे कि जगह इधर अच्छी वैसे थी, तो अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल जानते हैं और मानते हैं इस बात को सब कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत् लैंड, पुलिस और पब्लिक आर्डर तीन शब्द कानून में लिखे हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। ये संविधान ने केन्द्र सरकार के पास रखे हैं रिजर्व बाकी सारे सब्जेक्ट दिल्ली की, इस विधान सभा और इससे चुनी हुई सरकार, इससे निकली हुई सरकार को दिए हैं। लेकिन बहुत बेशर्मी से, बहुत असंवैधानिक तरीके से बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूदा केन्द्र सरकार ने, ऐसा नहीं है कि देश में संविधान 2016 या 15 में लागू हुआ। जब से दिल्ली की ये विधान सभा बनी तब से ये संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन 2015 में असंवैधानिक तरीके से केन्द्र सरकार ने सर्विसेस अपने अधीन ले लिया। ये सर्विसेस अपने अधीन लेने का मतलब तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता लोगों को। एक एक चपरासी की भी, अधिकारी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने का दायरा जबर्दस्ती छीन लिया चुनी हुई सरकार से, वो मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में है और हम भी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, टाइम लग सकता है लेकिन पूरा भरोसा है। अब बात आगे करते हैं उस पर तो चर्चा ही नहीं थी। सौरभ जी ने जिस बात को ध्यान दिलाया के जी केन्द्र सरकार द्वारा असंवैधानिक रूप से छीन लिये गये अधिकार का दुरूपयोग करते हुये केन्द्र सरकार जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह से रोज़ाना अधिकारियों को इधर से उधर उछाल रही है। सौरभ जी ने जो मुद्दा उठाया कि केन्द्र सरकार की इस ताश के पत्ते की तरह से हर दो-तीन महीने में हर दो-तीन महीने में अधिकारियों को फेंटने की अब उसके उनके क्या कारण हैं वो वो जानें पर फेंट तो रहे हैं कागज़ पर

लिखा हुआ है। उस फेंटने की वज़ह से सबसे ज्यादा नुकसान हॉयर और टैक्निकल एजुकेशन को हुआ है ये मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में यहां इस सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ इसलिये मैं उनसे सहमत हूँ। सर्विसिज़ को असंवैध ानिक तरीके से छीन लिये जाने का चुनी हुई सरकार के द्वारा सर्विसिज़ यानि की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को असंवैधानिक तरीके से छिन लिये जाने का सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के हॉयर एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन को हुआ है, मैं ये बात सौरभ जी की बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूँ और मैं उनसे इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो बात रखी कि किस तरह से अधिकारियों को ट्रांसफर, पोस्टिंग किया गया कैसे, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भई सुप्रीम कोर्ट में अभी सर्विस, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आयेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको भी इंतज़ार है हमको भी इंतज़ार है, हमीं उसमें गये हुये हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस दुरूपयोग पूर्ण चुनौती का फायदा उठाते हुये आपने जो कुकर्म किये हैं ज़रा उन कुकर्मों को देख लो। आपने उच्च शिक्षा को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने तकनीकी शिक्षा को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कैसे। उच्च शिक्षा का मतलब और तकनीकी शिक्षा का मतलब है यूनिवर्सिटीज़ वाली शिक्षा, उसका मतलब है आई.टी.आई. वाली शिक्षा, डिप्लोमा-डिग्री वाली शिक्षा, उसका मतलब है स्कील ट्रेनिंग वाली शिक्षा ये सारी की सारी शिक्षा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के दायरे में आती है। हॉयर एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन के दायरे में आती है। संविधान के तहत हॉयर एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन देने की जिम्मेदारी यहां मुख्यमंत्री जी की है, चुनी हुई सरकार की है लेकिन इन्होंने संविधान का मज़ाक बनाते हुये सर्विसिज़ छीन कर उसको बरबाद करने

में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत योजना बनाई है नई यूनिवर्सिटी खोलने से लेकर पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में सीट बढ़ाने से लेकर नये कैम्पस से बनाने से लेकर नये-नये तरीके के एडवांस लैवल के कोर्सिज़ तैयार करना स्कील के ऐसे-ऐसे सेन्टर्स तैयार करना वर्ल्ड क्लास स्कील सेन्टर तैयार करना जहां से बच्चों को तुरंत नौकरी मिलने लगे। रिसर्च बड़े-बड़े सैक्टर में कराने की, सब योजना बनाई हैं और उस पर काम कर रहे हैं लेकिन इन्होंने सर्विसिज़ छीनकर बार-बार ये कहने की कोशिश की है करके दिखाओ, हम तुम्हें करने ही नहीं देंगे हम तुम्हारे डायरेक्टर ट्रांसफर कर देंगे। अब मज़ाक ये बन गया है मैं शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत जिम्मेदारी से इस सदन के सामने ये बात रखना चाहता हूँ सौरभ भाई से सहमत होते हुये कि मैं शाम को किसी डायरेक्टर से बात करके जाता हूँ कि भाई नई यूनिवर्सिटी खोलनी है पुरानी यूनिवर्सिटी में ये करना है रिसर्च का ये प्रोग्राम चलाना है ये नया पाठ्यक्रम लेकर आना है अपने टीचर्स को इतना करना है अगली सुबह एल.जी. साहब उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब साल दो साल में ट्रांसफर हो तो मानते हैं। दो साल इनके केन्द्र के नियम भी कहते हैं देशभर में अधिकारियों को ट्रांसफर करने के लेकिन अच्छा कभी किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया जी ठीक काम नहीं कर रहा था शिक्षा का बेड़ागर्क कर दिया कोई गड़बड़ कर दी हटाओ उसको, सर्विसिज़ अभी आपके पास है सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है मतलब सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतज़ार है आपने असंवैधानिक तरीके से छीन रखी है उस व्यवस्था के तहत सर्विसिज़ आपके पास है लेकिन सर्विसिज़ में खुदा थोड़ी हो तुम। पूछा तो जायेगा आपसे कि भई क्यों ट्रांसफर किया। आप 2 महीने में एक डायरेक्टर को ट्रांसफर कर देते हो 3 महीने में एक सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देते हो, 8-10 महीने

सालभर में आपने कभी एक 4-5 साल में एक बार कोई ऐसा ट्रांसफर किया मान लिया कोई गड़बड़ की होगी अधिकारी ने या कोई अक्षम होगा कोई कारण हो गया होगा, ऐसा क्या कारण है कि हर 2 महीने बाद हर 3 महीने बाद आप डायरेक्टर हटा देते हो हर 3 महीने बाद आप सेक्रेटरी हटा देते हो। सवाल तो ये सदन इस बात पर कर रहा है और दुनियाभर की जहान की कहानियां सुनासुना कर इस सदन को और सदन के कार्यवाही देख रहे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई बस धन्यवाद दो दे दो सारे धन्यवाद बहुत अच्छे आदमी हैं अब बात करो क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं इतने, हर 2 महीने में ट्रांसफर करने की वजह क्या है ये बताओ। कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा होगा भई हॉयर एजुकेशन का डायरेक्टर हो सकता है हॉयर एजुकेशन पर अच्छा काम न कर रहा हो, टैक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर सेक्रेटरी हो सकता है टैक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा डिलीवर ना कर पा रहा हो कैसे तय कर रहे हो शिक्षा तो हम देख रहे हैं हॉयर एजुकेशन तो हम देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा डायरेक्टरेट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा हम देख रहे हैं हमसे पूछ लेते। आप हर 2 महीने बाद किसी को उठा रहे हो सौरभ जी ने जो लिस्ट दी बहुत ही इन्ट्रस्टिंग है वो मैंने अभी बहुत कम ध्यान दिया है इस ओर लेकिन मैं पीड़ा रोज़ झेलता था इस चीज़ को, आज उन्होंने उसको अंडरलाइन किया मतलब टैक्निकल एजुकेशन मोदी जी बड़ी स्किल इंडिया-स्किल इंडिया की बात करते हैं ये भी स्किल इंडिया-स्किल इंडिया कह रहे हैं धन्यवाद देते हैं जी स्किल इंडिया कर रहे हो लेकिन ये बताओ न स्किल इंडिया आयेगा कहां से, हर 2 महीने के डायरेक्टर बदलने से स्किल इंडिया आयेगा क्या। स्किल का डायरेक्टर

आप हर 2 महीने बाद उछाल देते हो कुर्सियां, म्युज़िकल चेयर खिला रखी हैं आपने स्किल के डायरेक्टर्स को। किस बात का धन्यवाद करें स्किल को बर्बाद करने का या स्किल-स्किल का राम नाम जपने का। आपने स्किल-स्किल-स्किल चिल्लाकर इतना कर रखा है जी मैं स्किल की बात कर रहा हूँ ये है आपका स्किल। स्किल एजुकेशन को बर्बाद करना आपका स्किल है। हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो टैक्निकल एजुकेशन का ये बता रहे थे मतलब जो स्किल आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, डी.टी.यू., आई.जी.डी.टी.यू., ट्रिपल आई.टी. डी. इस जैसी... एन.एस.यू.टी. नई यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को देखने वाले अधिकारियों को 2018 से लेकर आज तक एक सेक्रेटरी 24 दिन बाद हटा दिया आपने, दूसरा आदमी 1 महीने 11 दिन में हटा दिया, तीसरा आदमी लाये उसको 5 महीने 28 दिन में हटा दिया, चौथा आदमी लाये उसको 8 महीने में हटा दिया, पांचवां आदमी लाये उसको 4 महीने में हटा दिया, छठा आदमी लाये 6 महीने में हटा दिया, सातवां आदमी लाये 6 महीने में हटा दिया, आठवां आदमी लाये 5 महीने में हटा दिया, नवीं एक लेडी हैं वो 9 महीने से काम कर रही हैं उनको भी हो सकता है किसी दिन हटा ही दो ये तो सेक्रेटरी की स्थिति है स्कील और टैक्निकल एजुकेशन के, शर्म आनी चाहिये इस पर तो आपको अब धन्यवाद करें इस बात पर की शर्म करें, बताओ ध न्यवाद होना चाहिये कि शर्मिन्दा होना चाहिये। इस बात पर धन्यवाद करना चाहिये या शर्मिन्दा होना चाहिये कि स्कील और टैक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर को ये तो मैंने सेक्रेटरीज़ की स्थिति बताई। डायरेक्टर की स्थिति ये है 2018 से एक अफसर को 2 महीने 8 दिन के लिये लगाया फिर नया डायरेक्टर लगा दिया 3 महीने 12 दिन के लिये फिर नया डायरेक्टर लगा दिया 3 महीने 26

दिन के लिए फिर एक नया डायरेक्टर लगाया 1 साल 6 महीने के लिए फिर नया डायरेक्टर लगाया 11 महीने के लिये फिर नई एक डायरेक्टर लगाई 10 महीने के लिये और आज की तारीख में ये शर्म की बात है आप जिस चीज़ पर गर्व कर सकते हैं कर लीजिये और आई एम श्योर शिक्षा को बर्बाद होने पर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इनका नेता गर्व महसूस करता है कि अच्छा हुआ शिक्षा बर्बाद हो गई करिये गर्व इस पर मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में देश की राजधानी में टैक्निकल और स्किल एजुकेशन के पास डायरेक्टर नहीं पोस्ट कर रखा इन्होंने पिछले 22 दिन से लिंक ऑफिसर से काम चल रहा है किस बात का धन्यवाद करें करो धन्यवाद।

...व्यवधान...

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः करो धन्यवाद या डूब मरो शर्म से। 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं टैक्निकल और स्किल एजुकेशन में किस बात का धन्यवाद करें कि 22 दिन से आपने टैक्निकल और स्किल का एजुकेशन डायरेक्टर नहीं दे रखा दिल्ली सरकार को इस बात का धन्यवाद करें आपका इस बात का धन्यवाद करें कि 6 लाख बच्चों की जिन्दगी से खेल रहे हो। डायरेक्टर होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये। धन्यवाद चाहते हो, हम भी कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं आपके जो पिछले लाये थे वो भी आपके ही लाये थे हम तो उनको भी अच्छा ही कहते थे लेकिन ये करके गये हैं और ये करवा रहे हो फिर कहते हो धन्यवाद करो तो बर्बाद करने के लिये धन्यवाद करें हम नहीं करेंगे, आदमी अच्छे हैं पर बर्बाद कर रहे होंगे आपके ये वाले कर रहे हों या पहले वाले कर रहे हों आप लेकर आये थे आप जानो लेकिन सदन में क्योंकि धन्यवाद

की बात उठी। शर्म आती है और मैं तो, मैं उप-राज्यपाल महोदय पर जा ही नहीं रहा। गलती उप-राज्यपाल महोदय की बिल्कुल नहीं है न इनकी है ना पिछले वाले की है। ये तो केन्द्र सरकार में बैठे हुये लोगों की मंशा का सवाल है। अच्छे आदमी हैं वो भी अच्छे आदमी थे और ये भी अच्छे आदमी हैं। मैं जब-जब मिला हूँ उनसे अच्छा लगता है मैं उन पर जा ही नहीं रहा बिल्कुल पता नहीं क्यों लेकर गये। मैंने नहीं सुना 6-7 सदस्य बोले किसी सदस्य ने ये बोला हो कि उप-राज्यपाल साहब अच्छे आदमी नहीं है किसी ने बोला क्या किसी ने नहीं बोला इतने सारे लोग बोले तो सब बोले पता नहीं क्यों बोले अच्छे हैं अच्छे हैं अरे हम भी कह रहे हैं अच्छे हैं अब ये बताओ केन्द्र सरकार हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद ये स्किल एजुकेशन के टैक्निकल एजुकेशन के हॉयर एजुकेशन के डायरेक्टर्स को म्युज़िकल चेयर क्यों खिला रही है या तो आपको समझ नहीं है कि एजुकेशन का क्या इम्पोंटेन्स है या तो आपको समझ नहीं है कि एजुकेशन में कोई अधिकारी आये, अरे हम से भी पूछ लो। यार एक आदमी को किसी ने हो सकता है आपकी बात न सुनी हो हटा दिया हो मानते हैं कि जी आपकी कोई सर्विस आपके पास है ट्रांसफर-पोस्टिंग अभी आपके पास दे रखी है। मानते हैं कि किसी अधिकारी ने न सुनी हो आपको गुस्सा आया हो सुबह तक आपने हटा दिया उसको लेकिन हर 3 महीने बाद अधिकारी बदल रहे हो यार। हर 3 महीने बाद किसी को पत्ते की तरह फेंट-फेंट कर उठा देते हो, क्या कर रहे हो स्कील एजुकेशन, हॉयर एजुकेशन किसी भी देश को रोजगार उसकी नौजवानों को संभालने की एजुकेशन होती है। जहां स्कूल एजुकेशन उस देश के बच्चों को संभालती है नौजवानों को संभालने का काम स्कूल एजुकेशन, हॉयर एजुकेशन, टैक्निकल

एजुकेशन में किया जाता है। आप इस देश के नौजवानों के साथ खेल रहे हो, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो और यहां पर आकर भावपूर्ण कहते हो अच्छे हैं होंगे अच्छे खूब हाथ मिलाकर करिये अच्छे हैं हमने कब मना किया आप एक हाथ हिलाकर हम दो हाथ से कह देते हैं अच्छे हैं लेकिन बताओ ये काम क्यों कर रहे हैं ये केन्द्र सरकार और मैं उप-राज्यपाल साहब से तो सवाल ही नहीं है मेरा, मैं तो केन्द्र सरकार से पूछ रहा हूँ ये कर क्या रही है। 2 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया फिर 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया फिर 1 साल में एक डायरेक्टर बदल दिया फिर 11 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया फिर 10 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया 22 दिन से दिल्ली के पास में ना हॉयर एजुकेशन का डायरेक्टर है न टैक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजिज़ में एडमिशन का टाइम चल रहा है वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है लोग पूछते हैं भई एडमिशन कैसे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा है। आई.टी.आईज़ में एडमिशन हो रहे हैं स्किल सेन्टर्स में एडमिशन होने हैं डायरेक्टर ही नहीं है ये तो इनकी व्यवस्था है सर्विसज़ इसलिये सर्विस जानबुझकर लिया कि जब-जब केजरीवाल सरकार काम करने की कोशिश करे सर्विसिज़ का दुरूपयोग करके काम को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इतिहास गवाह है कि कैसे सर्विसिज़ को, और मैं इसीलिये इसी बात को दोहरा कर अपनी बात खत्म करूंगा कि सर्विसिज़ को असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार से छीनने का सबसे ज्यादा नुकसान हॉयर एजुकेशन और टैक्निकल एजुकेशन को पहुंचा है इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहां कि यूनिवर्सिटीज़ यहां के कॉलेजिज़ यहां के पॉलिटेक्निक और आई.टी.आई. संस्थानों को पहुंचा है और

इसका मतलब है कि दिल्ली के 6 लाख नौजवानों को इसका नुकसान पहुंचाया है उसने इन लोगों ने, इसका घड़ा इनका भरेगा और इसका पाप इनको भुगतना पड़ेगा इसका फल इनको भुगतना पड़ेगा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। आज की कार्यसूची में सातवें नम्बर पर सैकेन्ड पार्ट को समय ज्यादा हो गया कल लेंगे जो राजेश गुप्ता जी का प्रस्ताव है जिसमें बोलने के लिये राजकुमारी ढिल्लों जी का नाम है, बंदना जी का है, ऋतुराज जी का है, पवन शर्मा जी का है, सोमनाथ जी का है, मदनलाल जी का है। ये सत्ता पक्ष की ओर से थे विपक्ष की ओर से अभी नाम नहीं आये थे जो भी नाम आयेंगे इस विषय को कल लेंगे। माननीय सदस्यों का अब धन्यवाद करते हुये विपक्ष का भी धन्यवाद करते हुये कि कार्यवाही शांतिपूर्वक चली सबका धन्यवाद करता हूँ। अब सदन की कार्यवाही 5 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 5 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

...समाप्त...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।